हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

26 मार्च, 2008

खण्ड 1, अंक 13

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 26 मार्च, 2008

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(13) 1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(13) 25
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(13) 27
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना	(13) 40
सदन की कार्यवाही देखने के लिए एक समिति के गठन के मामले के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय का निर्णय	(13) 41
वाक-आउट	(13) 42
घोषणा—	(13) 43
अनुपस्थिति की अनुमति	(13) 44
वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(13) 45
अति विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत	(13) 73
वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(13) 73
बैठक का समय बढ़ाना	(13) 85
वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(13) 85
बैठक का समय बढ़ाना	(13) 90
वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(13) 90

मूल्य : 72

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 26 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 09:30 बजे हुई। अध्यक्ष (डा० रघुबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the question Hour.

Forcing the Farmers to open Accounts in Nationalized Banks.

***925 Shri S.S. Surjewala :** Will the Cooperation Minister be pleased to state:—

(a) whether the Government is aware of the fact that the officials of the Cooperative Banks are forcing loan seeking farmers to open accounts in the Nationallized Banks; if so, whether the action on the part of the offcials of the Cooperative Banks is illegal and undesirable; and

(b) if so, the action taken by the Government in this regard ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chattha) : No, Sir, it is not true that the officials of the Cooperative Banks are forcing loan seeking farmers to open accounts in the Nationalized Banks.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो भी मैम्बर्ज हैं वे मेरी बात की ताईद करेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति या किसान को-आपरेटिव बैंक से कर्जा लेने जाता है तो बैंक से उसे यह कहा जाता है कि किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवा कर चैकबुक और पासबुक यहां पर लेकर आओ। जब किसान किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाकर चैक बुक लेकर आता है तो उससे खाली चैकों पर दस्तखत करवाकर बैंक द्वारा ले लिये जाते हैं ताकि यदि कोई व्यक्ति अथवा किसान किसी कारणवश अपना कर्जा वापिस न कर पाए तो उसके दूसरे बैंक के खाते से पैसे रिकवर कर लिये जाएं। स्पीकर सर, यह प्रैक्टिस सारे को-आपरेटिव बैंकस में चल रही है। हमें कई ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने इस बारे में हमसे शिकायत की है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री महोदय को ऐसी कोई शिकायत मिली है और यदि मिली है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सरदार एच०एस० चट्ठा : स्पीकर सर, इससे पहले कुछ आदमी इस बारे में गवर्नमैंट को मिले थे। यह बात दुरूस्त है कि जो लोंग टर्म लोन दिये जाते हैं उनमें कुछ चैकस पर बैंक के लोग दस्तखत करवाते हैं लेकिन को-आपरेटिव बैंक के लोग चैक दस्तखत नहीं करवाते हैं और प्राईवेट बैंक्स में भी ऐसा नहीं है। स्पीकर सर, इस प्रकार की जो दिक्कत आती है वह लोंग टर्म लोन्ज़ के मामले में आती है लेकिन छोटे लोन्ज़ में ऐसी दिक्कत नहीं है। 5-10 साल के जो लोंग टर्म लोन्ज़ होते हैं उनके लिए वे 4-5 चैकस पर दस्तखत करवाते हैं। मैंने इस बारे में पता किया है यह बात को-आपरेटिव बैंक्स में नहीं है कि किसी दूसरे बैंक में खाता हो तभी किसान को लोन दिया जाएगा। यदि इस प्रकार की कोई स्पैसिफिक शिकायत हो तो आप हमें बता दें we will deal it very firmly.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि मेरे जिला कैथल में को-आपरेटिव बैंक है क्या वहां पर किसी अधिकारी को भेज कर इस बारे में इन्क्वायरी करवाएंगे? लौंग टर्म लोन्ज़ पर चैकों पर दस्तखत करवाए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कौन सी प्रैक्टिस है। इस प्रकार से खाली चैकों पर दस्तखत करवाना कानून के खिलाफ है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे इस बारे में कोई ऐक्शन लेंगे और जो इस प्रकार की प्रैक्टिस चल रही है क्या उसको बन्द करवाऐंगे?

सरदार एच० एस० चड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत हाउस को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कैथल को-आपरेटिव बैंक की हम इन्क्वायरी करवा देंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंकि कि लौंग टर्म लोन्ज़ के लिए दस्तखत करवाते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म लोन्ज़ में ऐसा नहीं करते। माननीय सदस्य श्री सुरजेवाला जी को यदि इस बात पर कोई ऐतराज है तो We will consider that इस पर भी दस्तखत न करवाए जाएं। लौंग टर्म लोन्ज में 20 किश्तें होती हैं 20 किश्तों पर only one post dated check पर अगर कोई दस्तखत करवाता है तो This practive is prevalent in Bhiwanit District where recovery is very late, ऐसा है स्पीकर सर, अगर माननीय श्री सुरजेवाला जी यह फील करते हैं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए तो इस बारे में विचार कर लेंगे।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं क्या महसूस करता हूं यह अलग बात है। इस प्रकार से चैकों पर दस्तख्त करवाना बिलकुल गलत बात है और कानून के खिलाफ है।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि नांगल चौधरी को-आपरेटिव बैंक में लोन लेने के लिए पीछे छः-छः महीने के केसिज पैंडिंग पड़े हैं जो भी लोग वहां पर लगे हुए हैं वे केसों का निपटारा नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री सुरजेवाला जी ने जो कहा वह सही है। मै माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे नांगल चौधरी में रेड करवा सकते हैं और यह पता करवा सकते हैं कि वहां पर पिछले 6-6 महीने की फाईलें क्यों पड़ी हुई हैं, वे फाईलें किस लिए अण्डर कंसिडरेशन हैं और क्या जो लोग इस के लिए जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स करवाएंगे ?

सरदार एच० एस० चड्ढा : अध्यक्ष महोदय, हम इक्कवायरी करवाएंगे।

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे को-आपरेटिव बैंक की ब्रान्च की बैलेंस शीट हर साल नहीं मिलाई जाती है और कितने ही सालों से वह पैंडिंग चली आ रही है। खेड़ी जलान में एक ब्रान्च है जहां छः साल से बैलेंसशीट नहीं मिलाई गई है। अगर इसकी जांच करवाई जाए वहां पर इम्बैजलमैंट पाए जाने की सम्भावना है। इसी के साथ जो नए एम०सी०ए० बनाए गए हैं वे चार महीने पहले ही बनाए गए हैं। लेकिन किसानों को वह पैसा अभी तक नहीं मिला है। हमने जब इस बारे में एम०डी० से बात की तो उन्होंने कहा कि ब्रांच की लिमिट तो बढ़ा दी है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। क्या मन्त्री जी इसमें पैसे का प्रबन्ध करेंगे ?

सरदार एच०एस० चड्ढा : अध्यक्ष महोदय, को-आपरेटिव बैंक लोगों के भले के लिए है इनका जो प्रश्न है वह तारांकित प्रश्न से रिलेटिड नहीं है लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय

सदस्य को बताना चाहूंगा कि लोगों के भले की जो भी बात होगी, वह को-आपरेटिव बैंकों से ही होगी।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो हाल में रूरल एरिया में को-आपरेटिव सोसाईटीज की रिस्ट्रकचरिंग हुई है मेरा अनुभव यह है कि इसके कारण बहुत काम खराब हो गया है और किसानों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। क्या सरकार ने रिस्ट्रकचरिंग के बाद कोई स्टडी करी है कि इससे जो आप किसानों का फायदा करने के लिए चले थे कहीं उनका बुरा तो नहीं हो गया है।

सरदार एच०एस० चड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस बारे में ऊपर और नीचे दोनों के लैवल पर मीटिंग्ज़ हुई हैं। दिल्ली में भी और यहां पर भी मीटिंग्ज़ हुई हैं। यह सिस्टम सारे भारत में बन रहा है, यह सिस्टम हमने अकेलों ने नहीं बनाया है बल्कि दूसरी जगहों पर भी बन रहा है। जहां से पैसा आता है, उनकी कुछ शर्तें हैं, उनको हमें पूरा करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से सोसाईटीज़ की बजाए छोटे बैंक बनने से पब्लिक का कोई नुकसान नहीं है।

Consrtruction of Bhiwani Ghaggar Drain

***946. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Irrigagion Minister be pleased to state the time by which the construction work of Bhiwani Ghaggar drain is likely to be completed ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, the scheme is in progress and is likely to be completed by 30.6.2009.

डा० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों सैशन के दौरान मैंने ड्रेन की इन्सपैकशन की थी और मैंने पाया कि वहां पर ड्रेन का 20 प्रतिशत काम भी नहीं हुआ है। बरसात जब भी आती है तो इस ड्रेन के न बनने के कारण भिवानी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। क्या मन्त्री जी इस ड्रेन को जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट करेंगे? क्या इसके अलावा जो इस ड्रेन का डिस्पोजल देवसर चुंगी पर है, उससे लेकर ड्रेन के शुरू होने तक मन्त्री जी एक चैनल बनवाएंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह जो भिवानी घग्गर ड्रेन है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यदि विशेष तौर पर भिवानी में देखें तो वहां पर सीवरेज का पानी इक्ट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही बुरा हाल है। अध्यक्ष महोदय, इनकी जो म्यूनिसिपल कमेटी की लैंड है वह सारा सलशी एरिया है। अध्यक्ष महोदय, भिवानी में फलैस फल्ड आता है उसको देखते हुए भिवानी घग्गर ड्रेन की एप्रूवल ली गई थी। अध्यक्ष महोदय, अन्डर दि चेयरमैनशिप ऑफ मुख्यमन्त्री, 38वीं हरियाणा स्टेट फल्ड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी और यह मेवाड़ आर०डी०एफ० 13 के तहत एप्रूव हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का जितना भी सिवरेज और फल्ड का पानी है वह गांव बापौड़ा, सूई, दांग, कलान, दांगखुर्द, सांगवान, तोशाम और दहिमा लाडवा से जाकर हिसार ड्रेन में मिलेगा। यह चैनल लार्ज पंपज के लिए है। इसकी वजह से वहां पर किसान इरिगेशन के लिए पानी लिफ्ट कर सकेंगे और यह चैनल रि-चार्जिंग का भी काम करेगा जहां तक इन्होंने चिन्ता जाहिर की है कि काम शुरू नहीं हुआ है तो इसमें लैंड इक्वीजीशन

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
प्रोसीडिंग अन्डर सैक्शन 4 और 6 with सैक्शन 17 (c) already have been completed. अध्यक्ष महोदय, उस लैंड का जो टोटल कम्पनसिएशन है वह 17 करोड़ 52 लाख है। अध्यक्ष महोदय, 157 एकड़ लैंड एल०ए०ओ० और डी०आर०ओ० के पास डिपोजिट कर दी है। अध्यक्ष महोदय, इक्वीजीशन की लैंड गांव जोन्पल, देवसर, बापौड़ा, सूई, बलीयाली, अलखपुरा, मुरटाना, किरावर और डिस्ट्रिक्ट भिवानी की है, इसके साथ मुजादपूर, कंवारी, धमाना, मुंजार, दहिमा और डिस्ट्रिक्ट हिसार की 138 एकड़ लैंड है, उसका अवार्ड अनाऊंस भी कर दिया गया है इसके लिए 15 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि रखी गई है। यह जो टोटल स्कीम है इसका जो रिवाईज एस्टीमेट है वह तकरीबन 27 करोड़ रुपये तक पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, बाकी के जो गांव हैं उनमें हालुवास, सांगवान, रतेरा इन डिस्ट्रिक्स भिवानी, गांव सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्स हिसार में है, इसमें करीबन 19 एकड़ जमीन है जिस पर एक्वीजीशन के लिए प्रोसैस चल रहा है और इसके लिए 2 करोड़ 17 लाख रखे गए हैं।

इसका तकरीबन पांच परसैंट काम हुआ है। इसकी सारी फोर्मेलिटीज जैसे टैंडर की या ऐस्टीमेटस की तैयार हो गयी हैं। मैं समझता हूं कि जल्दी ही इसका काम पूरा करवाने की हम कोशिश करेंगे। स्पीकर साहब, इसका वर्क तकरीबन 30 जून, 2008, तक खत्म होगा।

डा० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर सिवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगवाया जाएगा, क्या वहां पर पानी ट्रीट करके डाला जाएगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, सिवरेज ट्रीटमैंट प्लांट से पानी ट्रीट करने के बाद ही इसमें पानी डाला जाएगा। जो पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट है वह वहां के लिए अपनी एक स्कीम बना रहा है। वहां पर पानी ट्रीट करके ही डाला जाएगा ताकि केमीकलयुक्त पानी किसानों को न मिले।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मिथाथल घूसकानी ड्रेन जो आगे जाकर भिवानी घग्गर ड्रेन में मिल जाती है, उसकी अब क्या पोजीशन है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं पहले भी बता चुका हूं। आज मेरे पास इस बारे में डिटेल नहीं है लेकिन इनको बताना चाहूंगा कि इस ड्रेन का भी प्रौसस चल रहा है। ये मुझे इस बारे में सैपरेट नोटिस दे दें ताकि मैं इनको इस ड्रेन के बारे में डिटेल दे सकूं।

Trauma Centre on G.T. Road near Kurukshetra

***972. Sh. Ramesh Gupta :** Will the Health Minister be pleased to state:—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a Trauma Centre on G.T. road near Kurukshetra.

(b) if so, the time by which the said Trauma Centre is likely to be constructed?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहिन करतार देवी) : (क) नहीं, श्रीमानजी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्पीकर सर, साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इस समय तो कोई ऐसी स्कीम सरकार के विचाराधीन नहीं है लेकिन मैं भी अपने आपको इनकी चिंता के साथ जोड़ते हुए कहना चाहती हूं क्योंकि कुरूक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जो गीता के उपदेश के नाम से भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। वर्ष 2006 में ही नहीं बल्कि वर्ष 2007 में भी कुरूक्षेत्र, बहादुरगढ़ और दो तीन जगहों के लिए हमने ट्रॉमा सैंटर खोलने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे थे लेकिन भारत सरकार से अभी तक इनकी मंजूरी नहीं मिली है इसलिए मैं अभी यह नहीं कह सकती कि कब तक कुरूक्षेत्र में ट्रामा सैंटर खोल दिया जाएगा और कब तक यह कार्य पूरा करेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि अब हमने दोबारा से यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है।

श्री रमेश गुप्ता : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया है मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं लेकिन साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र, जी०टी० रोड पर एक ऐसा प्लेस है जहां पर रोज ऐक्सीडैंटस होते रहते हैं। चूंकि लोक नायक जय प्रकाश नारायण होस्पीटल, जी०टी. रोड से चार पांच किलोमीटर पीछे हैं इसलिए ऐक्सीडैंटस के बाद लोगों को वहां या किसी दूसरी जगह पर ले जाने में समय लग जाता है जिस कारण उनको समय पर फर्स्ट ऐड नहीं मिल पाती है इसलिए अगर जी०टी० रोड पर ही एक ट्रौमा सैंटर बन जाए तो इससे कई जानें बचायी जा सकेंगी। स्पीकर सर, वहां पर इसके लिए पंचायत जमीन देने के लिए भी तैयार है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द यह मामला टेकअप करके वहां पर एक ट्रोमा सैंटर बनाया जाए।

बहिन करतार देवी : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल उचित है। जैसा मैंने बताया कि हमने 2006 में भी कुरूक्षेत्र में एक ट्रोमा सैंटर खोलने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था और 2007 में भी इस तरह का प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा एक और प्रस्ताव दोबारा से उनके पास भेजा गया है। हम जल्द से जल्द भारत सरकार से इसकी स्वीकृति करवाकर जी०टी० रोड पर ही एक ट्रोमा सैंटर बनवाएंगे। वहां के होस्पीटल में तो यह ट्रोमा सैंटर नहीं बन सकता है लेकिन जो मेन रोड पर पी०एच०सी० है उसी में से हम इसको अटैच करेंगे।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की कैथल में भी कोई ट्रोमा सैंटर खोलने की योजना है क्योंकि कैथल भी एक और नेशनल हाई वे पर पड़ता है? वह बहुत लम्बा हाई वे है और काफी ऐक्सीडैंटस कैथल के आस पास के एरियाज में होते हैं।

बहिन करतार देवी : स्पीकर साहब, अभी तक तो करनाल, सिरसा, रिवाड़ी, यमुनानगर और अम्बाला में ही ट्रोमा सैंटर बनाने पर काम चालू है। मैंने पहले इनके एक सवाल के जवाब में भी बताया था कि इनके यहां पर जो मल्टी स्पेशलिटीज होस्पीटल बन रहा है उसमें ही ट्रोमा सैंटर भी बनाया जाएगा।

श्री राजेन्द्र सिंह जून : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बहादुरगढ़ में 100 बैड का अस्पताल बन रहा है उस के साथ ही मुख्यमन्त्री जी

[श्री राजेन्द्र सिंह जून]

ने वहां ट्रोमा सैंटर भी अनाउंस किया था। मैं कहना चाहता हूं कि ट्रोमा सैंटर के लिए पैसा शीघ्र मंगाया जाए ताकि काम शुरू हो सके?

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं कि डेढ़ करोड़ रुपया भारत सरकार ने ट्रोमा सैंटर्ज के लिए देना है। कुरूक्षेत्र, बहादुरगढ़ और पलवल का इस वक्त केस हमने भारत सरकार को भेजा है, जल्दी ही वहां से स्वीकृति मिल जाएगी तो हम यह काम पूरा करवाने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, बाकी सारे माननीय सदस्य तो नये ट्रोमा सैंटर खोलने की बात कह रहे हैं लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि करनाल में जो आलरेडी ट्रोमा सैंटर की बिल्डिंग बनी हुई है उसमें जो सुविधायें होनी चाहिएं वह कब तक उपलब्ध कराएंगे?

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि राज्य सरकार ने करनाल, सिरसा, यमुनानगर और रिवाड़ी के लिए न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजीशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, सामान्य सर्जन, एनैस्थेसिस्ट, यूरोलौजिस्ट और चार सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों की पोस्ट भरने की स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा माननीय सदस्या जो सी०टी० स्कैन मशीन की चर्चा करती रही हैं उसको भी खरीदने के आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बरवाला में सी०एच०सी० बनी हुई है और हमने जी०एच० बनवाने के लिए सरकार के पास डौक्यूमैंटस भेजे हैं। मैं मन्त्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि जी०एच० बनाने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन है यदि नहीं, तो क्या बनाने का कष्ट करेंगे?

Mr. Speaker : You should ask the separate Question in this regard.

श्री रमेश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां अस्पताल में डॉक्टर्ज की बहुत कमी है। फिजीशियन भी नहीं है, गाइनोकोलोजिस्ट भी नहीं है। ट्रोमा सैंटर तो जब मिलेगा, तब मिलेगा लेकिन वर्तमान में जो डॉक्टर्ज की कमी है उसको तक कब पूरा किया जाएगा ?

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, ये ठीक है कि 232 डॉक्टर्ज की इस वक्त स्टेट में कमी है। इस बारे में हमने रिक्वीजीशन भेज दी है और एस०एस०सी० जल्दी ही इन्टरव्यू लेना शुरू करेगी, जैसे जैसे सलैक्शन हो जाएगा, जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट लैवल पर तो प्राथमिकता के आधार पर जरूर पोस्टिंग कर देंगे।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि देहात में जो पी०एच०सीज़० है उनमें डॉक्टर्ज की बहुत कमी है। क्या कहीं यह कंसीड्रेशन में है कि स्पेसिफिक पी०एच०सीज० में चाहे कंट्रैक्ट बेसिज पर ही सही लेकिन डॉक्टर लगाये जाएं। यह भी हो कि वहां लगने के बाद वे उसी के अंदर रहे, शहरों की तरफ न दौड़ें।

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, माननीय सदस्य का कहना वाजिब है। अभी डाक्टर्ज की मानसिकता इतनी बदली नहीं है कि वे देहात में रहकर खुश हों। हमने इस समस्या के हल

के लिए इसके लिए प्रपोजल चलाई तो है लेकिन वह अभी सिरे चढ़ी नहीं है। हां, यह जरूर है कि रूरल एरिया में कुछ विशेष प्रोत्साहन डॉक्टर्ज को देने के लिए सरकार विचार कर रही है।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भिवानी में ट्रोमा सैंटर खोलने का कोई प्रावधान है?

श्री अध्यक्ष : क्या पहले इस बारे में कोई चर्चा चली हुई है।

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, अभी तो कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ज्यादातर राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही ट्रोमा सैंटर खोले जाएंगे। विपक्ष के इन साथियों ने तो रोहतक का ट्रोमा सैंटर बदल कर करनाल भेजा था। हमने रोहतक में दोबारा से ट्रोमा सैंटर शुरू किया है।

डा० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, जब तक सरकार स्पैशलिस्ट और सुपर स्पैशलिस्ट को अच्छा इन्सैंटिव नहीं देगी तब तक वे हमारे यहां आयेंगे ही नहीं। हमारे पूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गान्धी जी ने जब डा० नरेश त्रेहेन को बुलाया था तब उन्हें इन्कम टैक्स से एग्जैम्पट किया था और काफी अच्छे इन्सैंटिव दिये थें उसका फायदा यह हुआ कि हिन्दुस्तान में कार्डियक सर्जरी होनी शुरू हुई जिसके परिणामस्वरूप गल्फ कंट्रीज, इंग्लैंड, अमेरिका से लोग यहां आकर कार्डियक सर्जरी करवाने लगे। इसी प्रकार से जब तक हम इन स्पैशलिस्टस को अच्छा इंसैंटिव नहीं देंगे तब तक वे यहां नहीं आयेंगे। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इनको ज्यादा इन्सैंटिव देने के बारे में कोई विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष : फिर इन नर्सिंग होम्ज का क्या होगा?

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, जब तक कोई स्कीम लागू करने के लिए फाईनल नहीं हो जाए तब तक मैं हाउस में कोई आश्वासन नहीं दे सकती।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने आश्वासन दिया है कि जिला हैड क्वार्टरज पर डाक्टर्ज को जरूर भेजेंगे। फिर तहसील हैड क्वार्टरज का क्या होगा क्योंकि मेरे हलके की तहसील बहल, लोहारू और सिवानी, भिवानी से 60-60 किलोमीटर की दूरी पर हैं वहां आज तक कोई डाक्टर नहीं एप्वायंट किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर तो फिर भी नर्सिंग होम्ज होते हैं। मैं मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या तहसील हैड क्वार्टर पर भी डाक्टर भेजने के बारे में सरकार कोई विचार कर रही है ?

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री भाई भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने यह निश्चय कर लिया है कि हर जिला लेवल पर एक 100 बैडस का होस्पिटल होगा और उसमें सरकार एक स्पैशलिस्ट को भेजेगी ताकि उस जिले से बाहर मरीज को न जाना पड़े। मैंने आश्वासन तो यह दिया है कि जिला लेवल के होस्पिटल को प्रोयोरिटी दी जायेगी। फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि रूरल एरिया में काम करने वाले डाक्टर्ज के लिए सरकार एक विशेष स्कीम बना रही है जब यह स्कीम फाईनल हो जायेगी तभी मैं हाउस में आश्वासन दे सकती हूं।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, नारनौल, नांगल चौधरी और निजामपुर एरिया में क्रैशर जौन हैं और राजस्थान के क्रैशर जौन भी उसी एरिया में हैं इसलिए वहां पर गाड़ियां दिन-रात चलती हैं और बहुत एक्सीडैंटस होते हैं। लेकिन वहां पर होस्पिटल के नाम पर कोई सुविधा नहीं

[श्री नरेश यादव]

है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या उस एरिया में कोई ट्रामा सैंटर खोलने पर सरकार विचार कर रही है ?

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, रेवाड़ी में तो ट्रामा सैंटर सरकार ने पहले से ही खोल दिया है। हर सदस्य इस बारे में चिन्ता कर रहा है और चिन्ता करनी भी चाहिए। मैं इस बात से सहमत भी हूं। पहले बहादुरगढ़, कुरूक्षेत्र, बल्लभगढ़, पलवल, गुड़गांव के ट्रॉमा सैंटर मन्जूर हो जायें उसके बाद ही दूसरी जगह ट्रामा सैंटर खोलने पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, जहां स्पीड से गाड़ियां चलती हैं और वहां पर एक्सीडैंट भी ज्यादा होते हैं उन मरीजों को उस समय पर फर्स्ट ऐड की सुविधा मिले इसलिए जी०टी० रोड पर ट्रॉमा सैंटर खोले जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा प्रोपोजल बना रही है जिससे पी०डब्ल्यू०डी० (बी०एण्डआर०), ट्रान्सपोर्ट और हैल्थ विभाग सारे विभाग मिलकर एक साथ काम करें जिससे एक्सीडैंट कम हों और आम नागरिक को सुविधा ज्यादा मिल सके।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, इसमें रूल्ज रेगुलेशंज की बात है सारे विभाग एक साथ कैसे इकट्ठे काम करें ?

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, जिससे एक्सीडैंट कम हों और आम नागरिक को सुविधा ज्यादा मिल सके क्या ऐसा कोई प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में तो आप पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर साहब से पूछना।

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब का सवाल वाजिब है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले ट्रैफिक का विंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के पास था। मुख्यमंत्री महोदय जी ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के बाद हमें यह लगा कि शायद पुलिस बैटर इक्विपड है इसलिए जी०टी० रोड पर पुलिस विभाग द्वारा स्पैशल पुलिस स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं, जिनकी mobiles and ambulance से कनैक्टिविटी है और जिनके पास लोकल ट्रोमा सैंटर्स के नम्बर्स हैं और जिन के पास क्रेनस भी हैं। इन स्टेशनों में क्रेनस भी हैं इसलिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट की जरूरत नहीं है। पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) ने उनको स्पेस भी एलौकेट कर दिया है। आप जब अगली बार जी०टी० रोड पर जाएंगे तो आपको बायें और दायें ये सैंटर नजर भी आएंगे। इन सैंटरों का बाकायदा हैल्थ डिपार्टमैंट से कोर्डीनेशन है। हमने जी०टी० रोड पर व्यवस्था करके आलरेडी ये सैंटर बना दिए हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि बाकी जगहों पर भी ये सैंटर बनाने की हमारी योजना है।

तारांकित प्रश्न संख्या 983

(इस समय माननीय सदस्य श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Canal Based Water Supply Scheme

***974. Shri Nirmal Singh :** Will the Water Supply and Sanitation Minister be pleased to state the time by which the Canal Based Water Supply Scheme is likely to be materialized in Ambala Cantt.?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, Canal Based Water Supply Scheme for Ambala Cantt. being constructed at a cost of Rs. 30.81 Crores is likely to be commissioned by 31.12.2008.

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से जानना चाहूंगा कि क्या इस स्कीम में सारा अम्बाला कैंट कवर होगा या उसका कुछ पार्ट ही कवर होगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि यह काफी बड़ी स्कीम है। मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि यह स्कीम 1999 में कंसीव की गई थी और उसके बाद ही इसी तरह अधर में लटकी रही। मई, 2006 के अंदर दोबारा इस सरकार के गठन के बाद 30.81 करोड़ रुपये स्टेट प्लान से इसके लिए दिए गए। इसकी एक्स्ट्रीमली वाइज कवरेज है। अम्बाला कैंट में इस स्कीम के बनने के बाद हमें लगता है कि पानी की कोई प्रोब्लम नहीं होगी। 90 परसैंट से अधिक एरिया इस स्कीम से कवर हो जाएगा।

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम की भूमिका 1999 में नहीं बल्कि 1993 में बनी थी। क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो 10 परसैंट रिमैनिंग एरिया है, उसको भी इस स्कीम में लेने का सरकार का ख्याल है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हम दिसम्बर 2008 तक इस स्कीम को पूरा कर देंगे और हमें यह उम्मीद है कि अम्बाला में जो एग्जस्टिंग वाटर सिस्टम है और जो यह स्कीम है इन दोनों को मिलाकर 100 परसैंट एरिया कवर हो जाएगा।

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कौन सा 90 परसैंट एरिया इसमें कवर होगा और कौन सा 10 परसैंट एरिया रह जाएगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो अम्बाला में एग्जस्टिंग वाटर है और जो यह स्कीम है इन दोनों को मिलाकर हम उम्मीद करते हैं कि 100 परसैंट एरिया कवर हो जाएगा।

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कैनाल बेस्ड वाटर के बारे में पूछना चाहता हूं कि किस एरिया में केनाल बेस्ड वाटर जाएगा क्योंकि वैसे तो पूरे अम्बाला में पानी की सप्लाई है।

Sh. Randeep Singh Surjewala : Sir, that is why I have said that this is a canal based scheme and you will appreciat it Sir, and the Hon'ble member will also appreciate कि किसी शहर के लिए 30 करोड़ 81 लाख रुपये की स्कीम दी गई है और वह भी स्टेट प्लान बजट से दी गई है। वैसे जो नाबार्ड और एन०सी०आर० के एरियाज हैं वहां तो लोनिंग की व्यवस्था है। परन्तु सरकार ने जब टेक ओवर किया था उस समय स्टेट का बजट केवल 100 करोड़ का था। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 3 साल के बाद 652 करोड़ रुपये का बजट हो गया है। हमने कोंशियस डिसीजन लिया और लगभग 31 करोड़ रुपये की राशि एक शहर को दे रहे हैं। मैंने माननीय साथी को समय सीमा भी दे दी है कि दिसम्बर 2008 तक हम इस स्कीम को पूरा कर देंगे। 1993 में जो काम पूरा नहीं हुआ, 1999 में कंसीव होकर भी पूरा नहीं हुआ, वह काम हमने दो साल के अंदर पूरा कर दिया है।

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस स्कीम से सारे शहर में कैनाल बेस्ड पानी सप्लाई किया जाएगा या नहीं? जहां तक आप कह रहे हैं कि यह स्कीम स्पैशल अम्बाला कैंट के लिए है तो मैं कहना चाहूंगा कि जहां पानी का संकट है और जहां पानी टैंकरों से लाया जाता है क्या वहां पर भी इस स्कीम के तहत पानी जाएगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : यह जो कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम है जैसा कि मैंने बताया है कि सारा एरिया इसमें कवर हो जाएगा। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि किस बस्ती में टयूबवैल का पानी जाएगा और किस बस्ती में कैनाल का पानी जाएगा। We are augmenting this scheme for entire city. Sir perhaps I was not able to explain

10.00 बजे कि जब यह स्कीम पूरी हो जायेगी अम्बाला शहर में 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से मिलेगा। लेकिन कौन सी बस्ती और मकान में टयूबवैल का पानी दिया जायेगा और कौन सी बस्ती और मकान में कैनाल का पानी दिया जायेगा यह बताना तो मुश्किल काम है।

श्री बचन सिंह आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सफीदों शहर के बीच से पब्लिक हैल्थ विभाग का गंदा नाला गुजरता है जिसकी वजह से शहर के लोगों को बहुत समस्या हो रही है। डेढ़ वर्ष पहले मन्त्री जी वहां आये थे और उनको यह भी गंदा नाला दिखाया गया था। मन्त्री जी ने उसके लिए 2.27 करोड़ रुपये एक साल पहले मंजूर किए थे लेकिन अभी तक वह पैसा रिलीज नहीं हुआ है। इस गंदे नाले की वजह से सफीदों शहर के लोगों को बहुत समस्या हो रही है क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उसके लिए पैसा कब तक रिलीज किया जायेगा ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह पृथक प्रश्न है परन्तु सफीदों शहर की समस्या जैन्यूवन है। मैं मेरे माननीय साथी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में मुझे लिखकर भिजवा दें। इसी वर्ष जो राशि जायेगी उसमें इसके लिए कुछ राशि का प्रावधान करवाकर कम्पोनैंट्स में काम शुरू करवा दिया जायेगा और कोशिश करेंगे कि जल्दी ही पूरा काम कर दिया जाये।

श्री अमीर चंद मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सवाल पूछने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कैनाल वाटर सप्लाई से संबंधित प्रश्न पर चर्चा हो रही है। कैनाल्ज में इतना पानी नहीं आता कि हमारे वाटर वर्क्स को पानी मिल सके और जो टयूबवैल लगा रखे हैं उनका पानी खारा है। क्या मन्त्री जी हमारे लिए कोई ऐसी स्कीम बनायेंगे कि वहां के वाटर वर्क्स को कैनाल से पानी मिल सके ताकि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह पृथक प्रश्न है और माननीय सदस्य मक्कड़ जी ने जो सवाल उठाया है मैं समझता हूं वह हांसी विधान सभा क्षेत्र के बारे में है। शायद वे यह पूछना चाहते हैं कि क्या हांसी में भी कैनाल बेस्ड वाटर वर्क्स बनाया जायेगा? अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी सदन में माननीय सदस्य के स्पेसिफिक प्रश्न के जवाब में बताया था उसकी पूरी इन्फर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि यह पृथक प्रश्न है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हांसी में दूसरा वाटर वर्क्स बनाने के लिए शायद जमीन अधिग्रहण हो चुकी है। उसके पूरे कन्टूयर्ज क्या हैं इस बारे माननीय सदस्य लिखकर पूछ लें माननीय सदस्य को लिखित में जानकारी दे दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, यदि कैनाल बेस्ड वाटर वर्क्स नहीं बनाया जायेगा

और नीचे का पानी खारा होगा तो वहां पर पीने का पानी देने का कोई तीसरा साधन नहीं है। क्योंकि पानी या तो जमीन के नीचे से आयेगा या कैनाल बेस्ड से आयेगा इसलिए झांसी में सरकार ने कैनाल बेस्ड वाटर वर्क्स बनाने का निर्णय लिया हुआ है।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे मेवात जिले में जिला हैडक्वाटर पर भी पीने के पानी की बहुत किल्लत है और वहां रहने वाले लोग पीने के पानी के लिए बहुत परेशान हैं। मेरे साथी हबीब-उर-रहमान जी आज यहां नहीं बैठे वे तो अपने एरिया में पब्लिक हैल्थ के टैंकरों से पानी भरवा लेते हैं। वहां पर लोगों ने बड़े-बड़े पानी के टैंकर बनवा रखे हैं जो ट्रैक्टर के साथ जोड़कर पानी की सप्लाई करते हैं। एक टैंकर पानी के लिए 500-500 रुपये लेते हैं। जो अमीर लोग हैं वे तो अपने घर पानी का टैंकर मंगवा लेते हैं लेकिन वहां पर गरीब आदमी भी रहते हैं। जो गरीब आदमी हैं वे चार-पांच इकट्ठे होकर पानी का टैंकर मंगवाते हैं। इसके अतिरिक्त हैड क्वार्टर मेवात होने के बावजूद भी पब्लिक हैल्थ का एस०ई० पलवल बैठता है। यदि एस०ई० मेवात जिले में बैठे तो वहां की काफी समस्याएं हल हो सकती हैं। इसलिए मन्त्री जी बतायें कि क्या एस०ई० को मेवात जिले में बिठायेंगे और वहां पर जो पीने के पानी की समस्या है उसको किस प्रकार से दूर करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य साहिदा जी ने आज भी वही प्रश्न पूछा है जो उन्होंने कल भी पूछा था। कल भी उनको जवाब दिया गया था और आज मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि मेवात क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या इस सरकार के समय की नहीं है वहां पर पीने के पानी की समस्या 100 साल से भी पुरानी है। अध्यक्ष महोदय, कल इनके नेता सदन में आये थे इसलिए माननीय साथी का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो गया था और जवाब नहीं सुन पाये थे इसलिए आज ये ध्यान से सुन लें। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने मेवात क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए एक नये सिरे से योजना बनाई है। पिछले मुख्यमंत्री वहां पर एक ही स्कीम के लिए दो-दो बार पत्थर रखकर आये थे लेकिन एक भी पैसा वहां खर्च नहीं किया गया। जब हमने आकर कागज देखे। मुख्यमंत्री जी ने हमको बुलाया और यह कहा कि मेवात के लिए पेयजल योजना का शिलान्यास तो चौटाला जी करके गये थे अब तक तो वह बनकर तैयार हो गई होगी। उसका क्या हुआ? तो हमने पाया कि कागज के अन्दर भी इस प्रकार की कोई स्कीम नहीं है न कोई पैसा दिया गया, न कोई नक्शा बनाया गया और न ही कोई सर्वे करवाया गया। कुछ भी हमें वहां नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने नये सिरे से "राजीव गांधी पेयजल योजना" बनाई है। भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसका नाम है राईट्स। यह जो राईट्स एजेंसी है वह तकरीबन हज़ारों करोड़ों रुपये के जो प्रोजैक्ट्स हैं उनके सर्वे और स्पैशल सर्वे करके उसकी प्लानिंग करती है। उनसे हमने उसकी प्लानिंग करवाई है। 405 करोड़ रुपये का यह प्रोजैक्ट है। अध्यक्ष महोदय, शायद यह देश की सबसे बड़ी पेयजल योजना है और सबसे अनूठी पेयजल योजना भी है। अध्यक्ष महोदय, जो यमुना का एक्वेफर है वह आप भी समझ सकते हैं और हमने भी यमुना के एक्वेफर को टैब किया है। बाकायदा इसकी सैटेलाईट पिक्चर और इमेजिंग लेकर हमने यह देखा है कि मेवात के लिए परमानैंट वाटर सोर्स क्या हो सकता है? क्योंकि वहां कैनाल बेस्ड और दूसरा पानी जो अण्डर ग्राऊण्ड सबसॉयल वाटर है वह वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो हमने यह पाया कि तकरीबन 40 किलोमीटर पाईप लाईन से वाटर ले जाना पड़ेगा। जो दो जगह पर रैनीवैल्ज़ हैं तकरीबन-तकरीबन उन पर काम पूरा हो

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

गया है और वहां से 40-40 किलोमीटर पाईप लाईन जायेंगी और 300 के करीब टैस्टिंग स्टेशन बनायेंगे और लगभग कुल मिलाकर 15 हज़ार किलोमीटर पाईप लाईन डाली जायेगी। 250 से 300 के करीब ट्यूबवैल्ज़ इसको सप्लीमैंट करने के लिए एडीशनली डिप करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो कैचमैंट एरिया है जिसकी अभी डॉ० इन्दौरा बात कर रहे थे जो पहाड़ से पानी नीचे आयेगा उसके लिए हम 150 से अधिक इंजैक्शन बोरवैल्ज़ लगायेंगे ताकि हम मेवात में अण्डर ग्राऊंड वाटर टेबल को रिचार्ज़ कर सकें। इस सारे प्रोजेक्ट पर काम जारी है और मुझे इस बात की खुशी है कि हम इस योजना का पहला चरण 31 दिसम्बर, 2008 तक पूरा कर देंगे। इस प्रोजैक्ट को हमने जो मेवात में 2035 की पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से बनाया है। वैसे भी मेवात की जनसंख्या बाकी हरियाणा से ज्यादा है। इसलिए उसको भी स्टडी करके हमने 2035 की जनसंख्या के आधार पर इसे बनाया है। यह देश की सबसे अनूठी पेयजल परियोजना है क्योंकि इसमें आप उल्टी तरफ पानी उतारने वाले हैं। टोटल का टोटल पानी हम उसके अन्दर बूस्ट करके ले जायेंगे। माननीय सदस्य अगर इसका प्लान देखना चाहें तो वे मेरे कार्यालय में आ जायें मैं उनको वह भी दिखा दूंगा।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ये जो रैनीवैल्ज़ का बार-बार जिक्र कर रहे हैं यह परियोजना तो पिछली सरकार की देन है जिसके लिए 425 करोड़ रुपये दिये गये थे। उस समय जो मेवात डैवेल्पमैंट बोर्ड था उसने 26 लाख रुपये इसके सर्वे के लिए दिए थे उसमें चार नॉन ऑफिशियल मैम्बर थे और मैं भी उसका एक सदस्य था। लेकिन माननीय मन्त्री जी इसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि ऐसे ही श्रेय नहीं लिया जाता क्योंकि यह प्रोजेक्ट पिछली सरकार की देन है।

श्री अध्यक्ष : साहिदा खान जी, आप सवाल पूछिए क्योंकि यह क्वैश्चन ऑवर है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 6 साल तक इनकी सरकार थी। इन्होंने तब मेवात के लिये परियोजना क्यों नहीं बनवाई ? अध्यक्ष महोदय, सच बात तो यह है कि वह परियोजना डिजाईन ही नहीं करवाई गई। इन्होंने उस परियोजना का डिजाईन ही तैयार नहीं करवाया। आप इस बारे में हाऊस की एक कमेटी बना दें अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज़ मोशन लेकर आयें। They should bring a privilege motion against me. I challenge the Hon'ble Member, यह पहली बार राईट्स एजेंसी के द्वारा हमने उसकी बाकायदा डिजाईनिंग करवाई और इस परियोजना का काम शुरू किया है और पहले चरण को हम 31 दिसम्बर, 2008 तक पूरा कर देंगे। इनके नेता ने केवल 2 बार पत्थर रखवाने के अलावा और कोई कार्य वहां पर नहीं किया। अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा का तो मेरे पास कोई हल नहीं है।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भिवानी में दो वाटर वर्क्स हैं। इनमें से जो वाटर वर्क्स नम्बर एक है वह करीब-करीब 50 साल पुराना है और वह वाटर वर्क्स सोर्स ऑफ वाटर से करीब-करीब 4-5 किलोमीटर दूर था। आज के दिन भिवानी में एक और वाटर वर्क्स की बड़ी सख्त जरूरत है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या जूई फीडर के पास जहां पर वाटर वर्क्स के लिए जगह भी उपलब्ध है क्या वहां पर आप नया वाटर वर्क्स बनाने पर विचार करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह पृथक प्रश्न है इसलिए माननीय सदस्य इसकी पूरी डिटेल मुझे लिखकर भिजवा दें। इनकी बात को कंसीडर कर लिया जायेगा।

As far as second water works for Bhiwani is concerned, as I remember it is already on the cards.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अटेली के क्षेत्र में 4 गाँव ऐसे हैं जिनके लिए नहर बेस्ड स्कीम शुरू की गई थी। वह स्कीम अटेली में तो कम्पलीट हो गई है लेकिन कुबतापुर, मडलाना और कांवी के लिए नहर बेस्ड स्कीम अभी पूरी नहीं हुई है और उनकी वजह से लगभग 35 गाँवों में जो नये पानी के बोर होने थे, उनको इसलिए रोक दिया गया कि नहर बेस्ड स्कीम से पानी आ जायेगा। लेकिन अभी तक न तो वहाँ पर नहर बेस्ड स्कीम प्रोप्रली चालू हो पाई है और न ही बोर करने का काम चालू किया गया है। क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वे नहर बेस्ड स्कीम चालू करेंगे या ट्यूबवैल लगा कर हमें देंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह एक पृथक प्रश्न है। माननीय सदस्य मुझे लिख कर भिजवा दें, मैं इन्हें पूरी जानकारी लिखित में भिजवा दूंगा।

To Ply Bus from Narnaul to Nangal Chaudhary

***969 Sh. Radhey Sham Sharma Amar :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to ply the Haryana State Roadways bus from Narnaul to Nangal Chaudhary via Nizampur?

शिक्षा मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : नहीं श्रीमान् जी।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि नांगल चौधरी से वाया निजामपुर पहले भी बसें चलती थी। ये बसें 17 गाँवों को जोड़ती हैं। मैं मन्त्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ कि मेरे कहने पर इन्होंने वहाँ पर दो बसें चलाई भी थी लेकिन जी०एम० साहब ने उन बसों को दोबारा से बन्द कर दिया है। क्या इन 17 गाँवों के लिए जी०एम० ही नीति निर्धारण करेंगे या मन्त्री जी का भी उस पर कोई कंट्रोल है?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि नांगल चौधरी से नारनौल तक हरियाणा रोडवेज की बसें भी और राजस्थान रोडवेज की बसें भी चलती हैं। सर, इनका स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि नांगल चौधरी से वाया निजामपुर बसिज नहीं चल पा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर प्राईवेट बस सर्विस के तहत समितियों की बसिज चल रही थी लेकिन कुछ दिन पहले इन समितियों ने सरकार से मांग की थी कि ये रूट वायेबल नहीं हैं इसलिए उनके रूटों को बदल दिया जाये। डिपार्टमैंट ने यह एग्जामिन किया और पाया कि उनकी मांग वाजिब थी। इसलिए डिपार्टमैंट ने उन बसिज के रूटों को ट्रांसफर कर दिया है ताकि उनको ज्यादा नुकसान न हो। इसलिए नांगल चौधरी से वाया निजामपुर जो प्राईवेट सैक्टर की बसें चलती थी वे बन्द हो गई हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर भी जब माननीय सदस्य हमारे ध्यान में यह बात लेकर आये तो हमने इनके कहने के मुताबिक दो बसें जो अप-डाऊन करती हैं, वहाँ पर चलाई हैं। जहाँ तक 17-18 गाँवों की बात है, मुझे नहीं लगता कि नांगल चौधरी से निजामपुर तक इतने गाँव होंगे। इस रूट पर आगे इनका एक बड़ा गाँव है नयागाँव और वहाँ से रूट राजस्थान की ओर डाइवर्ट हो जाता है और वहाँ पर हमारी बसें भी उपलब्ध होती हैं और राजस्थान रोडवेज की बसें

[श्री मांगे राम गुप्ता]

भी मिलती हैं। नयागाँव से नांगल चौधरी तक 10 किलोमीटर का रूट जाता है, वहाँ जरूर इनको दिक्कत है। वहाँ पर इनके दो गाँव पड़ते हैं और वहाँ बस भी नहीं चलती। इनके कहने के मुताबिक हमने दो बसें चला रखी हैं फिर भी अगर ज्यादा जरूरत होगी तो एक-आध बस हम और चलाने की कोशिश करेंगे।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि वे रिकॉर्ड देख लें। अधिकारियों ने यह जवाब गलत दिया है। वहाँ बिल्कुल बस नहीं चलती है। यहाँ हाउस में गाँवों के लोग भी बैठे हैं। इसको चैक करवा लें यह बिल्कुल गलत बात है, अगर अधिकारी इस प्रकार की धोखाधड़ी करेंगे, मन्त्री जी को धोखा दे देंगे तो कैसे काम चलेगा?

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, माननीय सदस्य की शंका को वैरिफाई करें।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह नहीं कहता कि वे जो कह रहे हैं वह गलत है। वे जनता के नुमाइंदे हैं, हो सकता है कोई गलतफहमी इनको या हमारे अधिकारियों को हुई हो। अध्यक्ष महोदय, हम देख लेंगे कि कैसे हमारे अधिकारियों ने गलत जवाब भेजा है? मैं माननीय सदस्य को और हाउस को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी मांग के मुताबिक जो दो बसें चलाई गई हैं वे उसी रूट पर चलाई जायेंगी।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन रूट्स पर इन्होंने प्राईवेट बसें लगा रखी हैं वहाँ पर कॉलेज के छात्रों और बस वालों के बीच झगड़ा हो गया है। यह झगड़ा गाँवों की पंचायत तक पहुंच गया है और गाँवों वाले अपने निजी वाहनों से सवारियों को शहर तक छोड़ने जाते हैं और उन बसों का बाईकॉट कर दिया है। क्या मन्त्री जी इस समस्या का कोई समाधान करेंगे, कोई रोडवेज की बस चलाकर उन लोगों को सुख पहुंचाएंगे जिससे कॉलेज के लड़कों की भी परेशानी नहीं रहेगी?

श्री मांगे राम गुप्ता : सर, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है और यह बात सही है कि जहां हमारी सहकारी समितियों की बसें प्राईवेट सैक्टर में चलती हैं पब्लिक और स्टूडैंटस के ऑब्जैक्शन की वजह से इनमें से हमारे कई रूटस बन्द हो गये हैं। लोगों का ऑब्जैक्शन यह है कि सहकारी समितियों की बसें रूटस पर सही ढंग से नहीं चलती हैं जिसके कारण लोगों को बड़ी दिक्कत है। स्पीकर सर, जल्दी ही हम माननीय मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग बुला रहे हैं जिसमें इस प्राईवेट सैक्टर में सहकारी समितियों की बसें चलाने, उनको नये रूटस देने और नई पॉलिसी बनाने के बारे में फैसला लेने जा रहे हैं। सहकारी समितियों की बसों के बारे में कुछ गांवों में जो प्रॉब्लम आ रही है वह आगे नहीं रहेगी।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने एक वोल्वो बस सेवा शुरू की थी जो कुछ रूटस पर चलती थी। पीछे समाचार पत्र में यह पढ़ा था यह वोल्वो बसें चलानी बन्द कर दी गई हैं। ये बसें जो बन्द की गई हैं इसके क्या कारण हैं? क्या ये बसें घाटे के कारण बन्द कर दी गई हैं या कोई और कारण है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जब कोई काम शुरू किया जाता है तो उसको शुरू करने से पहले क्या उसका सर्वे नहीं करवाया जाता है? (विघ्न) स्पीकर सर, पंजाब में वोल्वो बसें अभी चल रही हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, वोल्वो बसें हमने बन्द नहीं की हैं बल्कि जो लोग इन बसों को ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने बन्द की हैं क्योंकि शायद उनको ये सूट नहीं कर थीं या फिर उनके लिए ये वायबल नहीं थी इसलिए उन्होंने बन्द कर दीं। अध्यक्ष महोदय, बसें बन्द करने के कारण हमने उनको नोटिस दिया है। एग्रीमैंट के मुताबिक हम उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि ये वोल्वो बसें फिर से चलाई जाएं और जिनके साथ पहले एग्रीमैंट था, बसें बन्द करने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। अध्यक्ष महोदय, ये वोल्वो बसें परिवहन महकमें की नहीं थी।

श्री रमेश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कुछ प्राइवेट को-आपरेटिव सोसाईटीज़ के द्वारा बसें चलाई जा रही थीं और फिर उनके रूटस बदल दिए गए लेकिन जिन रूटस पर पहले बसें चल रही थीं वहां पर अब बसें नहीं चल रही हैं जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अब वहां पर न तो को-आपरेटिव बसें चल रही हैं और न ही सरकारी बसें चल रही हैं (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हमने जी०एम० से पूछा था तो उन्होंने बताया कि प्राईवेट बसों वाले कहते हैं कि इन रूटस पर घाटे के कारण हम बसें नहीं चला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, जवाब तो मन्त्री जी ने देना है इसलिए आप बैठें और मन्त्री जी का जवाब सुनें।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से पहले भी यह बताने का प्रयास किया था कि प्राइवेट सैक्टर में सहकारी समितियों की बसें चलती थीं और उनमें से कुछ समितियों ने अपनी बसें चलानी बन्द कर दी थी। कुछ गांवों के लोगों और स्टूडैंटस के साथ इन बस वालों के साथ क्लैशिज़ हुए जिसके कारण बसें भी बन्द हुई और कई जगहों पर पुलिस थानों में केस भी दर्ज हुए। अध्यक्ष महोदय, हम उन रूटस पर बसों को जबरदस्ती नहीं चलवा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन रूटस पर जहां तक सरकारी बसें चलाने का सवाल है, हमारे पास इस समय इतनी बसें नहीं हैं कि इन रूटस पर बसें चलवा सकें। जनता की तकलीफ को हम महसूस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इस बारे में हम एक नई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं और आने वाले समय में उन रास्तों पर जहां पर सहकारी समितियों की बसें चलती थी और अब बन्द हो गई हैं सरकार की तरफ से कोई न कोई प्रबन्ध जल्दी ही किया जाएगा।

Setting Up of 33 K.V. Sub-Station at Village Kat-Kai

***995. Shri Naresh Yadav :** Will the Power Minister be pleased to State—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to setup a 33 K.V. power sub-station at village Kat-Kai of Ateli Constituency;

(b) if so, the time by which the construction work is likely to be started on the aforesaid sub-station;

(c) whether there is any proposal to install additional transformers, in the Ateli power house and 33 K.V. power station of Kati; and

(d) if so, the time by which the above said transformers are likely to be installed?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes, Sir. There is a proposal to setup a new 33 K.V. substation at village Kat-Kai of Ateli Constituency at an estimated cost of Rs. 165 lacs.

(b) Construction of this substation at village Kat-Kai is likely to start in 2008-09 and it will take about 8 months to complete the work after it starts.

(c) Yes, Sir. Augmentation of 132 K.V. substation Ateli with and additional 1x20/25 M.V.A. 132/133 K.V. capacity transformer has been approved at an estimated cost of Rs. 250 lacs. There is also a proposal to install to 10 M.V.A. 33/11 K.V. transformer in place of existing 5 M.V.A. 33/11 K.V. transformer at 33 K.V. substation Kanti at an estimated cost of Rs. 55 lacs.

(d) The work of augementation of 132 K.V. substation Ateli is likely to be completed be July, 2008 and that of 33 K.V. substation Kanti by May, 2008.

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का और खासतौर पर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले एक साल में हमारे यहां अटेली में एक 132 के०वी० का उपकेन्द्र और 33 के०वी० के 6 उपकेन्द्र मंजूर किए हैं। स्पीकर सर, पिछले सैशन में एडिशनल ट्रांसफार्मर कांटी में, नांगल चौधरी में, भासर में और दूबुलाना में लगने थे उस बारे में हम बार-बार अधिकारियों से पूछते थे तो वे कहते थे कि आ गए हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें यह पता चला कि वहां पर काम शुरू ही नहीं हुआ है। मन्त्री जी यह जो वहां पर डिम लाईट और कट की प्रोब्लम है उसको ठीक करने का एक यही तरीका है कि वहां पर एडिशनल ट्रांसफार्मर्ज लगें और अधिकारियों को भी यह कहा जाए कि वहां पर ट्रांसफार्मर्ज समय पर लगें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है वह वाजिब है इस बारे में मैंने अपने लिखित जवाब के डी पोरशन में बतलाया है कि 132 के०वी० सब-स्टेशन अटेली की आगुमैंटेशन जुलाई, 2008 में कम्पलीट कर देंगे। इसी तरह कांटी में 33 के०वी० का सब-स्टेशन मई, 2008 में पूरा कर देंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि यह जो कलायत शहर है यह बहुत ही पुराना है। क्या यहां पर जो 33 के०वी० सब-स्टेशन है उसको 132 के०वी० सब-स्टेशन में या 220 के०वी० सब-स्टेशन में कन्वर्ट करने का परपोजल है अगर है, तो यह कब तक बन जाएगा ? जब तक यह नहीं बन जाता है तब तक वहां पर 8 एम०वी०ए० या 10 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी रखने का कोई प्लान है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या जी को बताना चाहूंगा कि इनका जो प्रश्न है यह पृथक प्रश्न है। मैंने कल ही अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी और उसमें कैथल और कलायत के लोड को लेकर बातचीत की थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी स्पैशल कहा था कि कलायत के लोड को चैक करवाएं कि किस तरह से उसकी आगुमैंटेशन कर

सकते हैं। अभी जो कलायत में बिजली आती है उसका लोड नरवाना पर है। नरवाना आलरेडी ओवर लोडिड है। हम इस बारे में सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं कि इसको बतौर और शिमला के बीच में कहीं न कहीं बनाएं। आप जमीन के लिए हमारी थोड़ी सी मदद करें ताकि वहां पर 132 के०वी० सब-स्टेशन बन सके और जिस पर कलायत का लोड डाल सकें।

आई०जी० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि भिवानी रोड पर बीबीपुर गांव है और उसके आस-पास कलस्टर ऑफ विलेजिज हैं। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट के आदेश पर हम लोगों ने साढ़े चार एकड़ जमीन 132 के०वी० का सब-स्टेशन बनाने के लिए दी है। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इसका परपोज़ल कहां पर है और कब तक इसका परपोजल कार्यान्वित किया जाएगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है वह वाज़िब है और उनका यह प्रश्न पृथक है। इसकी रेडी इन्फर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है। मैं इस बारे में इनसे कहूंगा कि ये इस बारे में लिखवाकर भिजवा दें। हम मीटिंग बुलाकर और माननीय सदस्य को भी उसमें निमन्त्रण दे देंगे। हम इस बारे में प्रयास करेंगे कि उसमें समय सीमा निर्धारित हो जाए कि हम कब तक इसको पूरा कर देंगे।

Irregular/Illegal appointments of Class IV Employees in the Schools

***971. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Education Minister be pleased to State:—

(a) whether any complaint regarding irregular and illegal appointments of Class IV employees in the Schools in the State during the period from 1996 to 2005 was received by the Government; if so, the contents of the complaint.

(b) whether any enquiry was got conducted in the complaint in (a) above, if so, the contents of the enquiry report along with the names of officers/officials found responsible for the illegal/irregular appointment of class IV employees;

(c) whether the role of any Politician was alleged by any person during the course of enquiry in (b) above; and

(d) the action taken against the officers/officials found responsible for irregular/illegal appointments in (b) above?

शिक्षा मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : श्रीमान जी, स्टेटमैंट विधान सभा के पटल पर रखी जाती है।

स्टेटमैंट

(क) हां, श्रीमान जी। वर्ष 1996-2005 के दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति बारे दो शिकायतें प्राप्त हुई थी।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

(ख) हां, श्रीमान जी। पहली जांच रिपोर्ट में 138 व्यक्तियों द्वारा 198 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनियमित तथा गलत ढंग से नियुक्ति बारे मामला प्रकाश में आया। उक्त 138 व्यक्तियों की सूची अनुबन्ध 'क' पर संलग्न है।

दूसरी जांच रिपोर्ट के अनुसार तीन व्यक्तियों द्वारा जाली हस्ताक्षर करके विभाग में नियुक्ति प्राप्त की गई।

(ग) नहीं, श्रीमान जी।

(घ) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अनुबन्ध 'क'

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में चूककर्ता अधिकारियों की सूची :-

महेन्द्रगढ़

1 मिठुराम चोपड़ा, भूतपूर्व एस०डी०ई०ओ०, महेन्द्रगढ़, उप जिला शिक्षा अधिकारी, नारनौल-I

2 छोटे लाल तत्कालीन, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० खतौदड़ा - खंड शिक्षा अधिकारी, महेन्द्रगढ़

3 जय सिंह, भूतपूर्व मुख्याध्यापक, रा०उ०वि० छित्तरौली - खण्ड शिक्षा अधिकारी, कनीना

4 जय दलाल, भूतपूर्व खंड शिक्षा अधिकारी, अटेली

5 भूप सिंह, प्राचार्य रा०व०मा०वि० नारनौल

6 जगदीश चंद, तत्कालीन प्राचार्य, रा०व०मा०वि० गौद

7 मुरारी लाल आर्य, तत्कालीन मुख्याध्यापक, रा०उ०वि०, गोकलपुरा

8 गणपत राम सैनी, तत्कालीन प्राचार्य, रा०व०मा०वि० सिरोही बहाली

9 बलदेव कृष्ण सचदेवा, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, नारनौल

10 कांशी राम, तत्कालीन मुख्याध्यापक रा०उ०वि० जाडवा

11 मूल चंद, तत्कालीन प्राचार्य, रा०व०मा०वि० धोलेड़ा

12 बलबीर सिंह तत्कालीन प्राचार्य रा०उ०वि० राजावास

हिसार

13 विश्वामित्र, उपमंडल शिक्षा अधिकारी, हांसी

14 पुष्पा गिरधर, मुख्याध्यापिका रा०उ०वि० काजला

15 भूप सिंह मलिक, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० उमरा

16 दलबीर सिंह मुख्याध्यापक मजदपुर

17 अजीत सिंह डाला, जिला शिक्षा अधिकारी हिसार

18 कृष्णा रानी, मुख्याध्यापिका रा०उ०वि०, चीकनवास

19 हेत राम लांबा, एस०डी०ई०ओ०, आदमपुर

20 संतोष कुमारी, एस०डी०ई०ओ० हांसी

21 जगदीश चंद्र, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० खरकडा

22 मनोहर लाल, प्राचार्य रा०व०मा०वि० तेलनवाली

23 सुनीता हंस, मुख्याध्यापिका रा०क०उ०वि० आदमपुर

24 आशा रानी, मुख्याध्यापिका रा०क०उ०वि० खारा बरवाला

25 मान सिंह मुख्याध्यापक क०उ०वि० खारा बरवाला

जींद

26 किताब सिंह, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० मनोहरपुर

27 कपूर सिंह, एस०डी०ई०ओ० सफींदो

28 अजीत सिंह कादयान, एस०डी०ई०ओ० सफींदो

29 रणबीर सिंह मुख्याध्यापक रा०उ०वि० भम्भेवा, जुलाना

30 आर० हुड्डा, मुख्याध्यापक भदलाना

31 कर्मवीर सिंह, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० भम्भेवा

32 रघुबीर सिंह, एस०डी०ई०ओ० सफींदो

33 राम कुमार, एस०डी०ई०ओ० सफींदो

34 विद्या मलिक, जिला शिक्षा अधिकारी, जींद

35 जी०बी० सिंह, मुख्याध्यापक रा०क०उ०वि० खटकड

36 तारा चंद, मुख्याध्यापक काकरोड

37 सुनहेरा सिंह, मुख्याध्यापक रा०क०उ०वि० बरोदा

38 सतपाल मलिक, एस०डी०ई०ओ० नरवाना

39 रिसाल सिंह, प्राचार्य रा०व०मा०वि० धमतान साहिब, नरवाना

40 बिमला देवी, (डी०ई०ओ०) मुख्याध्यापिका रा०क०उ०वि० धनोदा

41 तेलु राम एस०डी०ई०ओ० नरवाना

42 सुरेन्द्र सिंह, मुख्याध्यापक जलभेरा, नरवाना

[श्री मांगे राम गुप्ता]

फतेहाबाद

43 एच०एस० रंगवा, एस०डी०ई०ओ० फतेहाबाद

44 प्रेम लता, मुख्याध्यापिका ढांगर, फतेहाबाद

45 शेर सिंह, प्राचार्य रा०व०मा०वि० भूना

46 राम कुमार, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० बाजीपुर

47 चुन्नी लाल, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० मानावली

भिवानी

48 राम पाल, खंड शिक्षा अधिकारी, बवानी खेड़ा

49 बीर सिंह, लेखा खंड शिक्षा अधिकारी, सिवानी

50 निर्मला स्योराण, खंड शिक्षा अधिकारी, बाढड़ा

51 रामपाल, खंड शिक्षा अधिकारी, दादरी

52 अत्तर सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी, लोहारू

53 बिमला स्योराण, खंड शिक्षा अधिकारी, बोंदकलां

54 रणधीर सिंह बलोदा, खंड शिक्षा अधिकारी, भिवानी

55 सतबीर सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी, तोशाम

56 शोभाकर, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० निमड़ीवाली

57 शांतिस्वरूप, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० सिरसी

58 धर्मवीर, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० आदमपुर, दादरी

59 मान सिंह शर्मा, तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी एवं एस०डी०ई०ओ० लोहारू

60 जगपाल सिंह, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० मढोली कलां, भिवानी

61 उमेद सिंह, एस०डी०ई०ओ०, लोहारू

62 मोमा राम, विज्ञान अध्यापक एवं मुख्याध्यापक रा०मा०वि०, सोरेडा कादिम, भिवानी

63 कर्ण सिंह, विज्ञान अध्यापक, रा०म०वि० सुरपुर कलां, भिवानी

64 मदन लाल, मुख्याध्यापक रा०मा०वि० सोरेडा जादिद, भिवानी

65 बृज राज, मुख्याध्यापक रा०मा०वि० गरवा, भिवानी

66 संतोष कुमारी, मुख्याध्यापिका रा०उ०वि० फालिया मिमा, भिवानी

67 राम पाल, मुख्याध्यापक रा०मा०वि० बुसान, भिवानी

68 कृष्ण कुमार, एस०एस० अध्यापक रा०मा०वि० कुंडलवास, भिवानी

69 जगपाल सिंह, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० बडदु चना, भिवानी

70 रमेश चन्द्र, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० बडदु चना, भिवानी

71 मुलाराम शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी

72 प्रेम सिंह, विज्ञान अध्यापक, रा०उ०वि० पाहड़ी, भिवानी

73 राजपाल मुख्याध्यापक रा०उ०वि० मंदन भिवानी

74 खुशी राम, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० भेरा, भिवानी

75 प्रेम लता, मुख्याध्यापिका रा०उ०वि०, रावलधी, भिवानी

76 ईश्वर सिंह, स्योराण, एस०डी०ई०ओ० भिवानी

77 सांभर मल, एस०डी०ई०ओ० बवानी खेड़ा

78 जगपाल सिंह, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० सेहर

79 धर्मपाल तंवर एस०डी०ई०ओ० भिवानी

80 रघुबीर सिंह, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० बाढड़ा

81 कंवर सिंह, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० बजीना

82 राजमल, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० खानक

83 शिवा भांकड, एस०डी०ई०ओ० भिवानी

84 राम कुमार, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० पटौदी

85 रोशनी शर्मा, प्राचार्य रा०क०व०मा०वि० चरखी दादरी

86 ओम प्रकाश, मुख्याध्यापक रा०क०उ०वि० बड़ेसरा

87 प्रकाश चंद्र, मुख्याध्यापक रा०उ०वि० नवांराजगढ़

अंबाला

88 धर्मपाल एस०डी०ई०ओ० अंबाला

89 कौशला देवी, मुख्याध्यापिका, बकनौर

90 कुमारी शशी सूद, मुख्याध्यापिका, मटेदी सेखां

91 सुदर्शन बंशी, मुख्याध्यापक, चौड़मस्तपुर

92 सुरेन्द्र सिंह, मुख्याध्यापक, सुलतानपुर

93 कांता गुप्ता, मुख्याध्यापिका, कानपुर

94 धूप सिंह राठी, जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला

95 नसीब सिंह, मुख्याध्यापक, बैबल

[श्री मांगे राम गुप्ता]

96 सुभाष गुप्ता, एस०डी०ई०ओ०, अंबाला

98 केहर सिंह, मुख्याध्यापक, भराडी कलां

99 गुरदयाल सिंह, मुख्याध्यापक, काधी माजरा

100 बलवंत कौर, मुख्याध्यापक, नारायण गढ़

101 आर०एल० रैना, एस०डी०ई०ओ०, नारायणगढ़

102 अमृत कौर गिल, मुख्याध्यापक, अंबली

103 भगतव स्वरूप, मुख्याध्यापक, जौली

104 विजय गुप्ता, प्राचार्य, सम्लेहड़ी

105 जीवन आशा, मुख्याध्यापिका, साहा

106 धर्मपाल शर्मा, एस०डी०ई०ओ०, अंबाला

107 त्रिलोचन सोढी, मुख्याध्यापक, पिलखणी

108 सुरेन्द्र कुमार गरचा, मुख्याध्यापक, मुलाना

कैथल

109 मेघ नाथ, प्राचार्य, कांथली

110 रेखा रानी, प्राचार्य

कुरूक्षेत्र

111 जसमेर सिंह, मुख्याध्यापक, मंगोली

112 राजेन्द्र सिंह, एस०डी०ई०ओ०, थानेसर

113 अमरजीत कौर, मुख्याध्यापक, नांगला

114 स्वर्ण कांता, मुख्याध्यापिका, सरीफगढ़

झज्जर

115 ओ०पी० सिंह, प्राचार्य रा०व०मा०वि०, झांसवा

116 हंस राज, मुख्याध्यापक रा०मा०वि०, तुम्बाहेड़ी

सोनीपत

117 रामफल, प्राचार्य रा०व०मा०वि०, बरोदा

118 सिलक राम, एस०डी०ई०ओ०, गोहाना

119 शकुंतला मुखिजा, प्राचार्य रा०व०मा०वि०, गन्नौर

120 मेघ राज, प्राचार्य रा०व०मा०वि०, पिपली खेड़ा

121 दया चंद राठी, प्राचार्य रा०व०मा०वि०, पांची जटाण

122 वेद वृत, इन्चार्ज रा०व०मा०वि०, रोहणा

123 चतर सिंह, प्राचार्य रा०व०मा०वि०, तिहाड़ मलिक

124 वेद पाल, अध्यापक रा०व०मा०वि०, तिहाड़ मलिक

125 राम सिंह, मुख्याध्यापक रा०मा०वि०, गढ़ीवाला

126 महाबीर सिंह, मुख्याध्यापक रा०उ०वि०, खेड़ी तागा

127 ऊषा गिरधर, मुख्याध्यापिका रा०उ०वि०, नांगल कलां

128 दयानंद प्राचार्य रा०व०मा०वि०, पपनेड़ा

129 दुर्गा गौड, प्राचार्य, डाईट, बीसवा मील

130 तेज राम मलिक, मुख्याध्यापक रा०उ०वि०, महलाणा

131 फूल देवी, मुख्याध्यापक रा०उ०वि०, महेन्दीपुर

132 सत्यनारायण, मुख्याध्यापक रा०उ०वि०, महेन्दीपुर

133 आनंद सिंह, मुख्याध्यापक रा०उ०वि०, सरदाना

पानीपत

134 धर्मवीर सिंह, रा०व०मा०वि०, महोटी

135 चांदना चौधरी, प्राचार्य रा०व०मा०वि०, जी०टी० रोड पानीपत

136 जय भगवान, मुख्याध्यापक रा०उ०वि०, छछड़ाना

137 सुशीला जैन, तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी, इसराना

करनाल

138 बी०एस० धालीवाल, खंड शिक्षा अधिकारी, असंध

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने सदन के पटल पर जानकारी रखी है और इन्होंने सवाल के पार्ट "सी" के जवाब में 'नो' किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति का इन नियुक्तियों में कोई दखल था? स्पीकर साहब, इन्होंने इन्कार किया है। हरियाणा प्रदेश में चौटाला जी के राज में चपरासियों से लेकर एच०सी०एस० तक की जितनी भी भर्तियां हुई उसमें नाकाबिल लोगों को, नागवारा लोगों को पैसा लेकर, रिश्वत लेकर बिठाया गया। स्पीकर साहब, कौआ चले हंस की चाल की कहावत को ये लोग सही सिद्ध कर रहे हैं। जो लोग नियुक्तियों में सरेआम गड़बड़ी किया करते थे आज वे अखबारों में अपनी स्टेटमैंट दे रहे हैं। स्पीकर साहब, इनको शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है। स्पीकर साहब, रिप्लाई में भिवानी और कई दूसरे जिलों का जिक्र है तो भिवानी से तो सांसद अजय सिंह चौटाला थे लेकिन उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने गरीब लोगों तक नहीं बख्शा।

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, ये क्वैश्चन पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं। इन्होंने खुद लाभ का पद लिया है इसलिए हरियाणा को नुक्सान तो इन्होंने किया है।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, इन क्लास फोर्थ ईम्पलाईज की अप्वायंटमैंटस की अथोरिटी स्कूलों के हैड मास्टर्ज़ और प्रिंसिपलज़ की थी। इन्होंने अपने हिसाब से ही जहां उचित समझा, गलत थे या ठीक थे, उनको लगा दिया। इसमें राजनीतिक रिपोर्ट हमारे पास कार्ड पर नहीं है। किसी राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से इनको लगाया गया हो ऐसी रिपोर्ट फाईल पर नहीं है। लेकिन जब यह शिकायत हमारे सामने आयी तो इंक्वायरी करवायी और इसलिए जबाव में भी यह बताया गया कि 198 आदमी गलत तरीके से सिलैक्ट हुए और लगे। स्पीकर सर, इसमें 138 अप्यांटमैंट अथोरिटी कसूरवार साबित पायी गयी हैं। उनके खिलाफ हम कार्यवाही करने जा रहे हैं। स्पीकर सर, पहली शिकायत के मुताबिक हमने बताया था कि इनको हटाने का हमने फैसला भी किया था इनको शो कॉज नोटिस भी दिए गए थे लेकिन ये लोग हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट ने हमारे शो कॉज नोटिस को खारिज कर दिया है। उसके बाद हमने रैगुलर इंक्वायरी के लिए विजीलैंस ब्यूरो को मामला भेज रखा है। जब विजीलैंस ब्यूरो की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद पूरी कार्यवाही कानून के मुताबिक की जाएगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने जो विजीलैंस ब्यूरो को इंक्वायरी करवाने की बात कही है मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब ये अपने जबाव में मानते हैं कि नियुक्तियां गलत हुई हैं तो फिर विजीलैंस ब्यूरो इनकी जांच क्या करेगा? इनकी तुरन्त छुट्टी करके नौकरी से निकालकर जांच उन लोगों की होनी चाहिए जिनका इन नियुक्तियों को करवाने में हाथ रहा है। स्पीकर साहब, उस वक्त की सरकार में तीन बाप बेटों का ही राज चला करता था। इनके बिना पूछे तो उस समय प्रदेश के अंदर पत्ता भी नहीं हिलता था इसलिए वे लोग इन गरीब लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए गुनाहगार हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस मामले में विजीलैंस ब्यूरो को ओम प्रकाश चौटाला और उनके दो बेटों की जांच के लिए वे कहेंगे कि इनका भी दायरा इसमें देखें।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि जब हमारे सामने यह शिकायत आयी और इसकी हमने जांच करवाई तो हमने इस शिकायत को सही समझा। उसी के मुताबिक हमने उनको हटाने के लिए एक कानूनी कार्यवाही का प्रोसैस शुरू किया। उनको शो कॉज नोटिस दिए गए लेकिन वे उसके खिलाफ हाईकोर्ट में चले गए और हाईकोर्ट ने हमारे उन शो कॉज नोटिस को क्वैश कर दिया और कहा कि पहले बकायदा प्रोपर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद ही कोई ऐक्शन लें। स्पीकर सर, अब हमने विजीलैंस ब्यूरो को इस मामले की प्रोपर इंक्वायरी करवाने के लिए केस भेज दिया है। जब उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हम कार्यवाही कर सकेंगे।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी को ज्ञान है कि शिक्षा विभाग में 'सी' और 'डी' कैटेगरीज के बहुत से पद रिक्त हैं, स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अगर पद रिक्त हैं तो इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, माननीय सदस्य की यह बात तो वाज़िब है कि हमारे विभाग के क्लास फोर की काफी पोस्टस खाली हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी यह फैसला किया है

कि जितनी भी निचले लैवल पर फोर्थ क्लास की पोस्ट्स खाली हैं, शिक्षा विभाग में ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों में भी यदि छोटे कर्मचारियों की पोस्ट्स खाली हैं तो उनको कलैक्ट करके दोबारा फिर से भरने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।

Mr. Speaker : Hon'ble members, now question hour is over.

(नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर)

Shortage of L.P.G.

***926. Shri S.S. Surjewala :** Will the Deputy Minister be pleased to state:—

(a) whether there is an acute shortage of LPG in Haryana; if so, the steps taken or proposed to be taken by the Haryana Government to remove the shortage of LPG; and

(b) whether Government has received the complaints regarding the black marketing of LPG; if so, whether any case has been registered in this regard?

उप-मुख्यमंत्री (श्री चन्द्र मोहन) : श्री मान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

एल०पी०जी० की कमी

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान एल०पी०जी० की बहुत कमी थी लेकिन अब काफी हद तक इसकी उपलब्धता में सुधार हुआ है।

राज्य सरकार द्वारा एल०पी०जी० की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

- सरकार और निदेशालय दोनों स्तरों पर स्थिति का नियमित पुनर्निरीक्षण तथा संचालन किया जा रहा है।
- तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार तालमेल तथा स्थिति की समीक्षा की जा रही है।
- व्यापारिक प्रतिष्ठान (होटल/ढाबा/रैस्टोरैन्ट) तथा मोटर वाहन चालकों द्वारा घरेलू गैस के अनाधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए नियमित जाँच की जाती है।
- विभाग के माप तथा तोल प्रभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को सही वजन के सिलैण्डर प्राप्त हों, बारे एल०पी०जी० वितरकों की नियमित रूप से जांच की जाती है।
- इसके अतिरिक्त, खाद्य एवं पूर्ति विभाग हरियाणा द्वारा एल०पी०जी० वितरकों की नियमित जांच की जाती है कि वे द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 की किसी भी प्रकार की उल्लंघना न करें।

[श्री चन्द्र मोहन] :

- उपरोक्त के अलावा, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को निर्देश दिये गये हैं कि सर्वेक्षण करके जाली उपभोक्ताओं को समाप्त करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा विवाह आयोजनों में केवल व्यापारिक सिलेण्डरों का ही प्रयोग हो।

(ख) . हाँ श्रीमान जी, पुलिस में दर्ज मामले तथा अन्य की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :-

	2007-08 (1/2008 तक)
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों द्वारा पुलिस में दर्ज करवाए मामले	7
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों द्वारा तेल कम्पनियों को भेजे गये मामले	6
नाप-तोल विभाग द्वारा जब्त राशि	1,25,500.00 रु०
तेल कम्पनियों द्वारा जितने एल०पी०जी० वितरकों को जुर्माना किया गया	10
जुर्माने की कुल राशि	3,98,432.00 रु०
समाप्त किये गये एल०पी०जी० वितरकों की संख्या	1
एल०पी०जी० वितरकों की संख्या जिन्हें कैश एंड कैरी रिबेट से वर्जित किया गया	1
एल०पी०जी० वितरकों की संख्या जिन्हें तेल कम्पनियों द्वारा चेतावनी दी गई	6

To imrove the Drainage System in Bhiwani

***947. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Water Supply and Sanitation Minister be pleased to state:—

(a) whether the Government is aware of the fact that drainage system of Bhiwani City is very inefficient: and

(b) if the reply to (a) above is in affirmative, the steps taken to improve the drainage system in Bhiwani?

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

इस समय भिवानी शहर में बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था के लिए 32.80 किलोमीटर बरसाती पानी का सीवर, 5 किलोमीटर बरसाती पानी का नाला, 13 सहायक पम्पिंग स्टेशन तथा डिस्पोजल कार्य पर विभिन्न क्षमता के 20 पम्प लगाए गए हैं। इस बरसाती पानी के निकासी प्रणाली पर कुल 241.00 लाख रुपये खर्च हुए जिसमें से 206.00 लाख रुपये वर्ष 2005-06 से अब तक उपलब्ध किए गए हैं। अधिक वर्षा और पानी इकट्ठा होने पर इसके अलावा शहर की मल निकास प्रणाली जिसमें 185.75 किलोमीटर पाईप सीवर, 5.5 किलोमीटर सलैज कैरियर तथा 6.5 किलोमीटर की खुली नालियाँ हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं। इकट्ठे हुए बरसाती पानी की निकासी मुख्य पम्पिंग स्टेशन लोहारू रोड देवसर चुंगी के निकट तथा ढाणा रोड पम्पिंग स्टेशन से की जाती है। सारे शहर के बरसाती पानी की निकासी के लिए यह प्रणाली पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। बरसाती पानी तथा शुद्ध मल की डिस्पोजल की क्षमता को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने हेतु सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार 2123.00 लाख रुपये की लागत से भिवानी घग्गर ड्रेन का निर्माण कर रही है। इसका निर्माण 30.06.2009 तक सम्पन्न होने की सम्भावना है। इस कार्य से शहर के बरसाती पानी की निकास प्रणाली में बढ़ोतरी होगी जिससे अधिक सुचारू डिस्पोजल होगी। इसके उपरान्त जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग शहर के अन्य क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उपयुक्त योजना बनाएगा।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Misappropriation or Bungling in purchase of Teacher Learning Material

115. Shri Karan Singh Dalal : Will the Education Minister be pleased to state:—

(a) whether any complaints were received regarding misappropriation or bungling in the purchase/distribution of Teacher Learning Material and disbursement of funds for school Environment out of SSA (Sarav Siksha Abhiyan) funds during the year 2005 till date in the State; and

(b) If so, the contents of such complaints alongwith the action taken thereon?

शिक्षा मन्त्री (मांगे राम गुप्ता) :

(क) हाँ श्रीमान जी।

(ख) फण्डज़ का दुरुपयोग, गलत खरीद, नियमों की उल्लंघना और दस्तावेजों में साजिश करने की शिकायतें जिला फरीदाबाद, भिवानी, मेवात, महेन्द्रगढ़ और कैथल जिलों से प्राप्त हुई थी। नौ कर्मचारियों के विरूद्ध एफ०आई०आर० दर्ज करवाई गई है। दो मामलों में चौकसी विभाग के द्वारा जांच करवाई जा रही है। दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

Up-Gradation of Schools in District Mahendergarh

121. Sh. Naresh Yadav : Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) the total number of schools up-graded in district Mahendergarh during the year 2005-06 together with the block-wise details thereof; and

(b) the names of the schools of above said district the proposal for the up-gradation of which is under consideration of the Government in the ensuing academic session?

शिक्षा मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : श्री मान जी,

(क) जिला महेन्द्रगढ़ में वर्ष 2005-06 के दौरान 20 प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा माध्यमिक विद्यालय तक बढ़ाया गया था। उनकी खण्डवार सूची अनुबन्ध 'ए' पर उपलब्ध है। वर्ष 2005-06 के दौरान कोई भी विद्यालय माध्यमिक से उच्च तथा उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तरोन्नत नहीं किया गया।

(ख) वर्तमान में जिला महेन्द्रगढ़ के किसी भी सरकारी विद्यालय का आगामी शैक्षणिक सत्र में दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अनुबन्ध 'ए'

जिला महेन्द्रगढ़ - 20

	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	खण्ड
1.	रा०मा०वि० गुवानी महेन्द्रगढ़	5462	अटेली
2.	रा०मा०वि० बचानी महेन्द्रगढ़	5454	कनीना
3.	रा०मा०वि० धारा महेन्द्रगढ़	5457	कनीना
4.	रा०मा०वि० खरखेरा बास महेन्द्रगढ़	5458	कनीना
5.	रा०मा०वि० खेरा महेन्द्रगढ़	5453	कनीना
6.	रा०मा०वि० नंगल हरनाथ महेन्द्रगढ़	5451	कनीना
7.	रा०मा०वि० सेलंग महेन्द्रगढ़	5456	कनीना
8.	रा०मा०वि० तलवाणा महेन्द्रगढ़	5459	कनीना
9.	रा०मा०वि० बलाना महेन्द्रगढ़	5443	महेन्द्रगढ़
10.	रा०मा०वि० बास खुडाना महेन्द्रगढ़	5449	महेन्द्रगढ़
11.	रा०मा०वि० माजरा कलां महेन्द्रगढ़	5450	महेन्द्रगढ़
12.	रा०मा०वि० मालरा सराय महेन्द्रगढ़	5448	महेन्द्रगढ़
13.	रा०मा०वि० प्यागा महेन्द्रगढ़	5455	महेन्द्रगढ़
14.	रा०मा०वि० सिसोठ महेन्द्रगढ़	5452	महेन्द्रगढ़

15. रा०मा०वि० ढाणी मालियां महेन्द्रगढ़	5460	नांगल चौधरी
16. रा०मा०वि० लुजोता महेन्द्रगढ़	5461	नांगल चौधरी
17. रा०मा०वि० बादोपुर महेन्द्रगढ़	5447	नारनौल
18. रा०मा०वि० जाखनी महेन्द्रगढ़	5445	नारनौल
19. रा०मा०वि० खोरमा महेन्द्रगढ़	5444	नारनौल
20. रा०मा०वि० तेहला महेन्द्रगढ़	5446	नारनौल

Officers of Haryana Civil Medical Service on leave

116. Sh Karan Singh Dalal : Will the Health Minister be pleased to state:—

(a) the names of officers of Haryana Civil Medical Services of Health Department alongwith the period and kind of Leave/Absence who are on leave or absent for more than six months as on 1st March, 2008.

(b) the names of officers in(a) above who have gone abroad with prior permission of the competent authority and who are over staying alongwith the action taken thereon;

(c) the names of the officers in (a) above who proceeded abroad without prior permission of the competent authority alongwith the action taken thereon;

स्वास्थ्य मन्त्री (बहिन करतार देवी) : श्रीमान जी,

(क) सूचना सदन के सम्मुख तालिका भाग-I पर प्रस्तुत है।

(ख) सूचना सदन के सम्मुख तालिका भाग-II पर प्रस्तुत है।

(ग) सूचना सदन के सम्मुख तालिका भाग-III पर प्रस्तुत है।

तालिका नं०-1

हरियाणा सिविल चिकित्सा अधिकारियों के नाम जो दिनांक 1.3.08 को 6 मास से अधिक अवकाश-अनुपस्थित हैं:—

क्र० संख्या	हरियाणा सिविल चिकित्सा अधिकारी का नाम	अनुपस्थिति की तिथि	अवकाश की तिथि	किस तरह का अवकाश	
1	2	3	4	5	6
1.	डा० श्रीमती दीप्ती कोल, चिकित्सा अधिकारी, ई०एस०आई०, एन०एच०-3, फरीदाबाद	22.9.99	—	—	
2.	डा० श्रीमती अल्का अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डीघल, झज्जर	18.10.99	—	—	

[बहिन करतार देवी]

1	2	3	4	5	6
3.	डा० श्रीमती सोनिया लाम्बा, चिकित्सा अधिकारी, सी०डी० सैक्टर-7, फरीदाबाद	14.2.01	—	—	
4.	डा० राज कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, ई०एस०आई०, एन०एच०-3, फरीदाबाद	14.3.02	—	—	
5.	डा० कविता यादव, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मीरपुर, रिवाड़ी	4.5.02	—	—	
6.	डा० संजय बिश्नोई, चिकित्सा अधिकारी ई०एस०आई० हस्पताल, जगाधरी	3.11.02	—	—	
7.	डॉ० श्रीमती कविता राणा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौलथा (पानीपत)	9.6.03	—	—	
8.	डा० श्रीमती सुमन, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाट, जीन्द	20.8.03	—	—	
9.	डा० मनोज कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य हस्पताल, कैथल	3.9.03	—	—	
10.	डा० सुनील कुमार मोंगा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारिया, सिरसा	20.10.03	—	—	
11.	डा० अतुल खेड़ा, चिकित्सा अधिकारी, समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तोशाम, भिवानी	21.10.03	—	—	
12.	डा० आनंद बेरी, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जजवंती जीन्द	29.1.2004	—	—	
13.	डा० श्रीमती सुषमा पासी, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढाकला, झज्जर	15.4.04	—	—	
14.	डा० अरूण कुमार, चिकित्सा अधिकारी, ई०एस०आई० डिस्पैंसरी, एन-1, फरीदाबाद	14.5.04	—	—	
15.	डा० श्रीमती मीना गोयल, चिकित्सा अधिकारी सामान्य हस्पताल, पानीपत	21.6.04	—	—	
16.	डा० रमीन्द्र सिंह, चिकित्सा अधिकारी सामान्य हस्पताल, पानीपत	12.7.04	—	—	

1	2	3	4	5	6
17.	डा० धर्मेन्द्र ज्यानी, चिकित्सा अधिकारी सामान्य हस्पताल, डबवाली, सिरसा	20.10.04	—	—	
18.	डा० मुनीष शांडिल्य, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामराय, जीन्द	1.11.2004	—	—	
19.	डा० गिरिश कुमार, चिकित्सा अधिकारी सामान्य स्वास्थ्य केन्द्र, महेन्द्रगढ़	1.12.04	—	—	
20.	डा० अनिल भाटिया, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, फतेहाबाद	4.2.05	—	—	
21.	डा० श्रीमती सीमा बंसल, चिकित्सा अधिकारी ई०एस०आई० डिस्पैंसरी, एन-3, फरीदाबाद	28.2.05	—	—	
22.	डा० बिपुल चौधरी, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वजीराबाद, गुड़गांव	2.5.05	—	—	
23.	डा० अशोक गुप्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जुलाना, जीन्द	12.5.2005 निलम्बित	—	—	
24.	डा० सुनील बजाज, चिकित्सा अधिकारी सामान्य हस्पताल टोहाना, फतेहाबाद	7.6.05	—	—	
25.	डा० श्रीमती रीतु राज देव, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरखास, सोनीपत	1.08.05	—	—	
26.	डा० जोगिन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य स्वास्थ्य केन्द्र, खड़करामजी, जीन्द	8.8.2005	—	—	
27.	डा० कमल नैन सिंहाग, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरीवाला, सिरसा	13.8.05	—	—	
28.	डा० राजेश बतरा, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य हस्पताल, रेवाड़ी	1.10.05	—	—	
29.	डा० श्रीमती प्रिया शर्मा, डी०टी०बी०ओ०, गुड़गांव	14.10.05	—	—	

[बहिन करतार देवी]

1	2	3	4	5	6
30.	डा० अजेश गोयल, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुस्तफाबाद	7.11.05	—	—	
31.	डा० जितेन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी सामान्य हस्पताल, कैथल	4.12.05	—	—	
32.	डा० श्रीमती सुमन फोगाट चिकित्सा अधिकारी, समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भनहेरू, भिवानी	5.12.2005	—	—	
33.	डा० मोहर सिंह, उप-निदेशक (एस०एस०)	5.12.05	—	—	
34.	डा० श्रीमती विपलागढ़, चिकित्सा अधिकारी ई०एस०आई, रिवाड़ी	22.12.05	—	—	
35.	डा० अशोक भाटिया, चिकित्सा अधिकारी ई०एस०आई० हस्पताल, एन-1, फरीदाबाद	22.2.06	—	—	
36.	डा० श्रीमती ललीता सांगवान, चिकित्सा अधिकारी सामान्य अस्पताल, झज्जर	24.2.2006	—	—	
37.	डा० बिजेन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीघल, झज्जर	1.3.06	—	—	
38.	डा० संदीप एम० कुमार, चिकित्सा अधिकारी सामान्य हस्पताल, हेली मंडी, गुड़गांव	22.4.06	—	—	
39.	डा० श्रीमती नीतू यादव, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरखास, सोनीपत	6.5.06	—	—	
40.	डा० जोगिन्द्र पाल, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरखोदा, सोनीपत	24.5.06	—	—	
41.	डा० रवीन्द्र गिल, चिकित्सा अधिकारी सामान्य हस्पताल, जीन्द	14.6.2006	—	—	
42.	डा० जितेन्द्र कौर, चिकित्सा अधिकारी सामान्य हस्पताल, पानीपत	9.7.06	—	—	
43.	डा० सुनील कुमार, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बापोली, पानीपत	1.8.06	—	—	
44.	डा० श्रीमती नीरजा कुमारी, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमरगढ़, जीन्द	4.9.06	—	7	

1	2	3	4	5	6
45.	डा० श्रीमती सुमन वर्मा, चिकित्सा अधिकारी, जिला जेल गुड़गांव	5.12.06	—	—	
46.	डा० डिम्पल यादव, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालू, कैथल	13.12.06	—	—	
47.	डा० विनोद शर्मा, चिकित्सा अधिकारी सामान्य हस्पताल, फतेहाबाद	6.3.07	—	—	
48.	डा० सुधीर गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी सामान्य स्वास्थ्य केन्द्र कालका (पंचकूला)	1.4.07	—	—	
49.	डा० लाल सिंह, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य स्वास्थ्य केन्द्र, नूंह	21.4.07	—	—	
50.	डा० महेन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुधोला, फरीदाबाद	10.5.07	—	—	
51.	डा० विनोद गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, सा० ह०, फतेहाबाद	28.5.07	—	—	
52.	डा० मनोज गर्ग, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य हस्पताल, टोहाना, फतेहाबाद	1.6.07	—	—	
53.	डा० श्रीमती श्वेता मौंगा, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य हस्पताल, बल्लबगढ़	8.6.07	—	—	
54.	डा० रमेश डूडी, चिकित्सा अधिकारी सामान्य हस्पताल, पानीपत	3.8.07	—	—	
55.	डा० ईला गर्ग, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहम्मदपुर अहीर, मेवात	—	14.11.05 से 8.7.06 9.7.06 से 31.1.08	चिकित्सा अवकाश-अर्जित अवकाश चिकित्सा आधार पर	
56.	डा० रमन दीप सिंह बराड़, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य स्वास्थ्य केन्द्र, औढा, सिरसा	—	1.4.07 से 30.9.08	असाधारण अवकाश	
57.	डा० कृष्ण कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य हस्पताल, भिवानी	—	1.3.07 से 23.6.08	अर्जित अवकाश	

[बहिन करतार देवी]

तालिका नं०-2

हरियाणा सिविल चिकित्सा अधिकारियों के नाम जो विदेश में अनुमति लेकर गये हुए हैं।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अनुमति के बाद की तिथि	जो कार्यवाही की गई
1.	डा० विजेन्द्र कुमार, सामान्य स्वास्थ्य केन्द्र, डीघल, झज्जर।	4.6.06	इस अधिकारी के विरुद्ध 25.10.07 को अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई थी लेकिन अधिकारी ने दिनांक 31.1.08 से त्याग पत्र दे दिया है त्याग पत्र स्वीकृत करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।
2.	डा० दया कृष्ण चहल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुटाना, सोनीपत	27.5.07	डा० दया कृष्ण चहल, चिकित्सा अधिकारी ने दिनांक 27.5.07 से 18.6.09 तक अवकाश बढ़ाने के बारे में आवेदन पत्र दिया हुआ है और वित्त विभाग हरियाणा द्वारा कुछ आपत्तियां उठाई गई है जिसके कारण मामला लम्बित है और आवश्यक सूचना विभाग से मंगवाई जा रही है।

तालिका नं०-3

हरियाणा सिविल चिकित्सा अधिकारियों के नाम जो विदेश में बिना अनुमति लेकर गये हुए हैं।

क्रम संख्या	चिकित्सा अधिकारी का नाम	जो कार्यवाही की गई
1	डा० सुनील कुमार बजाज, चिकित्सा अधिकारी, जरनल हस्पताल, टोहाना, फतेहाबाद	सरकार के पत्र क्रमांक 17/14-04-04HBI दिनांक 9.8.06 द्वारा नियम-7 के अधीन आरोप पत्र जारी किया जा चुका है और दिनांक 1.1.08 को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

Improvement of Electricity in District Mahendergarh.

122- Sh. Naresh Yadav : Will the Power Minister be pleased to state:—

(a) the total amount spent on the improvement of supply of electricity in district Mahendergarh during the period from2005 to 2007; and

(b) the details of old poles and obsolete wires replaced in the said district during the said period?

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला)

(क) श्रीमान, वर्ष 2005 से 2007 की अवधि के दौरान जिला महेन्द्रगढ़ में बिजली की आपूर्ति के सुधार करने पर 3625.29 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ख) वर्ष 2005 से 2007 की अवधि के दौरान जिला महेन्द्रगढ़ में बदले गए पुराने खम्बे तथा पुरानी तारों का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	बदली गई पुरानी तारें (कि०मी०)			बदले गए पुराने खम्बे
	एच०टी०	एल०टी०	योग	
2005-06	53	31	84	16 नं०
2006-07	74	43	117	40 नं०
2007-08	47	19	66	101 नं०

Officers of Haryana Veterinary Service on Leave

117. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state:—

(a) the names of officers of Haryana Veterinary Service of Animal Husbandry department alongwith the period and kind of leave absence who are on leave or absent for more than six months as on 1st March, 2008.

(b) the names of officers in (a) above who have gone abroad with prior permission of the competent authority and who are overstaying alongwith the action taken thereon?

(c) the names of officers in (a) above who proceeded abroad without prior permission of the competent authority alongwith the action taken thereon?

कृषि मन्त्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) :

(क) श्रीमान जी, हरियाणा पशु चिकित्सा सेवा के उन अधिकारियों के नाम तथा उनके अवकाश के विवरण की सूची अनुबन्ध 'क' पर है।

(ख) श्रीमान जी, हरियाणा पशु चिकित्सा सेवा के उन अधिकारियों, जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से विदेश गए हैं और अधिक समय से ठहरे हुए हैं, उनके विवरण की सूची उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही सहित अनुबन्ध 'ख' पर है।

(ग) श्रीमान जी, केवल एक अधिकारी डा० देवेन्द्र सिंह गोदारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण अनुमति के बिना विदेश गया है तथा 1.4.2004 से बिना अवकाश प्रार्थना पत्र दिए अनुपस्थित हैं। उसे नियम-7 के तहत आरोप पत्रित किया गया है तथा अनुशासनिक कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।

[सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा]

अनुबन्ध 'क'

क्र० स०	अधिकारी का नाम	अवकाश अवधि	अवकाश का प्रकार	क्या छुट्टी पर या 1.3.08 की अवधि अनुसार 6 महीने के अधिक समय से अनुपस्थित है
1	2	3	4	5
1.	डा० नरेन्द्र सिंह मान, उप निदेशक	4.9.06 से 15.9.06	अर्जित अवकाश	--
		18.9.06 से 17.10.2006	अर्जित अवकाश	अनुपस्थित
		17.10.06 से	-सम-	-सम-
		16.11.2006	-सम-	-सम-
		17.11.2006 से 16.11.09		
2.	डा० विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक	29.8.2006 से 30.4.2008	देय अवकाश	अवकाश पर
3.	डा० राजकुमार अरोड़ा	20.6.2002 से 31.12.2002	अर्जित अवकाश	अनुपस्थित
4.	डा० अमन सिंह मोर, पशु चिकित्सक	18.11.2003 से 14.5.2004	अर्जित अवकाश	अनुपस्थित
5.	डा० राजेश विदलान, पशु चिकित्सक	12.9.03 से 31.1.2004	अर्जित अवकाश	अनुपस्थित
6.	डा० बीर सिंह पशु चिकित्सक	7.8.2002 से 2.2.2003	अर्जित अवकाश	अनुपस्थित
7.	डा० बलजीत सिंह, पशु चिकित्सक	16.10.2002 18.10.2002	अर्जित अवकाश	अनुपस्थित
8.	डा० कुलदीप सिंह, पशु चिकित्सक	18.6.2006 से 2.7.2006	अर्जित अवकाश	अनुपस्थित
9.	डा० दलबीर सिंह, पशु चिकित्सक	--	ड्यूटी से अनुपस्थित 13.3.2001 से	अनुपस्थित
10.	डा० राजकुमार वर्मा, पशु चिकित्सक	--	-सम- 9.11.2003 से	अनुपस्थित
11.	डा० मनप्रीत कौर, पशु चिकित्सक	--	-सम- 16.10.2006 से	अनुपस्थित
12.	डा० शशि ढींगरा पशु चिकित्सक	--	-सम- 26.7.2002 से	अनुपस्थित
13.	डा० देवेन्द्र सिंह गोदारा पशु चिकित्सक	--	-सम- 1.4.2004 से	अनुपस्थित
14.	डा० पवन कुमार पशु चिकित्सक	19.3.2007 से 17.5.2007	अर्जित अवकाश	अनुपस्थित

अनुबन्ध 'ख'

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	समय अवधि जिसकी विदेश जाने की अनुमति ली गई	अधिक समय की अवधि	की गई कार्यवाही
1.	डा० नरेन्द्र सिह मान, उप निदेशक	4.9.06 से 15.9.06	16.9.2006 से अब तक	अधिकारी को नियम-7 के तहत आरोपित किया गया है। अनुशासनिक कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।
2.	डा० राजकुमार अरोड़ा पशु चिकित्सक	20.6.2002 से 31.12.2002	1.1.2003 से अब तक	अधिकारी को नियम-7 के तहत आरोपित किया गया है। अनुशासनिक कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।
3.	डा० अमन सिंह भोर, पशु चिकित्सक	18.11.2003 से 14.5.2004	15.5.2004 से अब तक	अधिकारी को नियम-7 के तहत आरोपित किया गया है। अनुशासनिक कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।
4.	डा० राजेश विदलान, पशु चिकित्सक	12.9.03 से 31.1.2004	1.2.04 से अब तक	अधिकारी को नियम-7 के तहत आरोपित किया गया है। अनुशासनिक कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।
5.	डा० बीर सिंह पशु चिकित्सक	7.8.2002 से 2.2.2003	3.2.2003 से अब तक	अधिकारी को नियम-7 के तहत आरोपित किया गया है। अनुशासनिक कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।

[सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा]

1	2	3	4	5
14.	डा० पवन कुमार पशु चिकित्सक	19.3.2007 से 17.5.2007	18.5.2007 से अब तक	छुट्टी में बढ़ोत्तरी का मामला सरकार के विचाराधीन है।

Quantity of Kerosene being distributed

123. Sh. Naresh Yadav : Will the Deputy Chief Minister is pleased to state:—

(a) the month wise total quantity of kerosene being distributed to the concumers by the Food and Supply Department in district Mahendergarh;

(b) the number and names of Government and non Government Agencies supplying kerosene in district Mahendergarh togetherwith the criteria for distributing the kerosene; and

(e) the rules and regulations for authorizing the depot holder in villages by the Department?

उप-मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन) : श्री मान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) महेन्द्रगढ़ जिले में खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 (2/2008 तक) के दौरान उपभोक्ताओं को प्रति मास वितरित की गई मिट्टी के तेल की मात्रा निम्न प्रकार से है:-

मास	मिट्टी तेल की जारी की गई मात्रा (किलो लीटरों में)
अप्रैल, 2007	660
मई, 2007	660
जून, 2007	660
जुलाई, 2007	684
अगस्त, 2007	684
सितम्बर, 2007	684
अक्तूबर, 2007	684

नवम्बर, 2007	684
दिसम्बर, 2007	684
जनवरी, 2008	684
फरवरी, 2008	540
कुल	**7308**

(ख) महेन्द्रगढ़ जिले में मिट्टी का तेल सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों नामतः भारतीय तेल निगम लिमिटिड तथा भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटिड द्वारा तेल टर्मिनल, रेवाड़ी के माध्यम से निम्नलिखित 4 मिट्टी के तेल के थोक विक्रेताओं द्वारा वितरित किया जा रहा है। यह थोक विक्रेता कम्पनियों के निजी लाईसैंस धारक है:-

1. मै० भारत ऑयल स्टोर, नारनौल (आई०ओ०सी०)
2. मै संतोष ऑयल कम्पनी, नारनौल (आई०ओ०सी०)
3. मै छन्नों देवी ऑयल कम्पनी, नारनौल (आई०ओ०सी०)
4. मै कर्ण ऑयल कम्पनी, सोहना स्थित नारनौल (बी०पी०सी०)

फरवरी, 2008 से पूर्व उन उपभोक्ताओं को, जिन के पास एल०पी०जी० की सुविधा नहीं है, को 5.5 लीटर मिट्टी के तेल की मात्रा प्रत्येक मास राशन कार्ड पर वितरित की जाती रही है। फरवरी, 2008 से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले राशन कार्डधारकों को 11 लीटर मिट्टी का तेल प्रति मास दिया जा रहा है। गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों, जिनमें पास एल०पी०जी० की सुविधा नहीं है, उन्हें 3 लीटर मिट्टी का तेल प्रत्येक मास दिया जा रहा है। इस प्रकार वितरण को तर्कसंगत बनाते हुए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अधिक मिट्टी का तेल जारी किया गया है, जिन्हें इस अनुदानित वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता है।

(ग) हरियाणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 2002 के अन्तर्गत सभी डिपोधारक पी०डी०एस० वस्तुएं जिनमें मिट्टी का तेल भी शामिल है, वितरित करने के लिए अधिकृत हैं।

Funding for Rinderpest Project

118. Sh Karan Singh Dalal : Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state:—

(a) whether the country including the state of Haryana has been declared Rinderpest free; if so, the date of such declaration;

[Sh. Karan Singh Dalal]

(b) whether the Central Government has stopped the funding of Rinderpest Project and its staff, if so, date of stoppage of funding by the Central Government; and;

(c) the details of the staff posted in Rinderpest project in the State and the justification of incurring expenses on the staff without work?

कृषि मन्त्री (सरदार एस०एस० चड्ढा) :-

(क) श्रीमानजी, देश को हरियाणा राज्य सहित 27/5/2004 से पशु प्लेग मुक्त घोषित किया जा चुका है।

(ख) जहाँ तक पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना के तहत भारत सरकार द्वारा टी०ए०, पी०ओ०एल०, प्रचार-प्रसार एवं अन्य कन्टीन्जैन्ट खर्चों के लिए निधिकरण किया जाता है, परन्तु अमले के वेतन आदि के भुगतान हेतु सहायता देना बन्द कर दिया है क्योंकि राज्यों द्वारा ही इस कार्यक्रम के लिए अमले आदि की व्यवस्था स्वयं अपने स्तर पर की जानी थी। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा 23-3-1998 को हिदायतें जारी की गई थी।

(ग) पशु प्लेग के लिए नियुक्त अमले का ब्यौरा निम्नलिखित है। यह न्यूनतम अमला क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा गाँवों में की गई जाँच-पड़ताल एवं दैनिक विवरणियों के निरीक्षण की सूचनाओं को संकलित करने हेतु रखा गया था। फिर भी, रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की हाल ही में 19-2-2007 को हुई बैठक में उप निदेशक (पशु प्लेग) के पद को उप निदेशक (पशु कल्याण एवं विस्तार) के रूप में तथा अन्य अमले को इस स्कीम से 2008-09 में डिप्लाय करने का अनुमोदन कर दिया गया है:—

1.	उप निदेशक	1
2.	पशु चिकित्सक	2
3.	सहायक	1
4.	आशु लिपिक	1
5.	लिपिक	2
6.	चालक	2
7.	साथी	1

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक कॉलिंग अटैंशन मोशन किडनी स्कैंडल इन हरियाणा के बारे में दिया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह गवर्नमैंट के पास कमैंट्स के लिए भेजा हुआ है।

सदन की कार्यवाही देखने के लिए एक समिति के गठन के मामले के संबंध अध्यक्ष महोदय का निर्णय :

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, I have given a Notice regarding constituting a Committee of the House in which at least two journalists of Press Gallery Committee should be included to watch that proper proceedings of the House are conducting instead of casting aspersions on each other. शून्य काल के दौरान मैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस सदन में चर्चा करना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Under which rule, you want to discuss this matter?

डा० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में बहुत ही लोकमहत्व के मुद्दे उठाये जाते हैं। अगर आप मुझे वह मुद्दे उठाने की अनुमति देंगे तो ठीक है नहीं तो धक्के से कहकर बाहर चला जाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Every action has its own reaction. रीऐक्शन किसी ऐक्शन की बदौलत है। क्या पता आपके द्वारा कहां कहां बबूल के बीज बोए पड़े हैं। (Noise and Interruptions). Indora Ji, please sit down. I am giving ruling in this regard. The notice given by Dr. Sushil Indora, MLA is not covered under any Rule of the Rules of Proceedure and Conduct of Business in the Haryana Lesiglative Assembly. The proceedings of the House are regulated in accordance with the Rule of Procedure of this House as well as established Parliamentary Practice and Convention. The allegations levelled in the notice that no important business was conducted in the House during discussion on Governor's Address and general discussion on Budget are incorrect and baseless. Hence, no such situation as alleged by the Hon'ble Member in the notice has arisen which necessitates the Constitution of any Committee.

डा० सुशील इंदौरा : एक ऐसी परम्परा है। (शोर एवं व्यवधान)

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जो बिजनेस ट्रांजैक्ट करना चाहिए था, जिन मुद्दों को सदन में लाया जाना चाहिए था, अध्यक्ष महोदय, उसके बजाये सच बात यह है कि इनके नेता यहां आकर केवल हाजरी लगाते हैं और हर रोज भाग जाते हैं। यह सबसे ज्वलंत मुद्दा सदन के समक्ष है। इनके नेता के द्वारा सदन में गलतबयानी की गई है। सबसे ज्वलंत मुद्दा किसान की लोन माफी को लेकर है। इस बारे में सदन की जो कमेटी बनी थी उसकी मीटिंग पिछले हफ्ते जो निर्धारित थी उस दिन वे भी 600 रुपये लेकर यहां से भाग गए और कल फिर भाग गए और कमेटी की मीटिंग में कमेटी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए जबकि सच बात यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा किसान की लोन माफी का मुद्दा था और सभी जानना चाहते थे कि कितना पैसा माफ हुआ है और कितना और माफ होगा। किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के किसान को राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने सर्वसम्मति से इस हाउस की कमेटी का गठन श्री मांगे राम गुप्ता जी की अध्यक्षता में किया था। कमेटी की पहली मीटिंग के दिन चौटाला जी आए, हाजरी लगाई, उसके बाद दो मिनट चेयर पर कुछ आक्षेप लगाए और भाग गए। कमेटी में बोल दिया कि मैं नहीं आ सकता।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

कल फिर आए, 600 रुपये की हाजरी लगाई और फिर भाग गए। आज फिर उनको कमेटी ने सम्मन किया हुआ है। इस बारे में आज के समाचार पत्रों में भी दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि आज मीटिंग में चौटाला जी आएं उसके बारे में वाद विवाद करें, तथ्य सामने लाएं। (शोर एवं व्यवधान) यह हरियाणा प्रदेश के किसान के लिए और गरीब के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है परन्तु इस मुद्दे पर इनकी कोई रुचि नहीं है। ये केवल आरोप प्रत्यारोप में पड़े रहते हैं या केवल मर्यादाओं, परम्पराओं और परिपाटियों का उल्लंघन करने के अलावा इनका और कोई कार्य नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यही कार्य डा० इंदौरा ने किया है इनकी पार्टी भी यही काम करेगी। इनकी पार्टी के नेता का भी यही लक्ष्य है। या तो ये माननीय सदस्य पर हमला करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उन पर आरोप-प्रत्यारोप करते हैं। आक्षेप लगाते हैं, इसके अलावा इनका और कोई कार्य नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने सबसे ज्यादा प्रजातांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया है।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। हमें भी अपनी बात करने का अवसर दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी बात कहने का मौका दीजिए। हमें यह भी बताया जाए कि गवर्नर ऐड्रेस पर कितनी चर्चा हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, हम एक अहम् मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। हमारी बात सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस बारे में मैंने रूलिंग दे दी है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर इन्दौरा और इनके साथियों को दो मुद्दों को लेकर चिन्ता हो रही है। एक तो जो आपने श्री फूलचन्द मुलाना जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जो पिछली सरकार के समय में सारी सम्पत्तियां जो देवीलाल ट्रस्ट को दे दी गई थी और जिनको बेच दी गई थी। उस कमेटी के माध्यम से पिछली सरकार का सारा तामझाम सामने आने वाला है। दूसरी कमेटी आपने श्री मांगेराम गुप्ता जी की अध्यक्षता में बनाई है जिसमें लोन वेवर की सारी फिगर्ज आ जायेगी। क्यों चौटाला जी दुम दबाकर भाग रहे हैं सदन से, क्यों नहीं आते कमेटी के सामने, क्यों नहीं बताते कमेटी को, दो बार कमेटी को दरखास्त दे कर भाग गये। क्या दिक्कत है उनको कमेटी के सामने आने में। कमेटी के सामने आयें और अपनी पूरी बात कहें। क्या सच है और क्या झूठ है उसका पता चल जायेगा। श्री मांगेराम गुप्ता जी की अध्यक्षता में बनी कमेटी के सामने दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जायेगा। इनको घबराहट उन दो कमेटियों की हुई है जो आपने बनाई हैं। दूसरी जो देवीलाल ट्रस्ट को जो सम्पत्ति दी गई गई हैं और देवीलाल ट्रस्ट द्वारा जो नंगी लूट की गई है उसके बारे में जो कमेटी बनी है-----

वाक-आउट

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, हमारी बात सुनिए। मैं कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, एक जरूरी एनाउंसमैंट है। I request you please take your seat.

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, आप आश्वासन दीजिए और सदन की कमेटी बनाईये।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में मैंने रूलिंग दे दी है।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, हमारी बात सदन के अन्दर सुनी नहीं जा रही है इसलिए हम सदन से वाकआउट कर रहे हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी इण्डियन नैशनल लोकदल के सदस्य सदन से वाकआउट कर गये)

घोषणा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that Shri Bhajan Lal who had been elected from 79-Adampur assembly constituency has been disqualified from the membership of Haryana Vidhan Sabha under 10th Schedule to the Constitution of India and the rules framed thereunder with immediate effect i.e. 25th March, 2008 and consequently he ceased to be member of the Haryana Vidhan Sabha and his seat has fallen vacant in terms of Article 190(3) of the Constitution of India.

शिक्षा मन्त्री (श्री मांगेराम गुप्ता) : स्पीकर सर, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी दोनों की हाउस में दी गई स्पीच के स्टेटमैंट के फिगर्ज डिफर कर रहे थे। इस बारे में आपने मेरी अध्यक्षता में हाउस की एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की हम दो-तीन मीटिंग्ज कर चुके हैं। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हाउस में तो आ जाते हैं लेकिन कमेटी की मीटिंग में नही आते। स्पीकर सर, इससे पहले कि मैं उस कमेटी के बारे में कुछ चर्चा करूं उससे पहले एक अहम मसले को आपके माध्यम से सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं। कल श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के सुपुत्र श्री अजय सिंह चौटाला जी ने एक प्रैस कान्फ्रैंस बुलाकर यह कहा है। **(शोर एवं व्यवधान)**

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ये किस रूल के तहत यह मुद्दा उठा रहे हैं इस बारे में हम चेयर की रूलिंग चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Mange Ram Gupta : It is my business. It is my right to speak. Why are you making objections, (Interruptions)

Mr. Speaker : A Minister can give reply any time. (Interruptions)

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हम बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हमें परम्पराओं का हवाला दिया जाता है लेकिन सत्ता पक्ष वाले परम्पराओं को ध्यान में रखें या न रखें उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, प्रैस के माध्यम से सरकार के ऊपर और मंत्रियों के ऊपर अननैसैसरी आक्षेप लगाए जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हम बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हमारे माइक के स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं लेकिन सत्ता पक्ष वाले बोलना न भी चाहें तो भी उनके माइक आन कर दिए जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Minister is giving the reply. Please listen the reply.

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने प्रैस कांफ्रैंस में यह कहा कि हरियाणा सरकार ने जो नायब तहसीलदार लगाने हैं उसमें मंत्रियों और मुख्यमंत्री के ये-ये रिश्तेदार लगाए जाएंगे। इन्होंने सरकार के ऊपर इतना बड़ा आक्षेप लगा दिया। उस लिस्ट में इन्होंने मेरे रिश्तेदार का नाम दिया है इसलिए मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। इस लिस्ट में इन्होंने नाम दिया है कि मांगेराम गुप्ता का रिश्तेदार विक्रम सिंगला सुपुत्र श्री सतीश कुमार, रोल नम्बर 5356। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस में जो भी बात करता हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं और मैं हाउस का समय खराब नहीं करता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, बाहर लोग भौंकते रहते हैं आप किसी की क्या परवाह करते हो। (शोर एवं व्यवधान)

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received Leave of Absence dated 25th March, 2008 from Shri Chander Mohan, Deputy Chief Minister which reads as under:-

"In continuation of my earlier request dated 10.3.2008, I would like to submit that as I am still in shock and not keeping good health, I am not be in a position to attend the Vidhan Sabha Session even on 26th to 28 March, 2008.

You are requested to kindly allow me necessary exemption."

Question is—

That Leave of Absence be granted to Shri Chander Mohan, Deputy Chief Minister to remain absent from the sitting of the House from 26th to 28th March, 2008.

Voices: Yes, Yes,

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received Leave of Absence dated 25th March, 2008 from Maj. Nirpender Singh Sangwan, M.L.A., which reads as under:—

'Respected Dr. Raghuvir Singh Ji,

I am to inform you that I will be out of station on 26th March, 2008 on account of some personal work. I am to request you to please condone my absence in the House on 26th March, 2008."

Question is—

That Leave of Absence be granted to Maj. Nirpender Singh Sangwan, M.L.A. to remain absent from the sitting of the House on 26th March, 2008.

Voices : Yes, yes.

The motion was carried

वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr Speaker : Hon'ble Members, now general discussion on the Budget Estimates for the year 2008-2009 will be resumed.

Hon'ble Members, almost all the members have spoken either on the Budget or on the Governor's Address. So, I would request the Hon'ble Members that please do not repeat the topics or subjects, as the matters have already been discussed on the floor of the House. Please conclude your speech within 10 minutes.

श्री फूलचंद मुलाना (मुलाना, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी सदस्यों ने बजट की प्रशंसा की है। वाकई में प्रशंसनीय बजट है जिसमें प्रदेश के सभी वर्गों के हितों के लिए कदम उठाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने 6650 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं इनको भी सरकार ने बहुत कुछ दिया है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे कर्मचारी और अधिकारी दफ्तरों में और फील्ड में काम करके जनता की सेवा करते हैं। मैं चाहूंगा कि उनका टी०ए०, डी०ए०, बढ़ाना चाहिए और हाउस रैंट के लिए सलैब सिस्टम नहीं होना चाहिए और हाउस रैंट बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ-साथ मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कर्मचारियों के मैडीकल एलाउंस, हाउस एलाउंस और कनवेंस एलाउंस आदि बढ़ाये जायें। अध्यक्ष महोदय, जिस समय पांच रुपये लीटर पैट्रोल था उस समय 15 रुपये कनवेंस एलाउंस दिया जाता था और आज पैट्रोल 47 रुपये लीटर हो गया है इसलिए कनवेंस एलाउंस भी बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से समाज में दूसरे वर्ग हैं उसी तरह से कर्मचारी भी हमारा एक पार्ट हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जायें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पे कमीशन की रिपोर्ट आ गई है उस पर सरकार विचार कर रही है। हमारी पूरी-पूरी कोशिश है कि कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जायें।

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, समय की कमी की वजह से मैं शोर्ट में अपनी बात करूंगा। कई माननीय सदस्य तो एक-एक घंटे बोले हैं लेकिन मुझे दस मिनट का समय दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2008-09 के बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। Member after Member praises the Govt. very profusely. इसलिए मैं उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। वाकई में बजट बहुत अच्छा है और सरकार ने पिछले तीन साल में बहुत अच्छे सराहनीय कार्य किए हैं। समय की कमी की वजह से जो पाबंदी अध्यक्ष महोदय, आपने लगाई है उसको देखते हुए मैं बहुत सी बातों को रिपीट नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में प्लान बजट 6650 करोड़ रुपये का है और नॉन प्लान बजट 19770 करोड़ रुपये का है। नॉन प्लान बजट प्लान बजट से तकरीबन तीन गुणा ज्यादा है। मैं पहले भी यही बात कह चुका हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से तथा वित्तमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक दर्जन के करीब महकमें ऐसे हैं जो नीचे से ऊपर तक रैडूडैंट हो चुके हैं। उनको सिवाय लोगों के काम में रूकावट पैदा

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

करना, देरी करना और अनियमितताएं करने के अलावा कोई काम नहीं है। इस तरह के महकमों को सरकार खत्म करने पर विचार करें। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन बनाया है। सरकार ने घोषणा की है कि छठे पे कमीशन की सिफारिशें प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे जो डाक्टर हैं वे प्रदेश से प्लायन कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल में डाक्टर्ज के पे-स्केल ज्यादा हैं इसलिए हमारे यहां डॉक्टरों का बहुत अभाव है। इसकी वजह से जनता को बहुत तकलीफ है। स्पैशली डॉक्टरों के और जो प्राईमरी स्कूलों में टीचर्ज़ हैं, वे डॉक्टर और टीचर्ज अच्छे हैं इसलिए उनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, एट पार होनी चाहिए। एक वक्त वह था जब हरियाणा में दूसरी जगह से डॉक्टर आते थे क्योंकि हमारे यहां पर स्केल बहुत अच्छे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू से ही यह कहना चाहूंगा कि बजट में स्वास्थ्य के लिए और स्पोर्टस के लिए बहुत ही कम रुपये रखे गये हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए 130 करोड़ रुपये रखे गये हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि इन दोनों महकमों हैल्थ और स्पोर्टस डिपार्टमैंट के जो प्रोग्राम हैं उनके लिए बहुत ज्यादा रुपयों की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि वित्तमंत्री जी इसकी ओर ध्यान देकर इसको ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक बार फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी और यू०पी०ए० की गवर्नमैंट का किसानों के कर्ज़े माफ करने के लिए आभार प्रकट करता हूं लेकिन इसके साथ ही मैं भारत सरकार से यह भी मांग करता हूं कि छोटे किसानों के साथ-साथ खेती से जुड़े हुए जो भूमिहीन लोग हैं जो खेती करते हैं? स्पीकर सर, इसमें बहुत से क्लासिज़ हैं और वे एग्रीकल्चर के एलाईड प्रोफैशन भी हैं, उदाहरण के तौर पर मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन और गांव के जो आर्टीजनज़ हैं चाहे वह मिस्त्री का काम करते हैं, चाहे लोहे का काम करते हैं, चाहे वे किसी तरह का भी काम करते हैं इन सबके कर्जे भी माफ होने बहुत जरूरी है। ये छोटे किसानों से भी निचले दर्जे के लोग हैं और ये सभी लोग खेती बाड़ी में ही मदद करने लग रहे हैं। इनका जीवन भी किसान और उसकी खेती के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इनके कर्जे भी माफ किये जाने चाहिएं जो कि बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा मैं यह भी दरख्वास्त करूंगा कि पजावा की जो ज़मीन है वह हमेशा से कुम्हार बिरादरी के लोगों की ही परम्परागत ज़मीन रही है। वही लोग उस पर काम करते थे। चाहे शुरू में गांव के द्वारा उनको वह ज़मीनें दी गई हो। लेकिन हज़ारों सालों से उस पर कब्ज़ा है। बहुत सी जगहों पर पंचायत ने या दूसरे लोगों द्वारा इनकी जमीनों को छीन लिया गया है। उनको दोबारा उनकी सारी जमीनें दिलवाई जानी चाहिएं। इसी प्रकार से मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा भैंस, गाय, बैल आदि लगभग सभी पशुओं के बीमा के लिए प्रावधान किया गया है लेकिन जो पशु कुम्हारों द्वारा रखे जाते हैं जैसे गधे और खच्चर, सरकार द्वारा इनके बीमा का कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। इनको भी इस पशु बीमा स्कीम में शामिल करना चाहिए। इनको छोड़ने की भी कोई वजह दिखाई नहीं देती। ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि इनका बीमा न करवाया जाये। ये बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि छोटा-मोटा सामान उठाने का सबसे ज्यादा काम ये दोनों जानवर ही करते हैं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब क्या इस प्रकार की कोई डिमाण्ड आई है ?

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, इस प्रकार की डिमाण्ड फील्ड से बहुत आती है। यहां पर तो उन बेचारों को कौन अन्दर आने देगा। स्पीकर सर, यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो दिहाड़ीदार मज़दूर है उनकी वेजिज़ भी बढ़ाई जानी चाहिएं और इस वक्त हरियाणा सरकार ने मिनीमम वेजिज़ 3500 रुपये किए हैं मैं कहूंगा कि यह मिनीमम वेजिज़ कम से कम पांच हजार रुपये होनी चाहिए क्योंकि सबकी वेजिज़ बढ़ रही है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं तो उन गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। जो भूमिहीन लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बीमा की जो योजना सरकार द्वारा बनाई गई है यह बहुत अच्छी है लेकिन इस समय वह प्रदेश के कुछ जिलों में है। यह योजना पूरे प्रान्त में होनी चाहिए। भारत सरकार इसमें सबस्टांशियल अमाउंट देती है। इस बारे में स्टेट गवर्नमैंट को भारत सरकार को कहना चाहिए कि यह योजना हमारी पूरी स्टेट में लागू होनी चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में यहां के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शहर में जो अनआर्गेनाईज़्ड सैक्टर है जैसे रेहड़ी वाले हैं, तपड़ी वाले हैं, छाबा वाले हैं और खोखे वाले हैं ऐसे बहुत से लोग हैं न तो इनको कोई पक्का स्थान मिला हुआ है जहां पर ये अपना रोजगार कर सकें। इन्हें बार-बार म्युनिसिपल कमेटी के कर्मचारियों और पुलिस वालों द्वारा परेशान किया जाता है इसलिए इनको कहीं न कहीं पर रोजगार करने के लिए पक्का स्थान दिया जाये। इसके साथ ही इनकी सेहत के बीमा की योजना भी लागू की जाये और इनके बच्चों की पढ़ाई का भी प्रबन्ध किया जाये क्योंकि यह बहुत ही गरीब तबका है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों में 3-4 साल से मानसून ने अपना रास्ता बदल दिया हैं इस बारे में मैंने एक सवाल भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से पूछा था और उसमें भी इस बारे में चर्चा की थी। मैं सरकार को और स्पेशली मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि इस इश्यू पर सीरियसली ध्यान देकर किसानों को, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों की, मौसम विभाग के लोगों की और एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की इनकी सबकी मीटिंग बुलाकर ये बात डिसकस करनी चाहिए और नेचर में जो मेजर चेंज आया है उससे मानसून ग्रिफ्ट करके गुजरात और राजस्थान की तरफ चला गया है और पिछले तीन-चार साल से हरियाणा और पंजाब में बारिश नहीं हुई। इस बार तो सर्दियों की बारिश भी नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस पर बहुत विचार करके कोई फैसला करने की जरूरत है। किसानों की दो-तीन दिक्कतें हैं, भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने बहुत सी दिक्कतें दूर भी की हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इस वक्त बड़ी प्रोब्लम है किसानों के इनपुट्स की, जिनको खेती के काम में लाया जाता है। सबसे पहली दिक्कत है डीजल की। डीजल आजकल नकली मिल रहा है। किसान 4-5 लाख रुपये लगा कर ट्रैक्टर खरीदता है और नकली डीजल के कारण 6 महीने में ही उसका इंजन बैठ जाता है और उसको उस पर 50 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। इससे किसानों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और वह दिवालिया होता जा रहा है। बीज भी नकली मिलते हैं, खाद भी नकली मिलती है और कीड़े मारने वाली दवाईयाँ भी नकली मिलती हैं जिनमें दुकानदार बेइंतहा मुनाफा कमाते हैं। किसानों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही उनके रेट्स के बारे में जानकारी है जिससे किसानों की फसलें भी नष्ट हो रही हैं और उन्हें घाटा भी उठाना पड़ रहा है। इन मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। इस कानून को बदल कर पहली बार पकड़े जाने पर कम से कम 10 साल की सजा और दूसरी बार उम्रकैद की सजा होनी चाहिए तथा इनके लाईसैंस भी रद्द किये जाने चाहिएं ताकि किसानों को लुटने से बचाया जा सके। इस

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

वक्त कानून मुर्दा है और जो महकमे की जिम्मेदारी है चैकिंग करने की, उसमें कोताही बरती जा रही है और कोई चैक नहीं करता। सभी जगह मिलीभगत है और लोग बड़ा भारी लाभ उठा रहे हैं। दूसरी बात मैं किसानों को दिये जाने वाले ऋण के बारे में कहना चाहता हूँ। भारत सरकार ने 2 साल पहले किसानों के लिए ब्याज की दर 7 परसैंट की थी, उस समय सभी ने खुले दिल से उसका स्वागत किया था। हरियाणा सरकार ने भी बहुत सी रियायतें किसानों को दी हैं। 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों के कई हजार करोड़ रुपये तक के ब्याज माफ किये हैं और किसानों ने उनका स्वागत भी किया है। असली चीज जो है वह ब्याज है जो लोंग टर्म पर किसानों को फायदा कर सकता है लेकिन मैं समझता हूँ कि 7 परसैंट ब्याज की दर अधिक है। मैं मांग करता हूँ कि हमें भारत सरकार को कहना चाहिए कि इसको 7 परसैंट से 5 परसैंट किया जाना चाहिए और जो भूमिहीन गरीब लोग हैं उनको 3 परसैंट पर लोन मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग और भी दूसरे महकमे हैं मैं सबका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगा। इन महकमों द्वारा किसान को पशुपालन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती, उनको कोई मदद नहीं दे पा रहे हैं और इसमें बजट भी बहुत कम है। इस बारे में मेरा कहना है कि हर जिले में कम से कम एक पशुपालन संस्थान या कॉलेज सरकार को जरूर खोलना चाहिए। हर जिले में स्पोर्टस का एक कॉलेज जरूर होना चाहिए। हमारे गाँवों में हजारों लड़के-लड़कियाँ हैं, अगर उनको कोच बनायेंगे तो पूरे देश की सेवा कर सकते हैं। उससे रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश का नाम भी ऊंचा होगा। मगर अभी भी पशुपालन में बहुत कुछ करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी आप वाइंड-अप करें।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे पांच मिनट का समय और दे दीजिए मैं अपनी बात को कन्कलूड करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार सरकार ने गेहूं की कीमत तय की है उसी प्रकार से जीरी के रेट भी तय किये जाने चाहिएं। मैं यह भी कहूंगा कि आगे आने वाली फसल से पहले सरकार को जीरी के रेट कम से कम 1000 रुपये प्रति क्विंटल तय करने चाहिएं ताकि जीरी बोने वाले किसान उत्साहित हों और किसानों को उसका फायदा हो सके। इसी प्रकार से बी०पी०एल० के बारे में जो भारत सरकार ने क्राईटेरिया बनाया है यह बहुत गलत है, उसमें भी बदलाव की जरूरत है। बिहार और उड़ीसा की आज जो स्थिति है वह पंजाब और हरियाणा में नहीं है। जो क्राईटेरिया बनाया गया है उसमें तो कोई कवर होता ही नहीं है। जिसके पास पक्का मकान है, वह जिसके पास बिजली की फिटिंग है, और वह जिसके पास टेलीविजन है वह भी उस स्कीम में कवर नहीं हो सकता। जो भी भूमिहीन हैं और जिनके पास रोजगार नहीं है उन सबको इसमें शामिल करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं शहरी विकास के बारे में भी कहना चाहता हूँ। बाकी शहरों के लिए 240 करोड़ रुपये टोटल दिये गये हैं लेकिन अकेले फरीदाबाद के लिए 1203 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

11.00 बजे हरियाणा के शहरों में से क्या फरीदाबाद देश का ऐसा सितारा शहर है जिसके बिना काम नहीं चलता। (विघ्न) जिला फरीदाबाद की मदद करनी चाहिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि शहरों की तरक्की के लिए, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए, उनमें काम करने के लिए बहुत सा रुपया चाहिए। शहरों में आमूल-चूल परिवर्तन करने

की लोड़ है। गांव में जितने भी स्कूल हैं या आर्टस के कॉलेजिज हैं उनको प्रोफैशनल स्कूलों में बदलना चाहिए। जिन लोगों ने आर्टस पढ़ना है या अकेली साईंस पढ़नी हैं वे यूनिवर्सिटी में जा कर पढ़ सकते हैं क्योंकि गांव के लड़के शहरों के लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि बड़ी-बड़ी कम्पनीज़ और मल्टीपलैक्स हैं वे हर छोटे से छोटे शहर में स्टोर खोलने जा रही है। अगर यही सिलसिला चलता रहा और सरकार ने उसको बन्द नहीं किया तो थोड़े दिन में परचून और रिटेल की दुकानें करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कोई सब्जी की दुकान करता है, कोई किसी जगह पर जूते बेचता है या और कोई चीज बेचता है, या कोई रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचता है ये सब लोग बेकार हो जाएंगे। जो लोग और कम्पनियां बड़े-बड़े स्टोर बना रहे हैं वे अरबों-खरबों पति लोग हैं। स्पीकर सर, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि यदि रिलायंस और दूसरी ऐसी कम्पनीज यह काम करने लग जाएंगी तो छोटे दुकानदारों का क्या होगा। स्पीकर सर, आठ करोड़ लोग जो परचून की दुकानें करते हैं वे कहां जाएंगे। ये गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया के फिगर्ज हैं इनके मुताबिक आठ करोड़ लोगों का भविष्य बिल्कुल डार्क हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले सरकार को इसके लिए पूरा ब्यौरा लेना चाहिए कि यह कितने लोग हैं। बड़े-बड़े स्टोर और मल्टीनैशनल कम्पनीज के मुकाबले में जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं या जो छोटे काम करने वाले लोग हैं जैसे छाबड़ी और रेहड़ी वाले लोग हैं या जो दूसरे छोटे काम करने वाले लोग हैं वे कहां जाएंगे? इन लोगों को समायोजित करने के लिए सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए। विदेशों में भी जब बड़े स्टोर आए थे तो उन्होंने भी इस बात की योजना बनाई थी लेकिन हमारी सरकार शायद अभी इस बारे में विचार नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, अब आप कन्कलूड करें।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की चार बातें जल्दी-जल्दी कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। स्पीकर सर, मुख्य मन्त्री जी और नहरी मन्त्री जी इस समय सदन में मौजूद नहीं है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनते ही उन्होंने यह कहा था कि पूरे हरियाणा में पानी का बंटवारा समानता से करेंगे। पानी का बराबर बंटवारा करेंगे। यह बड़ी अच्छी बात है और हम इस बात का स्वागत और समर्थन करते हैं। पूरे हरियाणा में अगर कोई एक जिला है जिसके साथ बेइन्साफी हो रही है वह कैथल जिला है और समय-समय पर मैं उसकी तरफ बार-बार ध्यान दिलवाता रहा हूं। स्पीकर सर, पूरे हरियाणा में वाटर एलाउंस 2.4 है जबकि कैथल जिल में 1.9 वाटर एलाउंस है। इस जिले को आपकी स्पोर्ट की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कैथल जिला जिसमें पैडी और व्हीट की कल्टीवेशन होती है इसलिए सबसे ज्यादा पानी उनको चाहिए। पूरे हरियाणा में वाटर अलाउंस 2.4 है और हमारे यहां यह 1.9 है। स्पीकर सर, यह बहुत पुरानी बात है जो कभी हुई होगी। इस सारे इलाके में जंगल था खेती की जमीन नहीं थी लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है अब जंगल नहीं है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जहां सारे हरियाणा में इन्साफ की बात कर रहे हैं तो कैथल से बेइन्साफी क्यों ? कैथल का वाटर अलाउंस भी 2.4 किया जाए। स्पीकर सर, मैं एक बात कहूंगा कि कैथल में इस सरकार ने पिछले साल बिल्कुल एक नई किस्म का कॉलेज खोला है माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इसका उदघाटन किया था और वहां पर क्लासिज शुरू करवाई हैं। स्पीकर सर, यह एक प्रोफैशनल कॉलेज है इसमें न तो आर्टस की क्लासिज हैं

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]
और न प्योर सांईस की क्लासिज़ हैं। यह कॉलेज पूरे हरियाणा में एक मॉडल है। स्पीकर सर, पीछे जो कमिश्नर एजुकेशन थे उन्होंने यह बात कही थी कि हम चाहेंगे कि इसी तरह के कॉलेजिज पूरे हरियाणा में खोलें और पहले वाले कॉलेजिज को बन्द कर दें। इस कॉलेज के लिए हमने 12 एकड़ जमीन मुफ्त दी है। यह जमीन दस करोड़ रुपये की है और शहर के नजदीक मेन रोड के पास है। यह जमीन सरकार के नाम हो चुकी है और इसका सब कुछ हो चुका है। इस कॉलेज में स्कूल के कुछ कमरे हैं, इसकी अपनी लैबोरेट्री भी चाहिए और भी चीजें चाहिएं। वहां कॉलेज की बिल्डिंग इस साल से बनानी शुरू करेंगे और जल्दी यह बिल्डिंग बननी चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, अब आप कन्कलूड करें।

श्री एस० एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं एक मिनट में कन्कलूड कर दूंगा क्योंकि मैं अपने हल्के की कुछ मांग रखना चाहता हूं वैसे तो मैं अपने बारे में कुछ कहता भी नहीं हूं। कैथल में दो सड़कें ऐसी हैं जिनका जीर्णोद्वार करने की जरूरत है। एक सड़क जो पेहवा चौक से करनाल बाईपास तक है और एक सड़क बिजली घर से सिविल स्टेशन तक है जो कि मन्जूर हो चुकी है और इनका सब कुछ हो चुका है सरकार को इसके लिए केवल पैसा देना है। स्पीकर सर, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सड़कों के लिए पैसा दे कर जल्दी इनको बनवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहूंगा कि मिल्क प्लांट के लिए 10 साल पहले किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी। लेकिन आज भी यह मिल्क प्लांट नहीं बना है, उसको भी जल्दी से बनवाने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में बहुत पशुधन है। मिल्क प्लांट नहीं बनने की वजह से वहां पर लोगों को सस्ते दामों पर दूध बेचना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं टैक्नीकल एजुकेशन की बात करना चाहता हूं। हमारे कैथल में एक टैक्नीकल इन्स्टीच्यूट भी बनाने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक ट्रांसपोर्ट कम्पलैक्स हुडा ने बनाया है और उसको डिवैल्प भी कर दिया है। वहां पर एक हफ्ते पहले ओपन ऑक्शन की गई थी। मेरा इस बारे में यह कहना है कि जिस तरह से करनाल और दूसरे शहरों में जो छोटे दुकानदार हैं और दूसरे हैं उनके लिए पहले ऑक्शन की गई थी और बाद में ओपन ऑक्शन की गई थी। क्या हमारे यहां पर भी इसी तरह से ऑक्शन करवाएंगे ? धन्यवाद!

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय वित्तमंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट में जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा के किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, मजदूर भाईयों के लिए, सभी वर्गों के लिए तथा शहरों और देहातों के लिए वित्तीय प्रबन्धन किए हैं, पैसे का इन्तजाम किया है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और वित्तमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि किस तरीके से पिछली सरकार के वक्त में हरियाणा प्रदेश का बजट पेश किया जाता था, उसकी बदहाली सदन में रखी जाती थी। उसमें पैसों की मारा मारी रहती थी। पिछली सरकार जो श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की थी, किस तरह से उनकी गलत नीतियों को लागू किया गया था और यहां से उद्योगधन्धों को प्लायन करना पड़ा था। उस वक्त दुकानदारी के उत्पीड़न का काम भी किया गया था। जिस वजह से सारे प्रदेश में हा-हाकार मची रहती थी। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने सही प्रोग्राम देकर आज

लोगों का सरकार के ऊपर भरोसा बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय, यू०पी०ए० की सरकार ने किसानों के 60,000 करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए हैं इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्तमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज प्रदेश के अन्दर एक सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न है, आज प्रदेश के लोगों को बहुत राहत दी गई है जिसकी वजह से भी प्रदेश के खजाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, पिछली विधान सभा में भी हमने यह मांग रखी थी कि कमजोर वर्ग जो भूमिहीन है उनके बारे में भी मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब किसान अपनी जमीन गिरवी रखकर बैंकों से कर्ज लेता है तो उनको डेढ़ प्रतिशत स्टैंप डयूटी देनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब में वे सारी डयूटीज माफ हैं तथा और प्रदेशों में भी वह स्टैंप डयूटी माफ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जहां आप सभी वर्गों को फायदा देने जा रहे हैं, अगर हरियाणा में मोर्टगेज करते वक्त स्टैंप डयूटी नहीं लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा और मैं इनको धन्यवाद करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज इसकी सीमा है लेकिन इसकी सीमा भी नहीं होनी चाहिए कि कितने से कितने लगा दिए। कोई भी किसान अनलिमिटेड कितना भी कर्ज ले, अगर वह अपनी जमीन गिरवी रखेगा तो उसके ऊपर स्टैम्प डयूटी का छुटकारा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ऐड-वोलरैम कोर्ट फीस है उसके पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ में अलग अलग मापदण्ड हैं। हरियाणा में यह चण्डीगढ़ और पंजाब से तीन से चार गुणा ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, जितने मुकदमें हाई कोर्ट में डलते हैं उनमें वकील मुविक्कलो से फीस ले लेते हैं लेकिन फीस तो वह उनसे हरियाणा के रेट वाली लेते हैं जो हाई कोर्ट में वे दावा करते हैं वह चण्डीगढ़ और पंजाब की तर्ज पर करते हैं। जो अभिभावक हैं उनकी जेब से पैसा तो चला जाता है लेकिन सरकार को उसका फायदा नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐड-वोलरैम कोर्ट फीस को भी चण्डीगढ़ और पंजाब की तर्ज पर माफ करके लोगों को राहत प्रदान करें ताकि मनी शूटस पर लोगों को राहत मिले। इसी तरह से जो सैल्फ ऐक्वायर्ड प्रोपर्टी है जिसको लोग अपने जीवनकाल में अपने खून पसीने की कमाई से खरीदते हैं तो उनको यह अधिकार होना चाहिए कि जैसे एनसैसर्टल प्रोपर्टी को 15 रुपये के स्टैम्प पेपर पर अपने बच्चों को या जिनको आप देना चाहते हैं उनको देने का प्रावधान हरियाणा के अंदर है। स्पीकर साहब, एनसैसर्टल प्रोपर्टी को तो हम 15 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन जो प्रोपर्टी एनसैसर्टल नहीं है और जो प्रोपर्टी एक आदमी ने अपने जीवनकाल में खरीदी है उसको अगर हमने अपने बच्चों के नाम करना है तो उसके ऊपर हमें स्टैम्प डयूटी लगानी पड़ती है। इससे गांवों में बहुत विपरीत असर पड़ता है, परिवारों में झगड़े होते हैं लोग अपने बजुर्गों के इंतकाल होने का इंतजार करते रहते हैं कि अगर उनका इंतकाल हो जाएगा, वे गुजर जाएंगे तो यह जायदाद हमें मिलेगी और हमें स्टैम्प डयूटी नहीं देनी पड़ेगी। स्पीकर सर, इस बारे में मैंने विधान सभा में भी एक सवाल लगाया था और उस वक्त के रैवेन्यू मिनिस्टर ने इस बात को माना भी था कि इससे कोई ज्यादा सरकार के खजाने की कमाई नहीं है उल्टे जो झगड़े प्रदेश में माँ बाप की जायदाद को लेकर बढ़ते हैं उन झगड़ों को समाप्त किया जा सकता है। सर, अपने जीवन काल में ही अपने हाथों की कमाई हुई जायदाद को कोई भी आदमी को अपने बच्चों के नाम पर 15 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ही ट्रांसफर करने का अगर अधिकारी बनता है तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि गिफ्ट डीड के जरिए जो यह रिलीज करने की व्यवस्था है जिस पर तीन परसैंट स्टैम्प डयूटी लगती है इसको समाप्त

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

किया जाए और 15 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर ही इसकी भी इजाजत दी जाए। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी मेरा निवेदन है क्योंकि यह बहुत बड़ी राहत प्रदेश के लोगों के लिए होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बजट में पेज 24 पर पैरा 39 में इन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया है और ऐग्रीकल्चर और ऐलाइड एक्टिविटीज की स्कीम लांच की है। सर, स्कीम तो लांच की गई है लेकिन उनके लिए उन्होंने पैसे का इंतजाम नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि और पशुधन को जब तक इकट्ठा करके आप आगे उनको नहीं बढ़ाएंगे, उनको साधन सम्पन्न नहीं बनाया जाएगा तब तक हरियाणा के किसानों का और खासकर बेरोजगार बच्चों का भला नहीं होगा इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में भी सरकार इंतजाम करे। इसी तरह से मुर्रा भैंसों के विकास के लिए जो एक परियोजना हरियाणा सरकार ने बनायी थी जिसकी केन्द्र सरकार में कुछ रुकावट लगी थी। मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर केन्द्र की सरकार उसमें कोई राहत नहीं देती है तो हरियाणा सरकार अपनी तरफ से इसमें राहत प्रदान करे और मुर्रा भैंसों को बढ़ावा देने के लिए कोई न कोई नयी स्कीम फिर से अपनी तरफ से चलाए। इसी तरह से शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। पहले लोग सरकारी स्कूलों की पढ़ाई पर विश्वास नहीं किया करते थे लेकिन अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था ठीक की गयी है, अतिथि अध्यापकों को लगाया गया है और सरकारी स्कूलों में पढ़ने लिखने का तरीका ठीक किया गया है। स्पीकर सर, अतिथि अध्यापकों के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को इनके बारे में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए जिससे हमारे इन बच्चों को प्रोत्साहन मिल सकें और इनकी हौसला अफजाई हो सके तथा टैक्नीकल ऐजुकेशन के साथ साथ शिक्षा को भी बढ़ावा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हायर ऐजुकेशन के रिस्ट्रक्चर करने का भी जो एक प्रोग्राम बनाया है वह भी बहुत अच्छा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जो रिस्ट्रक्चर ऐजुकेशन सिस्टम का कर रहे हैं तो शिक्षा विभाग को भी चाहिए कि कम से कम जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारे एक्सपर्टस हैं उनको बुलाकर पूछें कि हम हरियाणा प्रदेश में एक नयी व्यवस्था देने जा रहे हैं यह व्यवस्था लोगों का भला करेगी या नहीं करेगी। इसे लागू करने से पहले यूनिवर्सिटीज के वी०सीज० को बुलाकर नहीं पूछा। मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को पूरी तरह से देखने के लिए आप इस बारे में सदन की एक कमेटी बना दें। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने इतनी राहत लोगों को दी है उसमें मैं वित्त मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लोगों को जो वजीफा मिलता है वह तब मिलता है जब वे 18 साल के हो जाते हैं।

वित्त मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि फैसला हमने कर दिया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से खल के बारे में मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि खल एक ऐसा पदार्थ है जिसे किसान ले जाता है और भैंस और गाय को खिलाता है। जिससे दूध का उत्पादन बढ़े। जहां सरकार इतनी राहत दे रही है वहां इस खल को भी टैक्स से माफ करना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि फरीदाबाद में मेंहदी का कभी बहुत उत्पादन हुआ करता था। आज वहां

जो लोग मेंहदी उगाते हैं और उससे खिजाब बनाते हैं वह उत्पादन हरियाणा में नहीं होता है। मैं मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां फरीदाबाद में मेंहदी का बहुत बड़ा उद्योग है और जो लोग मेंहदी का काम करते हैं, उसको ऐक्सपोर्ट करते हैं उसका आजकल उत्पादन हरियाणा में न होकर राजस्थान और मध्यप्रदेश से मेंहदी लेकर आते हैं। मेंहदी के उत्पादन पर जो टैक्स सरकार ने लगाया हुआ है वह बहुत ज्यादा नहीं है अगर सरकार उस टैक्स को माफ करके कारखानेदारों को कहे कि वे मेंहदी के उत्पादन पर यहां के किसानों को प्रोत्साहन देंगे तो सरकार को उस टैक्स को माफ करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो इन्होंने बजट में बताया है कि एन०सी०आर० में (विघ्न) ....

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अब आप कंक्लूड करें। आपको बोलते हुए 11 मिनट का समय हो गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : ठीक है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, उसमें इकोनोमिक ग्रोथ एन०सी०आर० में 11.4 परसैंट है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन्हें सारे हरियाणा में इकोनोमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए गांवों में और जो इलाके पिछड़े हुए हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा। इसमें शिक्षा और साधनों का असंतुलन प्रदेश की तरक्की में रुकावट पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी सुझाव है कि जो ये बिजली विभाग को सबसिडी देते हैं यह सबसिडी विभाग को न देकर के किसानों को दी जाये। यदि किसानों को सीधे तौर पर सबसिडी दी जाएगी तो मैं समझता हूं कि बिजली का जो गलत इस्तेमाल होता है उस पर रोक लगेगी और इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो लोग डीजल सैट चलाकर पानी निकालते हैं जिनके पास बिजली नहीं है, उस डीजल सैट पर काम करने वाले किसान को भी सबसिडी या कोई राहत देनी चाहिए जिससे बिजली पर बोझ कम होगा और किसानों को इससे राहत भी मिलेगी। इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री राम किशन फौजी (बवानी खेड़ा, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी का भी हृदय से आभारी हूं कि इस बजट में हर समाज को, हर किसान, मजदूर और 36 बिरादरी के लोगों को राहत देने की बात की गई है। इसके साथ ही सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों का 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया जिनकी जमीन बैंकों के अंदर गिरवी रखी गई थी और कुर्की के ऑर्डर हो चुके थे। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे उन्होंने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल किया है। इसके साथ ही साथ मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि 5 एकड़ का कोई किसान अगर कोई लोन ले लेता है और फसल न होने की वजह से या बरसात कम होने की वजह से लोन चुका नहीं पाता है तो उसके बारे में मेरा सुझाव है कि जिनके पास न जमीन है, न मकान है, रहने के लिए जगह नहीं है और किसी बेचारे गरीब आदमी ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से लोन ले लिया और उसको भर नहीं सकता, मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि ऐसे गरीब लोगों का लोन भी माफ जरूर करना चाहिए। जिन गरीब लोगों के लिए रहने के लिए झुग्गी-झोंपड़ी डालने

[श्री राम किशन फौजी]

की जगह नहीं थी उन एस०सी० और बी०पी०एल० कार्ड होल्डर और उनकी बिरादरी के भाईयों को भी 100-100 गज के प्लाट देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही बड़ा सराहनीय और ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके लिए गरीब आदमी ता-जिन्दगी जब तक उनका जीवन रहेगा कांग्रेस पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवादी रहेंगे और उनके शुक्रगुजार रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में यह आश्वासन भी दिया था कि इन 100 गज के प्लाट वालों के लिए हम बिजली, पानी और सड़कों का प्रबन्ध करेंगे। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि इन सुविधाओं के साथ-साथ इन आवास कालोनियों में कम्यूनिटी सैंटर या चौपाल का अवश्य प्रबन्ध किया जाए ताकि वहां पर रहने वाले लोगों के बच्चों की शादी के समय तथा गमी खुशी के समय ये चौपाल काम आ सकें। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था वहां पर जरूर करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक बात के लिए मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि आज के दिन पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पानी की किल्लत है। खासतौर से हरियाणा प्रदेश के अन्दर बहुत किल्लत है। वर्तमान सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने बहुत प्रयास किया है और प्रदेश में समान पानी के बंटवारे की बात की है। हांसी-बुटाना लिंक नहर बनाकर एक सराहनीय काम किया है। इसके लिए विरोधी पक्ष के लोगों ने इस नहर का विरोध किया। पिछली सरकार श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की रही उसके समय में दक्षिणी हरियाणा के लोगों को पीने का पानी भी नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद पानी का समान बंटवारा करके एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का गुणगान हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा कदम है इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि एक दिन सारे हरियाणा में पानी का समान बंटवारा हो जायेगा। दूसरी बात एस०वाई०एल० नहर का बहुत लम्बा झगड़ा चल रहा है। इसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा को पानी देने के लिए एस०वाई०एल० बनाई थी इसके लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी से और प्रधान मंत्री जी से मिलकर इस नहर को जल्द से जल्द बनाने का प्रावधान कराना चाहिए। आज हालात यह है कि बरसात तो हो नहीं रही है और आने वाले समय में जो पानी पंजाब को ज्यादा मिल रहा है अगर उसका हिस्सा हरियाणा को नहीं मिला तो सिंचाई के पानी की बात तो दूर है पीने के पानी की दिक्कत आ जायेगी। इसलिए इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए नहीं तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए यह खतरनाक हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के छः साल के कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश में खून-पसीने की कमाई को सारी की सारी लूटकर चौधरी देवीलाल के नाम से जो ट्रस्ट बनाया था उसमें लगा दी और देश-विदेशों में उस पैसे को जमा किया। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आपने एक कमेटी बनाई है और मुझे भी उस कमेटी का मैम्बर बनाया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार का कोई आदमी चाहे वह अधिकारी है या कर्मचारी जब वह 100 रुपये की रिश्वत ले लेता है तो उसको तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेलों में डाल दिया जाता है। ऐसे ही जिस आदमी ने करोड़ो रुपया हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के लोगों की कमाई, भाला डलवाकर, धमकी देकर इकट्ठी की हो उस आदमी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, इसकी क्या वजह है उस आदमी को अब तक जेल में क्यों नहीं पहुंचा पाये? ऐसे आदमी को हाउस

में बिठाया हुआ है और यहां अपने भाषण देने के लिए और मात्र 600 रुपये लेने के लिए आता है। ऐसा आदमी तो पांच पैसे भी लेने आ सकता है। ऐसे आदमी को तो जेल के अन्दर डाल देना चाहिए। (विघ्न)

श्री शाहिदा खान (तावडू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे कहना चाहूंगा कि पहले ये अपने गिरेबान में झांक लें। परसों इन्होंने अवैध खनन पर डी०एस०पी० के खिलाफ बहुत बड़ा रोला किया। आज यहां ये बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं और दूसरों को जेल में भिजवाने की बात कर रहे हैं, इनको ऐसी बात कहते हुए ******** आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : शाहिदा खान जी ने जो अनपार्लियामैंट्री शब्द का प्रयोग किया है उसको रिकार्ड न किया जाए।

श्री राम किशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने मेरे बारे में बात कही इसलिए मैं इनको कहना चाहूंगा कि रामकिशन फौजी के बारे में पूरा हरियाणा जानता है कि उसने न कभी कोई गलत काम किया है और जब तक जीवन रहेगा न कभी गलत काम करेगा। यदि मैं कोई गलत काम करूंगा तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, आप और हम जब विपक्ष के सदस्य थे उस समय ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में खनन में लूट मचाई गई थी हमने उसका डटकर विरोध किया था। हम जेलों में भी गए थे। इन्होंने तो बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया था। हम मुख्यमंत्री जी से इस बारे में मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस केस की विजीलैंस इन्कवायरी होगी। अब हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने उस लूट को बन्द करवाया है। ओम प्रकाश चौटाला के दामाद डाक्टर अंतिल ने खानों की गैर कानूनी लीज दी हुई थी और लोग कहते थे कि ओम प्रकाश चौटाला और उसके बेटे ने पहाड़ की लूट मचाई हुई है। आने वाला दिन कभी उनको माफ नहीं करेगा, एक न एक दिन तो उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, ये पर्चियां मैं आपको भेजना चाहता हूं। जो खानों में काटी जाती थी। ये पर्चियां कैसे ली गई यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तीन दिन पहले खनन में गरीब मजदूरों पर मुकदमें बनाए गए और उस केस में मुख्यमंत्री महोदय ने इन्कवायरी के आदेश दिये हैं इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित साथी से एक ही बात जानना चाहता हूं कि परसों अवैध खनन में जो जे०सी०बी० का ड्रामा हुआ क्या वह आपका नहीं था या आपके भाई का नहीं था ? इस बारे में स्पष्टीकरण दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मैं तथ्यों के आधार पर कहूंगा और परसों भी मैंने बताया था और अब फिर बता देता हूं कि सोहना के थाने में, मानेसर के थाने में और तावडू के थाने में 4 बजे तैयारी होती थी और 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक करोड़ों रुपया इकट्ठा होता था। (शोर एवं व्यवधान) अगर न होता हो तो जनाब मना कर दें। जो चीज सामने है और जो तथ्य हैं उसको कौन मना कर सकता है। यह बीती हुई बात है। (शोर एवं व्यवधान) आज यह काम बन्द हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बात कही कि 3 दिन पहले एक अधिकारी ने गरीब आदमियों के ऊपर मुकदमें बनाए तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको जरूर सजा मिलेगी और सजा मिलनी भी चाहिए हम इस बात के पक्षधर हैं। उस अधिकारी ने उन गरीब आदमियों पर मुकदमें बनाकर भिवानी सी०आई०ए० में ले जाकर उनको पानी की होदियों में डालकर उनके ऊपर बैठ गए और उनकी हालत खराब कर दी। जब मुझे पता लगा तो मैं वहां गया। जब वे और लोगों को ले जाने लगे तो मैंने उनको रोका। मैंने मुख्यमंत्री महोदय जी को इस बारे में बताया और मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि इस केस की इन्कवायरी होगी और दोषी को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस केस में चाहे कितना बड़ा भी अधिकारी क्यों न इन्वालव हो, वह सस्पैंड होगा और गिरफ्तार होगा। अध्यक्ष महोदय, हम गलत काम के पक्षधर नहीं है। इनकी सरकार के अंदर बहन-बेटियों के ऊपर अत्याचार होते थे, गर्भवती औरत को इन्होंने पीटने का काम किया और ये बात अखबारों में आई। हमने इस बारे में हाऊस में मांग भी उठाई थी, हमने धरने भी दिए, हमने आंदलोन भी किए और यह कहा था कि अरे ओम प्रकाश चौटाला जी ये मुख्यमंत्री की कुर्सी तो आनी जानी चीज है।

डा० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, हर जनप्रतिनिधि का काम है कि वह जनता के हितों के लिए धरने दे, जलूस निकाले, घेराव करे और गिरफ्तारियां दे। लेकिन माननीय विधायक के भाई के साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और सत्ता में होते हुए ये अपनी ही सरकार के खिलाफ अपने भाई के साथियों के पक्ष में धरने दे रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। ये उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने जुर्म किया है और चोरी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं इंदौरा जी को बताना चाहूंगा कि अगर मेरा भाई इस काम में शामिल हो तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और इंदौरा जी भी वायदा करें कि यदि चौटाला जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में गलत कार्य किए हैं तो ये राजनीति छोड़ देंगे। अध्यक्ष महोदय, जब मैं हरियाणा विकास पार्टी में चौधरी बंसी लाल जी के साथ था उस समय मैंने अकेले होते हुए भी इनसे समझौता नहीं किया। आज मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं। अगर किसी गरीब आदमी के साथ ज्यादती होगी तो हम उनका साथ देंगे चाहे हम सरकार में हों। यह हमारी जिम्मेवारी है कि किसी गरीब आदमी के साथ किसी तरह की ज्यादती न हो।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। ***

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार है और हमारा यह पता करना फर्ज बनता है कि कहीं किसी अधिकारी के तार ओम प्रकाश चौटाला से तो नहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि गलत काम करने वालों को भी सजा दिलवाना हमारा काम है। लेकिन इनकी सरकार के समय में इनका कोई विधायक चौटाला जी और उनके बेटों के आगे नहीं बोलता था। उस समय किसी विधायक का हाथ तोड़ दिया जाता था, किसी विधायक की टांग तोड़ दी जाती थी। अध्यक्ष महोदय,

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौटाला जी उस समय इसी सदन में कहा करते थे कि जब तक जीऊंगा मुख्यमंत्री रहूंगा। मैं इनको कहना चाहूंगा कि चोरों की दुकान लम्बी नहीं चलती। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय,***

श्री अध्यक्ष : फौजी साहब ने जिन अनपार्लियामैंटरी शब्दों का प्रयोग किया है ये शब्द सदन की कार्यवाही में रिकार्ड न किए जायें।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमारी भिवानी जिले की बागड़ी भाषा है और उसमें जिसके अंग में गड़बड़ी हो उसे हम ऐसे ही बुलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ न कहते हुए अंत में मैं बजट की, सभी सदस्यों की, मुख्यमंत्री जी की, वित्तमंत्री जी की और आपकी प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद।

श्री नरेश मलिक (हसनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। समय का अभाव है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब हम बजट की तरफ देखते हैं इसमें Interest of loan payment 9.60 percent or loan repayment 9.4 percent यानि लगभग 5 हजार करोड़ रुपये हम सालाना लोन और ब्याज के भुगतान में पे कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम लोन रिपेमैंट पर नजर डालें तो पता चलता है कि वर्ष 2001-02 में 4 हजार करोड़ रुपये की लोन रिपेमैंट की गई है। वर्ष 2002-03 के दौरान 3274 करोड़ रुपये की लोन रिपेमैंट की गई है और वर्ष 2003-04 में 3498 करोड़ रुपये और वर्ष 2004-05 में 3014 करोड़ रुपये लोन और ब्याज की रिपेमैंट पर खर्च हुए। लेकिन वर्ष 2005-06 में इस मद पर केवल 1160 करोड़ रुपये, वर्ष 2006-07 में 114 करोड़ रुपये, वर्ष 2007-08 में केवल 742 करोड़ रुपये और इस साल 2008-09 में यह बढ़कर 2389 करोड़ रुपये हो गई है। यानि कि इतना पैसा हमारा लगभग 5 हजार करोड़ रुपये के आसपास केवल लोन और उसके ब्याज की रिपेमैंट में जा रहा है। वित्तमंत्री जी को चाहिए कि वे इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि अलटीमेटली यह प्रदेश का पैसा है। दूसरी बात स्पीकर सर, यह है कि आज भी हमारे हरियाणा प्रदेश की लगभग डेढ़ करोड़ से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है और रूरल डैवेल्पमैंट के लिए बजट में केवल 3631 करोड़ रुपये ही रखे गये हैं, जो कि बहुत ही कम हैं। इसलिए लोग गांवों से शहर की तरफ भाग रहे हैं। गांवों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण लोग गांव छोड़ रहे हैं। इस पर मेरा निवेदन है कि जो रूरल डैवेल्पमैंट के लिए बजट रखा गया है इसमें पंचायत के साथ और भी कई विभाग हैं जिनमें यह अमाऊंट बंट जायेगी। इस प्रकार से गांवों के समग्र विकास के लिए यह बहुत ही कम बजट है। इसलिए इसको हर हाल में बढ़ाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि महालेखाकार हरियाणा की वर्ष 2008-09 की रिपोर्ट है इसमें बहुत ज्यादा अनियमिततायें हैं। जितनी भी सरकार की स्कीमें थी उनमें से कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जो समय पर पूरी हुई हो और किसी स्कीम पर 5 करोड़ रुपये किसी पर 10 करोड़ रुपये और अगर कोई बड़ा प्रोजैक्ट है तो उस पर 50 करोड़ रुपये तक ज्यादा खर्च हुए हैं अगर यह पूरी रिपोर्ट पढ़ी जाये तो कई सौ करोड़ रुपये ऐसे हैं जो कि ज्यादा और अननैसेसरी खर्च किये गये हैं। यह सरकार और पब्लिक का पैसा है जो कि केवल अधिकारियों की लापरवाही की

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री नरेश मलिक]

वजह से टाईम पर प्रोजैक्ट्स पूरे न होने की वजह से ज्यादा खर्च हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी में लिखा है कि 19,026 कृषि क्षेत्र में बिजली के कनैक्शन पैंडिंग हैं जिनके लिए लोगों द्वारा इतना भारी पैसा सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाने के बावजूद भी ये कनैक्शन इतनी बड़ी मात्रा में कई साल से पैंडिंग पड़े हैं। इसके अतिरिक्त 14,540 कनैक्शन घरेलू क्षेत्र में पैंडिंग हैं और 2197 गैर घरेलू बिजली कनैक्शन पैंडिंग हैं। इसके साथ-साथ जो बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी वर्ष 2004 से बिजली कनैक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन 34 महीने बीत जाने के बाद अभी तक भी उन्हें बिजली के कनैक्शन नहीं मिले हैं। उनके कनैक्शन भी पैंडिंग हैं। अध्यक्ष महोदय, इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर 34-34 महीने में इम इण्डस्ट्रीज़ को कनैक्शन नहीं देंगे तो कैसे हमारे प्रदेश का विकास होगा, कैसे हमारा प्रदेश तरक्की करेगा ? अध्यक्ष महोदय, मानेसर-पलवल स्टेट हाईवे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजैक्ट है। आज जब हम वहां से निकलते हैं तो उस पर हमें कहीं भी काम चलता हुआ नज़र नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह काम किस कारण से बंद है और यह कब तक पूरा हो जायेगा। इसके अतिरिक्त जो 100 गज के प्लाट देने की सरकार द्वारा घोषणा की गई है यह बहुत ही स्वागतयोग्य निर्णय है। मैं भी इसका स्वागत करता हूं। लेकिन जिन गांवों में पंचायती ज़मीन नहीं है वहां के लोगों को प्लाटों का आबंटन किस प्रकार से किया जायेगा। पिछले बजट सैशन में वित्तमंत्री जी द्वारा इस बात का जिक्र किया गया था कि जिन गांवों में पंचायती ज़मीन नहीं है अगर हम वहां पर ज़मीन एक्वायर करके प्लाट देते हैं तो इसके लिए हमें 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। लेकिन इस बजट में कहीं भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस बारे में सरकार ने कुछ न कुछ तो प्लानिंग की होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या इस बारे में की गई प्लानिंग के बारे में इस हाउस को अवगत करवाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं अपने हल्के की 2-4 छोटी-छोटी समस्याओं की तरफ भी आपके माध्यम से सरकार का और विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय मेरे हल्के के गांव सुनारियां में गये थे उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनारियां खुर्द और सुनारियां कलां दोनों गांवों की सड़कें गलियां और नाले पक्के बनाने के लिए और जोहड़ की चारदीवारी बनाने के लिए अपनी मंजूरी दी थी। लेकिन अभी तक इसके लिए कोई एस्टीमेट्स वगैरह नहीं बनाये गये हैं जबकि इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा को 14 महीने हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरक्त सुनारियां गांव की 310 एकड़ जमीन जेल बनाने के लिए सरकार द्वारा एक्वायर की गई थी। उस गांव की 100 एकड़ ज़मीन और बची हुई है। इस बात की ग्राम पंचायत को कोई जानकारी नहीं है कि उस बची हुई 100 एकड़ ज़मीन का क्या किया जायेगा। जब इस बारे में मैंने डी०सी० से पूछा तो उनका कहना था कि सरकार इस जगह पर प्लाट डवैल्प करके गांव वालों को ही देने पर विचार करेगी। इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेने का अनुरोध मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से करूंगा। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी डोभ बार्नथापी समेत 3 गांवों में शूगर मिल का उद्‌घाटन करके आये थे तो इन तीन गांवों की गलियों और नालियों को सीमेंट से पक्का करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। उस पर भी अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इस

बारे में भी कार्यवाही करने का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा। अध्यक्ष महोदय, गाँव बालन्द में आदरणीय सांसद श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी आये थे और उन्होंने समशान घाट के बारे में तथा बेरी रोड़ से थली मंदिर तक सड़क की घोषणा की थी वह भी पूरी नहीं हुई है। मैं अपने कामों के बारे में नहीं कहता मैं तो उन कामों के बारे में कह रहा हूँ जिनकी घोषणा या तो मुख्यमंत्री जी या आदरणीय सांसद महोदय करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी यह आवाज उठाई थी कि मेरे हल्के के पाकस्मां गाँव से गान्धरा तक 22 फुट चौड़ा और दो किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। अगर उसे सड़क बना दिया जाये तो पाकस्मा गाँव के लोगों को बहुत फायदा होगा। अब अगर पाकस्मां गाँव के लोगों को सांपला जाना हो तो उन्हें या तो भेनंद हो कर जी०टी० रोड़ पर आना पड़ता है या किसरैंटी, अटायल हो कर सांपला जाना पड़ता है जो कि 12-13 किलोमीटर पड़ता है। अगर यह दो किलोमीटर का टुकड़ा बन जाये तो पाकस्मां गाँव के लोगों की 6-7 किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी और लोगों को फायदा होगा।

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : मलिक साहब, आपका गाँव कौन सा है?

श्री नरेश मलिक : सर, मेरा गाँव तो गान्धरा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : फिर यह क्यों नहीं कहते कि मेरे गाँव की रोड़ बनानी है। ठीक है, हम इसे बना देंगे।

श्री नरेश मलिक : मुख्य मंत्री जी, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक प्रार्थना और है, अबकि बार जब मैंने हल्के का दौरा किया तो लोगों की बहुत शिकायतें पानी के बारे में आई हैं। पहले नहर ठीक समय पर आ जाया करती थी लेकिन अबकि बार 30-40 दिन में आई है जिससे लोगों के पानी के वार कट गये। इससे पेयजल की भी समस्या पैदा हो गई है। सभी वाटर वर्क्स सूखे पड़े हैं। इस समस्या का कोई न कोई समाधान किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री रमेश गुप्ता (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, 18 मार्च, 2008 को माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वार्षिक बजट पेश किया है उस पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। पिछली बार जो बजट पेश किया गया था उस समय से आज तक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और जो प्रयास किये गये थे उसमें हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं। अब भी वित्त मंत्री जी का यही प्रयास है कि हरियाणा का चहुंमुखी विकास हो और जो गरीब और पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं मिलें। इस कार्य में सरकार सफल भी रही है। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में जनता की भावनाओं और आशाओं को ध्यान में रखते हुए समाज के हर वर्ग के लिए राहत दी है। यह बजट चाहे विद्यार्थी हों, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों या राज्य के सरकारी कर्मचारी हों सभी के हितों पर केन्द्रित है। 2008-09 के बजट में जो अनुमानित आय है वह 21698 करोड़ दिखाई गई है और जो खर्च है वह 20284 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। इस प्रकार से 1414 करोड़ रुपये का सरप्लस बजट पेश किया है। इकोनॉमी रेट में भी हरियाणा 11.6 की रेट से केन्द्र की ग्रोथ रेट से आगे है। कृषि क्षेत्र में भी 4.5 परसैंट ग्रोथ रेट से नेशनल लेवल की 2.6 परसैंट ग्रोथ रेट से अधिक है। जो प्रयास मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में किये गये उससे पैदावार में भी हरियाणा तरक्की कर रहा है। हमारा प्लांड बजट भी 6650 करोड़

[श्री रमेश गुप्ता]

का है जो कि पिछले वर्ष से तो 25.5 परसैंट अधिक है जिससे कल्याणकारी योजना चलाई जा सकती हैं। यह बजट 7 मार्च को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का प्रतिबिम्ब है। यह बात मैंने कुरूक्षेत्र में भी प्रैस कान्फ्रेंस में कही थी कि इस बजट से लगता है कि हरियाणा सुनहरी भविष्य की ओर अग्रसर है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा शिक्षा के ऊपर भी काफी खर्च किया जा रहा है और अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के लिए मुख्य मंत्री अनुसूचित जाति शिक्षा स्कीम इस साल से इन्ट्रोड्यूस हुई है ताकि बच्चे बीच में स्कूल न छोड़ें। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए तर्कसंगत बनाया जा रहा है, नये पोलिटैक्निकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। 76 पोलिटैक्निकल कॉलेज बनाए गए हैं और 52630 सीटें इनमें रखी गई हैं। स्पीकर सर, इसी तरह से दो टैक्नीकल कॉलेज, 61 इन्जीनियरिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज खोले गए हैं। स्पीकर सर, पहले इस प्रकार की टैक्नीकल ऐजुकेशन के लिए हमारे बच्चों को स्टेट से बाहर जाना पड़ता था परन्तु अब हमारी सरकार इस ऐजुकेशन के लिए यहीं पर ही इन्स्टीच्यूट डिवैल्प कर रही है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली की मेन डिमाण्ड है। किसी भी पिछली सरकार ने बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया लेकिन वर्तमान सरकार ने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पग उठाए हैं। जो नये थर्मल प्लांटस लगा जा रहे हैं उनकी वजह से आने वाले दो वर्षों में उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलने लगेगी (विघ्न) स्टेट में बिजली की कमी होने के बावजूद माननीय मुख्य मन्त्री जी ने किसानों को पैडी के लिए बिजली दी जिसकी वजह से बिना डीजल फूंके किसानों की पैडी की फसल पकी है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने हल्के की कुछ डिमाण्डज की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। 6 जुलाई, 2006 को माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मेरे हल्के में एक पब्लिक रैली की थी उसमें राखसी नदी के बारे में मांग की गई थी और उसका काम मन्जूर भी हो चुका है इसकी खुदाई भी हो गई है। इसका काम एक साल में होना है और यह दादूपुर नलवी के साथ जुड़ेगी। इसके लिए कुछ जमीन एक्वायर होनी थी उसके लिए दफा 6 के नोटिस हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि इसके लिए फण्डज ऐलोकेट किए जाएं ताकि यह काम शुरू हो सके। स्पीकर सर, लाडवा में एक स्पोर्टस स्टेडियम के लिए भी जगह तजवीज की गई है और नगरपालिका ने इसकी मन्जूरी दे दी है। सरकार से मेरा निवेदन है कि इसकी मन्जूरी जल्दी से जल्दी देने की कृपा करें ताकि यहां पर जल्दी से जल्दी स्टेडियम बन सके। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने जो रेलवे ओवर ब्रिज पिछली सरकार ने टैक्स के साथ शुरु किया था माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जनता की मांग और कठिनाई को देखते हुए इस ओवर ब्रिज को बिना टैक्स के किया और 15 करोड़ रुपये सरकार ने अपनी तरफ से दिये इससे लोगों को काफी राहत मिली है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारी रेलवे ओवर ब्रिज की मांग है जो हमारा बाईपास रोड है और एक जो सुन्दरपुर फाटक है वहां से रेलवे ओवरब्रिज जो कि मेरे ख्याल से मन्जूर हो गया है इसलिए इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि आने वाले समय में लोगों को इससे लाभ हो सके और आने वाले सूर्य ग्रहण पर लोगों को दिक्कत न हो। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पेहवा से हरिद्वार को जो फोरलैनिंग के बारे में भी कहा था

और क्योंकि हमारे यहां कोई रेलवे लाईन भी नहीं मिली हुई है इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सड़क की फोरलेनिंग जल्दी की जाए।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, अब आप बैठें। अगर आपने ओर कोई बात कहनी है तो वह आप लिख कर मुझे भिजवा दें वह इसके साथ ऐड कर दी जाएगी।

श्री बच्चन सिंह आर्य (सफीदों) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं कोई नई बात नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि सारी बात बजट पर हो चुकी है और मेरे साथी भी काफी कुछ कह चुके हैं। स्पीकर सर, इस बजट से पहले इस सरकार के जो पिछले बजट पास हुए हैं उनके परिणाम भी अब आने शुरू हुए हैं, चाहे कहीं पर पावर हाउस बनते हों, चाहे सड़कें बनती हैं उनसे लोगों को लाभ मिल रहा है। लगातार पिछले तीन सालों से चाहे वे गरीब वर्ग के लोग हों चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों मुझे कोई घर ऐसा नहीं लगता जिसे इस सरकार के आने के बाद कुछ लाभ न हुआ हो। हरियाणा में चाहे गरीब आदमी हो चाहे कोई एम०सी० या बी०सी० का आदमी हो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसको चलाने के लिए साईकल न मिला हो और किसी गरीब महिला को अपना रोजगार करने के लिए मशीन न मिली हो। किसानों के कर्जे मुआफी की बात हो, चाहे को-ऑपरेटिव सोसाईटीज के ब्याज मुआफी की बात हो या किसानों को उनकी उपज के भाव दिलाने की बात हो, अब पूरे हरियाणा में पूरी तरह से सभी वर्गों में बड़ी जबरदस्त खुशहाली है। पिछले बजट भी बहुत अच्छे पेश किये गये थे।

श्री अध्यक्ष : आर्य साहब, ये सारी बातें पहले ही आ चुकी हैं यदि आप कोई नई बात इन्कलूड करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कहें।

श्री बचन सिंह आर्य : अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो सदन का बहुत थोड़ा सा समय लेते हैं और बहुत ठीक बात कहते हैं लेकिन ये हमारे भाई खाली इस बात पर टाईम खराब कर देते हैं जिसका इनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी फौजी साहब बोल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं इन भाईयों से इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक स्पैसिफिकली किसी का नाम न लिया जाए इस प्रकार से बीच में नहीं बोलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति काना हो सकता है, कोई लंगड़ा हो सकता है कोई अन्धा भी हो सकता है केवल एक व्यक्ति से इनकी पहचान नहीं है। इस प्रकार की बात को ले कर 15-15 मिनट का समय ये लोग खराब कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इन लोगों को तो रोकते नहीं हैं लेकिन हम तो ठीक बात ही कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कहना चाहूंगा कि पिछले बजट में मुर्राह भैंसों के लिए प्रावधान किया गया था। मुझे नहीं पता है कि उसके लिए केन्द्र की सरकार से मंजूरी मिली है कि नहीं मिली है। लेकिन मैं इसी तर्क पर गऊओं के बारे में कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने गऊओं के रख-रखाव के लिए इतना पैसा दिया है कि उतना पैसा आज से पहले कभी नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज जो शहरों और गांवों में गऊएं कूड़ा खाती फिरती हैं उनको भी गऊशालाओं में रखने का प्रबन्ध क्या यह सरकार करेगी? अध्यक्ष महोदय, आज आपको भी मालूम है कि गऊ मूत्र से कैंसर का ईलाज हो रहा है उसी तरह से गऊ के दूध के भी बहुत लाभ हैं। मेरा निवेदन है कि वित्तमंत्री जी गऊओं के लिए भी बजट में प्रावधान करें।

श्री राधे श्याम शर्मा (नारनौल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री

[श्री राधे श्याम शर्मा]

चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का, वित्तमंत्री जी का और इस सरकार का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना शानदार बजट हरियाणा की जनता को दिया है। इसके लिए मैं इनको बधाई भी देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अखबार में देख रहा था उसमें लिखा था कि –

जिन्दगी तेरी पहचान अब सरल हो गई है,

कदम धरा कि मंजिल पास हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट का कदम है यह बड़ा ही ठोस कदम है, सबके हित का कदम है, गरीबों के हित के लिए कदम है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने बहुत सी योजनाएं हरियाणा में शुरू की हैं जैसे कि अनुसूचित जाति के छात्र और छात्राओं के लिए छात्रवृति योजना है, डाक्टर भीम राव बाबा अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजना है, इन्दिरा गांधी पेय-जल योजना है, राजीव गांधी समबर्द्धन योजना है, लाडली योजना आदि। अब हम किस-किस योजना का जिक्र यहां पर करें। इन सभी योजनाओं को गरीबों की भलाई के लिए शुरू किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज अनुसूचित जाति के बच्चे स्कूलों से बाहर जाते नजर नहीं आएंगे, वे स्कूलों के अन्दर ही नजर आएंगे। अध्यक्ष महोदय, सदन में बजट पर बोलते हुए कुछ निराश चेहरों ने बजट पर टिप्पणियां की हैं कि यह बजट नीरस है, निराशा से भरा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, उनकी यह बात सुनकर मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा कि इस सरकार से पहले उनके वक्त में 22 सौ करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था और वे 250 करोड़ रुपये का बजट पूरा भी नहीं किया गया। उनका जो बजट बनाने का प्रिंसीपल था उसको देखकर मुझे आज सैक्सपीयर की याद आती है। One may smile and smile yet be a serpend under it. अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय का बजट अच्छा था या यह बजट जो वित्तमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी सभी के लिए 6650 करोड़ रुपए का लेकर आए हैं, यह अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से इनसे कहना चाहूंगा कि यह जो पेय-जल योजना बनाई है, इस योजना में नांगलदुर्ग और निजामपुर को भी शामिल किया जाए। इस बारे में मैंने मांग भी की थी। माननीय वित्तमंत्री जी ने मुझे इस बारे में कहा था कि मेरे पास जब यह स्कीम आएगी तो मैं इनके लिए भी पैसा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, अब यह स्कीम इनके पास आ चुकी है और 6650 करोड़ का बजट भी सदन में आया है। मेरा आपसे निवेदन है कि पेय-जल योजना सिर्फ 25 करोड़ रुपये की है और इसमें से हमारे यहां पर भी इस योजना के तहत पैसा मंजूर करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, हमारी एक मांग भाखरी और जाखणी गांव की भी है उसके लिए भी मेरा इनसे निवेदन है कि इस बारे में भी विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर नांगल चौधरी में मण्डी की शैड के बारे में भी प्रार्थना है, उसको भी बनाने का कष्ट करें। इसी के साथ नांगल चौधरी से न्यामोतोर, मोरोंड और गोठरी की सड़कें टूटी हुई हैं उनको भी बनाने का प्रावधान किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इन कामों को करने के लिए हमारी सहायता करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, अब आप बैठ जाएं। बाकी बातें आप डिमांड पर बोलते हुए कह लेना। (विघ्न) सुखबीर सिंह जी आप बोलें।

श्री सुखबीर सिंह (रोहट) : अध्यक्ष महोदय, जो बजट चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के आर्शीवाद से पेश किया है, यह बहुत ही बढ़िया बजट है। यह बजट सभी वर्गों के हित के लिए है। अध्यक्ष महोदय, जो पिछली सरकारें थीं, उनमें कहीं न कहीं क्षेत्रवाद की बू थी, जातिवाद की बू थी, कहीं पैसे से अपना पेट भरने की बू थी। लेकिन आज के जो मुख्यमंत्री ये बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले भिवानी, सिरसा और हिसार के मुख्यमंत्री रह लिए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो आज के मुख्यमंत्री हैं, ये सारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हमारा पंजाब और हरियाणा ज्वायंट था। चालीस सालों में मुश्किल से एक ही रीजनल सैंटर पहले रोहतक में दिया था लेकिन आज जींद में, रिवाड़ी में रीजनल सैंटर्ज चल रहे हैं। इसके अलावा कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी इस सरकार ने बनवा दी हैं। अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी ऐजुकेशन को जानते नहीं थे जबकि ऐजुकेशन तो हर आदमी के लिए जरूरी है, गरीब के लिए जरूरी है, किसान मजदूर के लिए भी ऐजुकेशन जरूरी है। स्पीकर साहब, ऐजुकेशन की जरूरत अब समझी गयी है इसलिए अब सरकार ने सारे हरियाणा में कई यूनिवर्सिटीज बनायी हैं, रीजनल सैंटर्ज बनवाए हैं। इसी तरह से सभी रोडज भी बनवायी गयी हैं। आज दिल्ली की रोड्ज बेकार हैं लेकिन हरियाणा की रोड्ज अच्छी हैं। अध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाने के लिए पैसा दिया जाए क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड की रोड्ज की हालत खराब है लेकिन पी०डब्ल्यू०डी० की रोड्ज अच्छी हैं तो इन रोड्ज को भी अच्छा बनवाया जाए। इसी प्रकार से केन्द्र सरकार के द्वारा जो 60 हजार करोड़ रुपये का कर्जा किसानों का माफ किया गया है वह भी अच्छी बात है। यहां पर सभी ने किसानों का जिक्र किया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे गरीब आदमी चिढ़ते हैं।

श्री अध्यक्ष : फरमाणा जी, वह बात तो आ ली है आप रिपीटेशन न करें। आपको बोलते हुए तीन मिनट हो गये हैं जबकि आपने दो मिनट मांगे थे।

श्री सुखबीर सिंह : स्पीकर साहब, हमें भी ये बातें कहनी पड़ती हैं। स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि किसानों के साथ साथ गरीब आदमियों का कर्जा भी माफ किया जाए। पहले खेलों को भी बढ़ावा नहीं दिया जाता था लेकिन इस सरकार के समय में खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। चौटाला साहब न खिलाड़ी थे न ही वे खेलों के बारे में जानते थे। हरियाणा में खेलों का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि हरियाणा खेलों से ही जाना जाता है। स्पीकर साहब, एक कबड्डी खेल है हरियाणा स्टाइल कबड्डी। डांगी साहब भी हरियाणा स्टाइल कबड्डी करवाते थे और शूगर मिल में खेलते थे। मेरा सरकार से कहना है कि हरियाणा स्टाइल कबड्डी को भी हरियाणा सरकार की तरफ से मान्यता दी जाए और हरियाणा स्टाइल कबड्डी के खिलाड़ियों को भी नौकरियां भी दी जाएं क्योंकि जब खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं तो हमारे नौजवान उनको खेलते हुए अच्छी तरह से देखते हैं। इसी प्रकार से मेरे हल्के में जोहड़ों में पानी भरने की भी समस्या है। यहां पर सभी साथियों ने मनुष्यों के पीने के पानी की समस्या का जिक्र तो किया है लेकिन मैं यह कहता हूं कि पशुओं को भी पीने का पानी मिलना चाहिए। अभी गर्मी है इसलिए मेरा कहना है कि मेरे हल्के में सभी जोहड़ों को पानी से भरवाया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, फरमाणा माजरा गांव में एक साल से जोहड़ नहीं भरे गए हैं हालांकि इसके बारे में मैंने कई बार कहा भी है। स्पीकर साहब, इसी प्रकार से रेलवे लाईन बनाने की बात है। सोनीपत से जींद रेलवे लाईन बनवाने के बारे में मैंने कहा था और हुड्डा साहब ने कहा था कि इसके लिए पैसा भरवाएंगे इसलिए इस बारे में भी ध्यान दिया

[श्री सुखबीर सिंह]

जाए क्योंकि जमीन वहां पर महंगी होने लग रही है जिसकी वजह से वहां पर लोगों का विरोध होने लग रहा है। सरकार के द्वारा जो भी जमीन ऐक्वायर की जाती है वह फटाफट की जाए। 75 लाख रुपये मुआवजा देकर तुरन्त जमीन ऐक्वायर की जाए। अगर आप अभी जमीन ऐक्वायर नहीं करेंगे तो फिर 75 लाख रुपये का मुआवजा भी कम होगा, लोग ज्यादा मुआवजा मांगेंगे क्योंकि दिल्ली में इतना मुआवजा दिया गया है। स्पीकर साहब, रोहतक और सोनीपत जिले में जितनी भी जमीन ऐक्वायर की जाए वह तुरन्त की जाए। एस०ई०जैड० के लिए जमीन देने के लिए अब खरखौदा के लोग 75 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे मांग रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जमीन के रेट बढ़ गए हैं इसलिए अब हमारी भी मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष : फरमाणा जी, अब आप खत्म करें। जो बातें आपकी रह गयी हैं उनको आप लिखकर दे देना।

श्री सुखबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। भट्टगांव से बड़वासनी की रोड भी बननी चाहिए। स्पीकर साहब, पैसे को लूटने वालों को, बदमाशों को साथ में रखने वालों को और अपने आपको बहुत बड़ा बदमाश समझने वालों को आपने यहां से दूर रखा है अपने ज्ञान से अपनी विवेचना से और अपने तजुर्बे से इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, नहीं तो यह सदन सड़ता रहता। हुड्डा साहब ने जो काम किए हैं और ईमानदारी की जो मिसाल इस दुनिया में रखी है वैसी किसी ने नहीं रखी है इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री आपको हरियाणा में आगे नहीं मिलेंगे। स्पीकर साहब, मैं तो यही कहूंगा कि ये जब तक जीयें मुख्यमंत्री ही रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : फरमाणा साहब, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे लिए रास्ता खोल दिया ताकि मैं बोल सकूं।

डा० सीता राम : स्पीकर साहब, एक आदमी तो ऐसा मिला जिसने मुख्यमंत्री जी की तारीफ की।

श्री अरजन सिंह : एक आदमी क्यों पूरा हाउस उनकी तारीफ कर रहा है।

Mr. Spaker : It is the weakness of everybody.

प्रो० छत्तरपाल सिंह (घिराय) : स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बजट अनुमान पर बोलने के लिए समय दिया। स्पीकर साहब, पिछले काफी समय से सारे साथियों ने बजट के ऊपर अपने दृष्टिकोण से विचार रखें। स्पीकर साहब, पोलिटिकल पार्टीज चुनाव के अंदर लोगों के सामने अपनी बात लेकर जाती हैं और उसके मुताबिक फिर पांच साल तक अपनी परफोरमैंस दिखाती हैं। इसकी चर्चा हरियाणा की इस पंचायत में आपकी अध्यक्षता में हमेशा होती है। तीन साल से इस सरकार का एक्सपीरियैंस हरियाणा के लोगों ने किया है चाहे वह पिछले तीन साल के बजट हैं चाहे आज का बजट प्रस्तुत हुआ है, सरकार की जो परफोरमैंस है उसको हरियाणा की जनता ने अच्छी तरह से देखा है। जिस प्रकार से कुछ एक अपवाद जो राजनीति में रहे उसकी वजह से अविश्वास की खाई बढ़ती चली गई थी। कांग्रेस की सरकार ने, माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब के नेतृत्व की सरकार ने इस खाई को पाटने का काम किया है। जिसके फलस्वरूप एक मतदाता और नेता के बीच में विश्वास की बात पनप कर सामने आई है। स्पीकर सर, जिस प्रकार से गवर्नमैंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और

यू०पी०ए० की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में गरीबों के और किसानों के हक में जो 60 हजार करोड़ रुपये की कर्ज माफी का फैसला लिया गया है। उस फैसले का कोई सानी नहीं है। 60 हजार करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने माफ किया है और 830 करोड़ रुपया पैनल्टी और ब्याज हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने माफ कर दिया है और इसके अलावा 1600 करोड़ रुपये का बकाया बिजली के बिलों का बोझ जो गरीबों और किसानों के ऊपर था वह माफ करके बहुत ही सराहनीय कदम उठाये गये हैं। मेरे से पूर्व बोलते हुए बहुत से वक्ताओं ने इन विषयों पर चर्चा की है मैं भी अपने आपको उनके साथ शरीक करते हुए कुछ बातें और कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से बकाया बिजली के बिल माफ किए गए हैं इससे उन लोगों को तो रियायत दी ही गई है जो लोग बिलों की पेमेन्ट नहीं करते थे लेकिन साथ ही जो लोग रैगुलर बिजली के बिलों की अदायगी करते थे, जो अपना लेनदेन ठीक रखते थे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको भी प्रोत्साहन उसमें दिया गया है इसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि यह जो 60 हजार करोड़ रुपये की राशि माफ की गई है उसमें भी जिन लोगों का लेन देन ठीक था उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाए। इस बारे में हरियाणा सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पिछली सरकारें जो यहां पर काम करके गई हैं। उन्होंने चुनावें के समय जनता के समक्ष जो वायदे किए चाहे वह कर्ज माफी के थे या बिजली के बिलों की माफी के थे या बिजली पानी फ्री देने के वायदे थे उनको पूरा करने की बजाय सत्ता में आने के बाद उनकी मदद करना तो दूर की बात थी। बजाय इसके वे अपने परिवार को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते रहे, जिससे जनता में बहुत बड़ी अविश्वास की भावना उनके प्रति पैदा हुई। बहुत सारे लोग भ्रमित हुए, जिनकी क्षमता तो शायद थी लेकिन वे लालायित थे कि शायद माफी मिलेगी, शायद हमें पैसे का प्रोत्साहन मिल जाए, इस चक्कर में उन्होंने अपनी आदतें खराब कर लीं। अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार जिस पार्टी के बैनर पर और जिस आधार पर जनता में विश्वास दिखाकर आई है उस सरकार ने इस किस्म की लालायित और लोगों को लालच में डालने वाली बातें नहीं की। हमने न कर्जा माफी की बात कही, न ही बिजली के बकाया बिलों को माफ करने की बात कही थी लेकिन सत्ता में आने के बाद लोगों की जैनुअन प्रौब्लम्स को समझा और उनका कर्ज माफ किया। यह लोगों के विश्वास को बढ़ाने में सबसे सराहनीय कदम है। जो राजनीतिक पार्टियां प्रदेश की आमदनी के हिसाब से घोषणायें नहीं करती हैं वे सारे संसाधन अपने घरों में बनाने में लगी रहती हैं। उन्हें जनता की सुध नहीं रहती है। ऐसी सरकारें इस प्रदेश व देश के लिए कलंक होती हैं। इस तरह के लोग अविश्वास पैदा करने वाले लोग होते हैं। राजनीति में जो लोग मेहनत से और निस्वार्थ भाव से संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। बहुत सारे त्याग करते हैं और लोगों की सेवा करने का जुनून जिन लोगों में है, जिस प्रकार से इस देश के शहीदों ने फांसी के फंदों को अपने गलों से लगाया, ये विपक्ष के लोग उन नेताओं की आत्माओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता और देश की जनता जागरूक हो ताकि इस किस्म के लोगों को दोबारा से कभी सत्ता में आने का अवसर न मिले। यदि उन्हें दोबारा से अवसर न मिले तो मैं कह सकता हूं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था और 1966 में जब से हरियाणा प्रदेश का अलग से गठन हुआ था तब से लेकर अब तक बीच में ऐसे अपवाद राजनीति में न रहे होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा की आज जो माली हालत है उससे कई गुना ऊपर आज होती। मैं समझता हूं कि आज इनके लिए इस अपराध को स्वीकार करने की बात है। यह इनको

[प्रो० छत्तरपाल सिंह]

करना चाहिए। लोगों के बीच में हाथ जोड़कर माफी मांगने की बात है। जिनकी वजह से ये अपवाद इस राजनीति में पनपते रहे। स्पीकर सर, आपने जैसे ही सत्ता में आने के बाद हरियाणा के किसान की सुद ली है। पानी का समान बंटवारे की बात हरियाणा सरकार ने की है। मैं इस बात का ऐसा उदाहरण हूं जिसकी कान्सटीच्यूंशी के 70 प्रतिशत एरिया में भाखड़ा का पानी लगता है और 30 प्रतिशत एरिया में यमुना सिस्टम का पानी लगता है। मैं इस पीड़ा को दोनों दृष्टिकोणों से बहुत अच्छी तरह से समझता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रो० साहब, आप वाईंड-अप कीजिए।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर एड्रैस पर भी नहीं बोला था इसलिए मुझे थोड़ा समय और दिया जाए। स्पीकर सर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि जो हांसी-बुटाना लिंक नहर बन रही है उस नहर के बन जाने के बाद मेरे 30 प्रतिशत एरिया को उस नहर से पानी मिलेगा। जो किसान अपने पड़ोस में पानी लगता हुए देखते थे और उनके साथ लगते डोले में पानी लगता देखते थे और खुद पानी से वंचित रह जाते थे वे इसी प्रकार से रैस्ट आफ दि हरियाणा के लोग उस पानी का आनन्द उठा पायेंगे। स्पीकर सर, मेरे इलाके में यमुना सिस्टम से फीड होने वाली कैनाल थी जैसे पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी, सिवानी फीडर के पानी को रिड्यूस करके भाखड़ा सिस्टम से पानी दिया गया उससे दो दिक्कतें पैदा हुईं, एक तो भाखड़ा सिस्टम एग्जिस्टस था उस पर लोड बढ़ गया और दूसरा उधर सिवानी फिडर एबैंडन हो गई है। पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी में उसकी कैपेसिटी से आधा पानी रन करता है। इसलिए वे जो उसकी वेरासिटी का पानी न मिलने से खरड़ अलीपुर, लाडवा, भगाणा, सिसाय, चानत, भाटला और मय्यड़ पिछले दो-तीन साल से टेल पर पानी की भारी किल्लत आ रही है। जैसे ही हांसी-बुटाना लिंक नहर में पानी हम पंक्चर करके ले करके आयेंगे और सिवानी फीडर का पानी रिस्टोर किया जायेगा। पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी को उस कैपेसिटी को रिस्टोर किया जायेगा और लोग वहीं पानी पायेंगे तभी उन लोगों को उनका हक मिलेगा। आज जो दिक्कत हो रही है तभी वह दिक्कत खत्म हो सकती है। आज उस पानी की कमी की वजह से मेरे इलाके में यह डिमाण्ड हो रही है कि नेशनल माईनर बनाया जाये या नेशनल चैनल बनाये जायें ताकि वे भाखड़ा सिस्टम से पानी ले सकें। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से गुजारिश करता हूं कि मेरे इलाके के किलाणा माईनर की पी०एल०सी० की ऑफटेक की बहुत सख्त जरूरत है। मैं इस बारे में 2-3 बार सरकार से गुजारिश करता आया हूं लेकिन अभी तक कोई निर्णायक कदम नहीं उठाये गये हैं। न्यू लाडवा माईनर की डिमाण्ड उभर कर आई है क्योंकि पिछले काफी दिनों से पानी की भारी किल्लत है। डाटा में बहुत पुरानी गऊशाल है। मौठ माईनर की एक्सटैंशन की मांग एक कलैस्टर ऑफ विलेजिज से आ रही है। पानी की कमी के कारण वहां पर गऊएं पानी के लिए तरसती हैं। यदि मौठ माईनर की एक्सटैंशन हो जाती है तो मैं समझता हूं कि जहां गऊओं को पानी मिलेगा उस कलैस्टर ऑफ विलेजिज के लोगों को पीने के पानी के लिए राहत मिलेगी। स्पीकर सर, भाजद, भाठला और सिसाय, काली रावण के बीच का एक पैच पानी की कमी के कारण जूझ रहा है। इस इलाके की मेन मांग हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय इरीगेशन मिनिस्टर जिनका मैंने कई बार इस बारे में लिखकर भी भेजा है इसके लिए कोई न कोई अच्छा प्रावधान करेंगे तो हमारे इलाके को उससे बड़ा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से मैं उनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि खोखा, भाटला, कुलाणा, खरड़ गांवों के बीच का एक

पैच ऐसा है अगर नई स्कीम देकर उसको प्रोपरली कमाण्ड किया जा सकता है इससे जो विशेष दिक्कतें हैं उनको मैं हाईलाईट इसलिए करना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि एक साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि किसानों को पूरा पानी देने के लिए और उनके खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए और सिंचित करने के लिए एक एनाउंसमैंट की थी और वाटर कोर्सिज की रिपेयर और रिमॉडलिंग की अनाउंसमैंट भी की गई थी। इस साल के जो बजट अनुमान हैं उनमें इसके लिए 32 से 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन यह पैसा तो पिछले जो बैलेंस काम चल रहे हैं उनको पूरा करने के लिए शायद ही पूरा हो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहूंगा कि 200-250 करोड़ रुपये का प्रावधान वाटर कोर्सिज की रिपेयर और रिमाडलिंग के लिए और किया जाए ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अनाउंसमैंट थी वह हम पूरी कर पाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि अधिकारियों की वर्किंग परफोरमैंस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर जी बैठे हैं और सभी विभागों के वज़ीर इस हाउस में होते हैं और आप जानते हैं कि स्कूलों की पढ़ाई का जो वातावरण है उसके ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मास्टर सालों साल तनख्वाहें लेकर चले जाते हैं। मास्टर अपनी मर्जी से प्रयास करते हैं और विधायकों के ऊपर दबाव डालते हैं और मर्जी का पोस्टिंग स्टेशन लेने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसी पोलिसी ले डाउन हो जिसमें टीचर का जो रिजल्ट हो उसको ठीक दृष्टि से आंका जाए। नकल पर कंट्रोल किया जाए। हमारे ग्रामीण इलाकों में विशेष तौर से जो दिक्कत है कि हमारे बच्चे मैट्रिक और 10+2 की डिग्री लेने के बाद नौकरी के लिए जाते हैं तो उनको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है और उसमें उनको बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनको जो वातावरण मिलना चाहिए था और जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वह टीचर्स के नॉन वर्किंग एटीच्यूड की वजह से नहीं मिल पाती। अध्यक्ष महोदय, मैं एक गुजारिश और करना चाहूंगा, टैक्नीकल एजुकेशन डिपार्टमैंट मेरे पास रहा है और मुझे इसका अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने उस वक्त रूरल पोलिटैक्नीक के नाम से शोर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की थी। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि देहात के प्रवेश में जो बच्चा जन्मता है, पलता है उसके बीच में और अर्बन एरिया में पलने वाले बच्चे के बीच में संसाधनों का फर्क होता है, उनको गाइडलाइंनस देने वालों में फर्क होता है। उसको एंट्रैंस टैस्ट फेस करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जो टैक्नीकल एजूकेशन है उसको जॉब आरियंटिड करने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार ने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीच्यूटस खोलने का प्रावधान किया है, काफी लिब्रेलाइजेशन भी किया गया है। काफी प्राइवेट इंस्टीच्यूटस भी खोले गए हैं लेकिन उसके बावजूद शोर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सिज के लिए हमें रूरल टैक्नीकल एजुकेशन सैंटर की पुनः स्थापना करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं कह पाया। जो कही जानी जरूरी थी। मैं समझता हूं कि जब आप डिमांडस पर बोलने का मौका देंगे तो मैं अपनी सारी बातें करने का प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि गवर्नर एड्रैस पर 5 दिन तक बहस हुई और तकरीबन 38 ऑनरेबल मैम्बर्ज ने उसमें पार्टिसिपेट किया और तकरीबन 776 मिनट उसमें लगे। इसी तरह बजट डिस्कशन में तकरीबन 36 मैम्बर्ज ने हिस्सा लिया और 612 मिनट के करीब लगे। ऑनरेबल मैम्बर्ज ने अपने अपने विचार रखें इस बात को मैं समझता हूं कि बहुत से मैम्बर्ज अपने विचार रखना चाहते थे और लम्बा भी बोलना

चाहते थे but I am sorry, I could not give ample time to the members. अब डिमांडस पर पूरा दिन है, एप्रोप्रिएशन बिल पर भी पूरा दिन है उस समय सभी मैम्बर्ज बोल सकते हैं Now, the Finance Minister will give reply on the budget estimates for the year 2008-2009.

वित्तमंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 2008-09 के बजट अनुमान 18 तारीख को इस सदन में पेश किए थे और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया था कि वे अपने अमूल्य सुझाव इसमें सुधार करने के लिए हमें दें। मैंने सभी माननीय सदस्यों से कहा था कि यदि वे अच्छे सुझाव बजट पर देंगे तो हमें खुशी होगी और हम उनके सुझावों पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे। स्पीकर सर, जैसा कि आपने बताया है दस घंटे से ज्यादा का समय माननीय सदस्यों ने बजट चर्चा पर लिया है इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि पहली बार ऐसा अवसर होगा कि आपने विपक्ष के सदस्यों को लगभग-लगभग डेढ़ घंटे का समय बजट पर चर्चा करने के लिए दिया और दो सदस्यों वाली बी०जे०पी० पार्टी के सदस्यों को भी 70 मिनट का समय बजट पर चर्चा करने के लिए दिया। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि जितना समय माननीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने के लिए दिया उसमें कोई ठोस सुझाव हमारे पास नहीं आये, जिनका मैं जवाब देता। अध्यक्ष महोदय, एक बात जरूर है कि मेरे जवाब के दो पहलू बनते हैं। एक राजनैतिक पहलू जिस पर विपक्ष के साथियों ने ज्यादातर समय लिया और दूसरा बजट से संबंधित बातें जिनका जिक्र कुछ माननीय सदस्यों ने किया है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि आपने कहा है कि कल भी डिमांडज पर माननीय सदस्य अपने-अपने विचार रखेंगे। वह ऐसा समय है जिस पर सभी सदस्य किसी विभाग की समस्या के बारे में या अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं के बारे में खुलकर चर्चा कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बजट हमारी सरकार का चौथा बजट है। अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री चिदम्बरम जी ने 14 तारीख को लोक सभा में बजट पर आम बहस में बीच में बोलते हुए एग्रीकल्चर सैक्टर के बारे में कहा था कि जो ग्रोथ रेट यू०पी०ए० सरकार में 8.8 प्रतिशत है अगर यही ग्रोथ रेट एक दशक तक रहे तो 5 हजार साल पुरानी गरीबी की जो गुरबत का अभिशाप लोगों पर है वह वाईप आऊट हो सकता है, खत्म हो सकता है। स्पीकर सर, आपको जानकर खुशी होगी कि जहां देश का आर्थिक विकास 8.8 प्रतिशत है वहीं हरियाणा का ग्रोथ रेट पिछले तीन साल के दौरान 10 प्रतिशत, 11 प्रतिशत और 11 प्रतिशत से भी अधिक 11.2 प्रतिशत रहा है। इसका जिक्र वित्तमंत्री भारत सरकार ने भी किया है। स्पीकर सर, मैं यह दावा कर सकता हूं कि यदि इसी तरीके का आर्थिक विकास हमारे प्रदेश का रहे जहां देश के वित्तमंत्री एक दशक की बात कर रहे हैं मैं कह सकता हूं कि हरियाणा से गरीबी 6-7 साल में खत्म हो सकती है। इसके लिए हमने प्रयास किए हैं और हमारे प्रयासों की सराहना भी की जा रही है। हमारी सरकार की सराहना कई अखबारों में भी की गई है 20 मार्च के ट्रिब्यून के अडीटोरियल में लिखा है कि—

> "Unlike Punjab and Himachal Pradesh, where the political leadership resorts to populism, avoids tax hikes and squanders resources on a bloated administration, Haryana has better managed its finances. There are no giveaways like free power or atta-dal gimmicks. Comfortably placed Finance Minister Birender Singh has presented a Rs. 3.80 crore surplus budget for 2008-09 and met the targets of the Fiscal Responsibility Budget Management Act ahead of

schedule. Thanks to its proximity to Delhi. Haryana's revenue has more than doubled--Rs. 900 crore, it has reached Rs. 21,695 crore--in three years." स्पीकर सर, इस प्रकार से जो मैंने कहा कि तीन साल के समय में हमारी सरकार की जो आमदनी थी वह हमारे 2008-09 के बजट अनुमानों के मुताबिक बढ़ी है। स्पीकर सर, मैं यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहता। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर न्यूज़ पेपर ने, हर समाचार पत्र ने कोशिश की है कि हमारे बजट को पंजाब के बजट के साथ कम्पेयर किया जाये। स्पीकर सर, पंजाब साईज़ में भी हमसे बड़ा है। पंजाब की इकोनॉमी को अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में भी वह हमसे बहुत आगे रही है। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं कि जब 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ और पहला बजट आया तो उस समय टोटल टैक्स कलैक्शन 16 करोड़ रुपये थी और आज हम उसी टैक्स कलैक्शन को 10 हजार करोड़ रुपये पर लेकर आये हैं। स्पीकर सर, एक अजीत अखबार है जो पंजाब से निकलता है और पंजाबी में छपता हैं उसमें पंजाबी में लिखा है वैसे तो मैंने उसका हिन्दी अनुवाद भी किया है लेकिन मैं आपको उसे पंजाबी में ही पढ़कर सुनाता हूं। यह मैं इसलिए सुना रहा हूं कि परसों पंजाब के वित्त मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी ने यह कहा कि अगर गुड़गांव को निकाल दिया जाये तो हरियाणा बिहार जैसा राज्य है उसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। मैं 'अजीत' अखबार द्वारा की गई टिप्पणी को आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है कि 'दोनों राज्यों के बजटों का जायज़ा।' हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया। मैं इसको पंजाबी में ही पढ़कर सुनाऊंगा। मोटे तौर ते नज़र मारयों इह कौड़ी हकीकत सामने आंदी है कि पंजाब नालों हरियाणे दी माली हालत काफी चंगी है। हरियाणा विकास दी बढ़ी माली आमदनी, प्रति जीव आमदनी, करां दी वसूली, वित्तीय घाटे दी दर आते अगले साल लईं रखे टीचियां (Targets) नू तोलया जाये ता हरियाणा दा पलड़ा भारी दिखदा है। (विघ्न) जित्थे एक पासे पंजाब विधान सभा विच्च सरदार मनप्रीत सिंह बादल कोई नवें कदम चुक्कण पखों अपनी बेबसी ज़ाहिर करदे रहे उत्थे बीरेन्द्र सिंह ने खुलकर अपने विकास दे नज़रिए, स्कीमां अते रियायतां दे रूप विच्च बजट पेश कीता। जिस तों ए प्रभाव बणदा सी कि खजाने अते ब्यौंतबंदी (Fiscal Management) दी लगाम वाकई उन्हां दे हथां विच्च है। स्पीकर सर, यह इसलिए भी है क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं इतना कहता रहता था कि यह नहीं हो सकता कि आप एक्साईज़ और टैक्सेशन दोनों ही विभाग किसी दूसरे मंत्री को दें। मैंने इनको कहा कि इनमें एक्साईज़ तो बेशक आप किसी दूसरे मंत्री को दे दो लेकिन टैक्सेशन को आपको वित्त मंत्री के पास ही रखना होगा क्योंकि देश के 80 प्रतिशत राज्य ऐसे हैं जिन में Taxation is supposed to be with the Finance Minister तो इन्होंने यह फैसला लिया। कई बार मैं मीटिंग्स में जाता और मैं जब फाइनैंस मिनिस्टर की मीटिंग्स करता तो मैं उनको खुलकर यह कहता था कि Don't treat me as full-fledged Finance Minister. I am Minister for expenditure. लेकिन पिछले 7-8 महीने से जब से यह फैसला लिया गया तो तब से हमने एक नई पद्धति कायम की। यह सिर्फ मैं अपने इनेलो के साथियों को अपने और मुख्यमंत्री के बीच की बात बता रहा हूं। मैं उनसे भी इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं और इस बारे में मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रजातांत्रिक प्रणाली का बेसिक कंसैप्ट यह है कि लोगों का शासन, लोगों द्वारा तथा लोगों के लिए

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

शासन और उसमें जो इंडायरैक्ट पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी है वह थ्रू रिप्रैजैंटेटिव है। थ्रू रिप्रैजैंटेटिव इसलिए है कि हमारे देश का साईज बहुत बड़ा है वर्ना स्विटजरलैंड जैसा देश भी है जहाँ पर डायरैक्ट डैमोक्रेसी है। जहाँ लोग सुबह, दोपहर या शाम को अपने आप फैसले करते हैं वह भी किसी कॉफी हाउस में बैठकर या कहीं पार्कों में बैठकर। वे कानून बनाते हैं, वे निर्णय लेते हैं लेकिन अपने देश में जिसकी 110 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या हो और उसमें 28/29 राज्य हों। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं ने डॉ० भीमराव अम्बेडकर जी ने यह समझा कि यहाँ पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी हो, लोगों के नुमाइंदे हों, लोगों द्वारा चुने हुए हों लेकिन अध्यक्ष महोदय, बदकिस्मती यह है कि जब हम चुनकर आ जाते हैं तो लोगों को कहते हैं कि तुम तो अगले 5 साल के बाद मिलना। हम फिर कोई नया रूप लेकर आयेंगे। हम फिर कोई नई राजनीति की शतरंज बिछायेंगे, हम नया झांसा देने के लिए आयेंगे। फिर कोई नया झूठ बोलने का सिलसिला शुरू करेंगे और झूठ भी वह जिस पर पूरी रिसर्च हुई हो कि वह सच में परिवर्तित हो जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र में अगर हम लोगों से बेरुखी कर लेंगे, उनसे मुंह मोड़ लेंगे तो हम सबसे बड़ा धोखा उन लोगों के साथ करते हैं जो हमारे को अपना प्रतिनिधि बनाकर किसी विधान सभा में या लोकसभा में भेजते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी समझता हूँ कि अगर प्रजातांत्रिक ढांचे में हम रहते हैं तभी विकास की बात हम सोच सकते हैं और विकास तभी सम्भव है जब डैमोक्रेसी को हम, उसकी जो बैस्ट परिभाषा है, उसमें ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, यह लिखा है कि--

"There is a close linage between democracy and the development. There are synonyms. Nowadays, national and regional markets are developing much faster and more strongly than anywhere and the capital, technical, industrial and commercial labour have moved from one region to the other region across the subordinating diversities."

सर, यह भी लिखा है कि इस सारे डिवैल्पमैंट के सिलसिले में अगर प्रोसपैरिटी जिसको हम सम्पन्नता कहते हैं that is combined with unequal distribution, चाहे कुछ लोग ही धनी बन जायें और वे भी डैमोक्रेसी के माध्यम से then prosperity combined with unequal distribution of wealth will be a challenge for the harmonious relationship in the society. जो समाज का हमारा ताना-बाना है वह खत्म हो सकता है और इसलिए हम जनप्रतिनिधियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए वे लिखते हैं कि—

"Under such circumstances, people representatives need to be more responsible and they should be more fair and to work as per the expectation of their electors. Irresponsible behaviour on the floor of the House by some other Members during the Session is a glaring example of betraying the faith of the people and the voters. Valuable time of the assemblies wasted by way of slogans and disturbances in the representative houses, it is rather very painful and a blot on the fair name of representative democrary. We need some retrospection."

जैसे इन्दौरा जी शुरू हो जाते हैं। हमें आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं यह बात सिर्फ अपने विपक्ष के सदस्यों को ही नहीं कहता मैं अपने सदस्यों को भी

कहता हूँ कि हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारी साथी रामकुमार गौतम जो मेरे साथ पढ़े हैं, जब इन्होंने पहली बार मुझे हाउस में बोलते हुए सुना तो ये कहने लगे कि अरे बीरेन्द्र तू तो बोलता भी बहुत अच्छा है। मैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि जब मैं उनका सहयोगी और साथी होते हुए अच्छा बोलने लग गया तो उनको कुछ न कुछ तो मेरे से भी ग्रहण करना चाहिए।

मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि बजट पर अगर 70 मिनट भाषण देते हैं तो उसमें से 50 मिनट ऐसी बातें होती हैं जिनका बजट से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। मैं केवल विपक्ष के साथियों से ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूं और उनके इस व्यवहार की नखेदी करता हूं उनका क्रिटिसिज्म करता हूं क्योंकि ये हमारी मर्यादाएं नहीं हैं। स्पीकर सर, हमारी मर्यादा यह है कि जिन लोगों के लिए हमने सपने संजोये थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए हम सदन में आये थे उन लोगों के लिए कुछ करके दिखाएंगे और उनके जीवनस्तर को ऊंचा उठाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम हरियाणा के लोगों के साथ राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। स्पीकर सर, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि पिछले 40 साल जब से हरियाणा प्रदेश बना है तबसे हमारी यह कोशिश रही है हमारी पार्टी की कोशिश रही है कि लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। चीफ मिनिस्टर कोई भी बना हो लेकिन सरकार के अन्दर विजन की कमी रही है। अगर सरकार 20 साल आगे की नहीं सोच सकती है तो वह जनता का भला नहीं कर सकती है। अगर पांच साल का राज करना है तो बगैर बजट पास किये भी यह हो सकता है, बजट में बगैर कोई कोमा या इन्वर्टिड कोमा बदले भी बजट को उसी पद्धति से पास कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने बजट को एक नया रूप दिया है। स्पीकर सर, जैसा मैंने कहा है कि अगर आप सब का सहयोग हो तो हरियाणा के अन्दर जो बिलो पावर्टी लाईन के लोग हैं जिन को बी०पी०एल० बोलते हैं और जिनको खुश करने के लिए हमारे ये साथी भी आज हमारे विरूद्ध जलूस निकालते हैं और प्रदर्शन करते हैं। केवल ये लोग ही नहीं हम लोग भी इस बात से बड़े चिन्तित रहते हैं हमारा कोई भी गरीब भाई इससे छूट न जाए लेकिन हमारी समझ का ढांचा ऐसा बन चुका है कि अगर इस बी०पी०एल० में कोई तगड़ा आदमी आ गया है जिसके घर के सामने ट्रैक्टर खड़ा है लेकिन वह बी०पी०एल० में आ गया। आपके राज में बी०पी०एल० का कार्ड बनवाने में कोई दिक्कत नहीं आई है लेकिन अगर उस तगड़े आदमी का नाम बी०पी०एल० से कटवाना हो तो उसके लिए कोई साहस नहीं करता। स्पीकर सर, हमें गरीब जनता में यह साहस पैदा करना है कि जो उसका हक है वह सिर्फ उन्हीं के लिए है और अगर कोई उनका हक छीनता है तो उनमें इतना माद्दा होना चाहिए कि वे उसके खिलाफ खड़े हो कर बोल सकें कि साहब यह गलत है। इस पद्धति को कायम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी एक नई सोच है कि हमारे समाज के जो गरीब भाई हैं जो बी०पी०एल० में कवर होते हैं उनके अन्दर एक जज्बा पैदा कर सकें। स्पीकर सर, इस बजट के माध्यम से हमने यह करके दिखाया है। मैं विजन और दूरदृष्टि की बात इस लिए कर रहा हूं कि मेहरबानी करके लोगों में जो खोखले नारे हैं उन नारों से जनता को गुमराह करके हम जनता के उस वर्ग के साथ धोखा करते हैं जैसे कि चौटाला साहब के समय में हुआ। स्पीकर सर, मैं कई बार दिल्ली से गाड़ी में बैठ कर आता हूं तो कई तरह की बातें सुनते हैं। इसमें इनका भी कोई दोष नहीं होता लेकिन जो इनके स्तुतिकार हैं उनको मैं दोष देता हूं जिन्होंने यह नारा दिया कि 'चौटाला नहीं यह तो आंधी है यह दूसरा महात्मा गांधी है' है और अब तीसरा महात्मा गांधी भी हो रहा है उनके स्तुतिकार भी कहते हैं कि यह कुलदीप बिश्नोई नहीं यह तो महात्मा गांधी है। स्पीकर सर, मेरे कहने का

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

अभिप्राय यह है कि महात्मा गांधी के मुकाबले में पहुंचने की चेष्टा करना किसी भी राजनेता की भूल है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक आदर्श कायम किया था और उन्होंने कभी कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं किया था। आज अगर हम कहें कि मुख्य मन्त्री के तौर पर एक विजनरी मुख्य मन्त्री है तो वह गलत नहीं होगा। अगर पूर्व मुख्य मन्त्री पथ-प्रदर्शक होते हैं तो हम उस नारे की सराहना करते लेकिन उनके स्तुतिकारों की वजह से ही हाउस में ऐसा माहौल पैदा हुआ। जिस तरह से हाउस में हुआ है कि वे लोग दूसरे साथियों की तरफ एसॉल्ट करने के लिए गए। उनके अपने मन में ऐसा कुछ नहीं था लेकिन क्योंकि उनके लीडर ऑफ दि पार्टी मौजूद थे उनको खुश करने के लिए यह बात की गई। स्पीकर सर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इससे डैमोक्रेसी मजबूत नहीं होती। अगर आपका भाषण सत्यता पर आधारित हो तो आप निज़ाम को बदल सकते हैं, सब कुछ बदला जा सकता है लेकिन उनके जो स्तुतिकार हैं जो चाटुकार हैं, वे तुलना में उस हद तक पहुंच जाते हैं जिस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर कोई जाट मुख्य मन्त्री बन जाए तो भी वे पूरी तरह से उनके चाटुकार बन जाते हैं जैसे अब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी मुख्य मन्त्री हैं और इनसे पहले चौटाला साहब मुख्य मन्त्री थे और उनसे पहले भी दूसरे मुख्य मन्त्री थे, उनके सत्ता में आने के छः महीने के बाद उनके चाटुकार साथी हैं वे कहने लगेंगे कि अब तो आप सर छोटू राम के मुकाबले पर पहुंच गए हैं। अपना नाम पत्थरों पर लिखवाने से लोग आपको याद करें, ऐसा नहीं होता। अपने नाम से अपनी पहचान हो, यह जरूरी है। स्पीकर सर, राजनीतिक तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि हमारी पार्टी ने जो राजनीतिक मान्यताएं रखी हैं उन पर हमने चलने की कोशिश की है। मैं यह नहीं कहता कि हम उन पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम यह चाहते हैं कि हरियाणा के हर नागरिक को आजादी से सांस लेने की इजाजत है, ऐसा उसे महसूस हो। वह यह सोचे कि मुझ पर किसी किस्म का दबाव नहीं है, जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे उनको अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना अपना धर्म है। पिछले शासन में उस राज धर्म की धज्जियां उड़ाई गईं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज भी हमारे साथ भी लोग ऐसे करते हैं। कोई हमारा वर्कर आकर अपना मोबाइल फोन मिलाकर यह कहता है कि करिये जी डी०सी० से बात, करिये जी एस०पी० से बात। यह बात कहां से प्रचलित हुई। जब पार्टी के उस समय के राज के कार्यकर्ताओं ने स्टेट पार्टी का टोटली इरोजन कर दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते जो फैसला होगा, जो कुछ होगा ऊपर से ही होगा। हमने अपने जो अधिकारी हैं उनमें एक नया विश्वास पैदा किया। हम कोई ऐसा काम आपसे नहीं कहेंगे जो आपके अधिकारों से परे हो या जो आपकी नजरों में गलत हो। हमने वह विश्वास पैदा किया है। आज भी मैं यह कह सकता हूं कि हरियाणा का बजट तीन साल में 9.5 हजार करोड़ से 21 हजार करोड़ का होने की बात है। हमारी जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कुछ तो ऐसा होगा। आज हमारे पड़ौसी प्रदेश पंजाब के हालात क्या हैं। पंजाब के इस बार के भी और पिछले राज के भी वित्त मंत्री ने मुझे कहा कि अगर हमें अपने पांव पर खड़े होना है तो हमें इस साल 10 हजार करोड़ रुपया जनरेट करना पड़ेगा। आप हमारे को कुछ उधार दे दो। कांग्रेस की सरकार के समय में वित्त मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंगला था उन्होंने कहा था तो हमने कहा कि हमारी कैपेसिटी 500 से एक हजार करोड़ रुपया देने की है लेकिन अगर भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहे तो हम देने के लिए तैयार हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि पंजाब की नौकरशाही जो थी उसकी लगाम जब उग्रवाद भयानक रूप लिए हुए था तब खुली रही, उसकी

वजह से यह कमी आई। जो सिस्टम में गिरावट आई उसी का नतीजा है वरना तो आप जानते हैं कि पंजाब के अकेले लुधियाना शहर में 200 मर्सिडीज गाड़ियां हैं। सारे देश में तकरीबन 2 हजार मर्सिडीज गाड़ियां होंगी और अकेले लुधियाना में 200 गाड़ियां हैं। आप अंदाजा लगाएं कि पंजाब का अकेला शहर इतना अमीर हो सकता है जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरे हरियाणा में भी शायद 50 गाड़ियां नहीं होंगी। आज भी जो लोग यह कहते हैं कि पंजाब पीछे रह गया है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी जो कमिटमैंट है चाहे नौकरशाही की कमिटमैंट है चाले पौलिटिकल लीडरशिप की कमिटमैंट है। लीडर शिप अगर चाहे और यह फैसला कर ले कि वोट लेने के लिए आटा दाल स्कीम लागू करनी है। (विघ्न)

अति विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत

Mr. Speaker : Hon'ble members, Sardar Nirmal Singh Kalhon, Hon'ble Speaker, Punjab Vidhan Sabha is present in the V.I.P. Gallery to witness the proceedings of the House. I on behalf of the House and myself welcome him.

वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानो पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : शुक्र है कि आपने स्पीकर महोदय का जिक्र कर दिया। अब मैं अपनी स्पीच को थोड़ा मोड़ भी देता हूं। मैं यह कह रहा था कि पंजाब में कमियां कहां से आईं कि आज उनको पैसे-पैसे के लिए अपनी बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। स्पीकर सर, पंजाब की एग्रीकल्चर इन्कम, पंजाब की इण्डस्ट्रियल इन्कम और पंजाब का सर्विस सैक्टर अगर इसको कम्पेयर किया जाये तो जहां हम one हैं they are at 1.6, हमारे से डयोढ़े से भी आगे हैं। लेकिन हमारी टैक्स कलैक्शन जयादा है। एक बार मैं इम्पावरड कमेटी की मीटिंग में गया तो इम्पावरड कमेटी के चेयरपर्सन जो वित्त मंत्री पश्चिम बंगाल हैं ने मुझसे पूछा कि आपके हरियाणा में वैट की कलैक्शन कितनी है? तो मैंने कहा, "This year we may touch 10,000 crore." Every member of that meeting was stunned to find out the figures. Then what they told me, "May you just reach at! Whether it is from all taxes or it is VAT alone?" I said, "It is from VAT and CST because CST is being phased out." Now, we are losing Rs. 1500 crores because of the reduction of the CST from 4% to 3% and this time it would be 2% only and still we are having more than 20% growth as fas as VAT is concerned. स्पीकर सर, यह बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि हमने इन चीजों के लिए प्रयास किये हैं ताकि हम इतने फण्ड जनरेट कर सकें। हमारे साथ चुने हुए लोगों की भावनाएं हैं लोगों ने हम पर विश्वास किया है ताकि हम उसको कायम रख सकें। स्पीकर सर, मैं यह बात आपसे कहना चाहूंगा कि इन सारी परिस्थितियों में हम आज उस जगह पर खड़े हैं जहां से हरियाणा प्रदेश लम्बे कदम भर सकता हैं। मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में हमारी जो ऐग्रीकल्चर की ग्रोथ थी जहां से हमने टेक ओवर किया वह नेशनल ग्रोथ 1.8 प्रतिशत थी जो बहुत ही डिसमल थी। बहुत से लोगों ने इस बारे में चिन्ता जाहिर की थी कि ऐग्रीकल्चर सैक्टर में अगर 4 प्रतिशत ग्रोथ को टच नहीं करेंगे तो ऐग्रीकल्चर क्राईसिस आयेगा और क्राईसिस आया और उस क्राईसिस की वजह से हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की। शुक्र है कि हरियाणा में और पंजाब में लोग फिर भी संघर्ष करते रहे। लेकिन महाराष्ट्र का क्षेत्र विदर्भ है और आन्ध्रप्रदेश जैसे जितने भी राज्य हैं जहां किसान इन्वेस्ट करके ऐग्रीकल्चर करते हैं वहां पर सैंकड़ों नहीं हजारों की संख्या

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

में किसानों ने आत्महत्याएं की। आन्ध्रप्रदेश में तो एक हजार नहीं तीन हजार से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। इस बात को भांपते हुए और देखते हुए हमने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जो पहले चण्डीगढ़ में हुआ उसके बाद नैनीताल में हुआ उसमें जितने कांग्रेस रूलिंग स्टेट थी उन्होंने यह बात कही कि आप मेहरबानी करके इस ऐग्रीकल्चर क्राईसिस को नहीं रोक सकोगे तो देश के अन्दर जो हमारा सैट-अप है जो ढांचा है वह चरमरा जायेगा और देश किसी भी दिशा में जा सकता है। मुझे यह बात अच्छी तरह से याद है और इसके लिए यू०पी०ए० की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गान्धी जी का मैं धन्यवाद भी करूंगा क्योंकि मैंने पर्सनली यह महसूस किया है। कहने वाले लोग तो अनेक बात करते थे कि यह तो विदेशी महिला है यह क्या समझती है वह अकेली एक नेता ऐसी है इस देश में जिसने 60 साल की आजादी के इतिहास में कांग्रेस मंच से किसान की वकालत जोरदार शब्दों में की। लोगों ने तो यहां तक भी कहा, 'She is open to conviction.' जब कुछ लोग उनसे मिलकर आये और यह कहा कि पांच एकड़ से काम नहीं चलेगा कुछ और सोचो उन्होंने 'ना' नहीं कही, उन्होंने कहा सोचा जा सकता है और ऐसा संभव हो सकता है। मुझे अच्छी तरह से याद है श्रीमती सोनिया गांधी ने नैनीताल में यह पूछा कि गेहूं की मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है और कहा कि किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। किसानों को लाभकारी मूल्य के लिए ही उसके बाद गेहूं का मूल्य एक हजार रुपये प्रति क्विंटल फिक्स हुआ। मुख्यमंत्री और हम जब भी सलाह करते थे, ये इस बात के पक्षधर रहे हैं मैं इस बात के लिए इनकी सराहना करता हूं। मैं यह कहता था कि ब्याज 12 परसैंट कर दें, 7 परसैंट कर दें या 6 या फिर 5 परसैंट कर दें लेकिन किसान खुश नहीं होगा। मैं यह कहता था कि किसान को बीज में सबसिडी दें, खाद में सबसिडी दें। खाद की सबसिडी के नाम पर इस देश में 40 हजार करोड़ रुपये से ऊपर अमाउंट जो किसान के खाते में लिखा जाता है वह उसको नहीं मिलता बल्कि यह सबसिडी उस कारखाने वाले को मिलती है जो उस खाद को बनाता है। जहां तक किसानों को डाइरेक्ट सबसिडी देने की बात है तो पी० चिदम्बरम ने पिछले साल के बजट स्पीच में कहा था कि इस सबसिडी का फायदा किसान को डाइरेक्ट मिलना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमने अब की बार 2800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पावर सैक्टर में ऐग्रीकल्चर में सबसिडी दे रहे हैं। एक टयूबवैल पर 53 हजार रुपये की सबसिडी हम किसान को देते रहे हैं। इस बात पर हम विचार करेंगे, हमने मुख्यमंत्री महोदय जी ने को भी कहा है, हमने महकमें के मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को भी और महकमें के सैक्रेटरी को भी कहा है कि यह नहीं चलेगा कि आप हर साल हमारे से 400 करोड़ 500 करोड़ बढ़ाकर लेते चले जाओ। हम किसान को कहेंगे कि जो उसे 53 हजार रुपये की टयूबवैल पर सबसिडी है उसमें से तू हमारे से 40 हजार रुपये ले ले और बिल अपने आप दे और जो बाकी बचे वह अपनी जेब में रख, हमें कोई मतलब नहीं ताकि हम हजारों करोड़ रुपये बचाएं और किसान के दिमाग में यह बात हो कि उसे टाइम पर बिजली का इस्तेमाल करना है, टाइम पर टयूबवैल चलाना है। इससे बिजली में जो कमी है उसमें सुधार लाया जा सकता है, इस प्रकार की हमारी भावना है। डा० मनमोहन सिंह जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, मैं कई बार कहता हूं कि अर्थशास्त्री का और किसान के लोन वेवर्स का जो मामला है यह आपस में अंतर्द्वंद्व है। अर्थशास्त्री पी० चिदम्बरम जी ने पिछली 29 तारीख को जो बजट पेश किया था उसमें उन्होंने किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के ऋण माफ किए जिसको कहते हैं कि काटा मारना, जिसको हरियाणवी भाषा में कहते हैं उतरम पातरम। उतरम पातरम की जब

घोषणा हुई उस दिन से लेकर आज तक ये लोग इलैक्ट्रोनिक्स मीडिया के थ्रू कहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। मैंने एक जगह कहा कि अगर किसान कोलैप्स होकर उठ सकता है तो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने से क्या। देश के 70 प्रतिशत लोगों को राहत मिल सकती है, 80 प्रतिशत किसान वर्ग को राहत मिल सकती है, मझले और स्मॉल फार्मरस को राहत मिल सकती है तो बैंकिंग सिस्टम क्या करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इस लिए कहा रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि--

> "Sheer size of our gesture shows our commitment to our farmers for our determination to improve their lot and our desire to see agriculture restored to its rightful place in the Indian economy."

सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस बात पर जो अर्थशास्त्री यह कहता है कि बैंकिंग सिस्टम कौलैप्स हो जाएगा खुद देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और देश के प्रधानमंत्री अपनी भाषा में उस बात को स्पोर्ट करते हैं जिसे हमने किया है। He says—

> "Our Government took the historic initiative to our farmers' loan on an unprecedented scale. The debt relief of this magnitude has never been conceived or admitted before. It is an income transfer of an unparrailed scale."

आगे कहते हैं कि--

> "If bankruptcy is permissible form of business outcome in industry, what is irrational amount of the waiver."

मैं रामकुमार गौतम जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी आपने जींद में रैली की थी। इनके नेता कहते हैं कि यदि उनकी सरकार आई तो किसानों को चार प्रतिशत ब्याज दर पर लोन देंगे और उन्होंने यह भी कहा कि हम कर्जे भी माफ करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सैंटर में पांच साल तक एन०डी०ए० की सरकार रही जिसके प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे। उन्होंने उस दौरान एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसानों का भला होता और आज ये रैली करके वादा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बार गलती से चौटाला जी कुरुक्षेत्र में वाजपेयी जी को लेकर आये थे। आगे पता नहीं ये ऐसी गलती दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे। कुरुक्षेत्र में देश के प्रधान मंत्री कहते हैं कि हमारे गेहूं और धान से गोदाम भर चुके हैं इसलिए सरकार गेहूं और धान की फसल नहीं खरीदेगी। मेहरबानी करके किसान फसल डाईवर्सीफिकेशन करें और दूसरी फसलें उगायें। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फूल उगाओ। अध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा यदि मेरा मकान कुरुक्षेत्र से दस कि०मी० की दूरी पर हो और मैं टुलीप लगाऊं या दूसरे फूलों की खेती करूं तथा डिब्बे बनाकर फूलों को टाटा-407 में लेकर बेचने के लिए दिल्ली जाऊं और दिल्ली में जाम लगा मिल जाये तो मैं फूलों की उपज की कमाई लाने की बजाय राख लेकर ही वापिस लौटूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बातें इमप्रक्टीकल बातें थी। कई बार किसान के नेता उनका साथ नहीं देते लेकिन भगवान साथ दे देता है। गौतम साहब, अगले साल देश में फसल नहीं हुई और पांच साल से जो गोदाम सरकार भरे हुए बताती थी वे एक साल में ही खाली हो गए तथा किसान की गेहूं और धान की फसल बिक गई। अध्यक्ष महोदय, अब हमारा किसान समझ गया है, नाटक से काम नहीं चलेगा। हमने करके दिखाया है, हमने कोई वादा नहीं किया था कि हम बिजली के बिल माफ करेंगे लेकिन हमने 1600 करोड़ रुपये के किसानों के बिजली के बिल माफ किए हैं।

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

अध्यक्ष महोदय, अब हमारे सामने किसान एजीटेशन करते हैं कि हमारी जमीन के भाव 1.50 करोड़ रुपये होना चाहिए। हम उनसे पूछते हैं कि यदि वही किसान चौटाला जी के समय में तीन साल पहले एजीटेशन करते तो क्या कहते कि हमारी जमीन का भाव 10 से 15 लाख रुपये प्रति एकड़ होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह हमने करके दिखाया है कि आज किसान अपनी जमीन का प्रति एकड़ के हिसाब से डेढ़ से दो करोड़ रुपये की मांग कर रहा है। हमने प्रदेश में फ्लोर रेट तय किए हैं और जिस जमीन में एक दाना भी अनाज का सैंकड़ों साल से पैदा नहीं हुआ होगा यदि उस जमीन का भी अधिग्रहण किया जायेगा तो 10.40 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा। उसके अतिरिक्त 33 साल तक 15000 हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से रॉयल्टी भी प्रति एकड़ के हिसाब से दी जायेगी और रॉयल्टी में प्रति वर्ष 500 रुपये की बढ़ौतरी भी होगी। अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रावधान इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो बात आज कही है वह बात दीनबंधू सर छोटू राम ने 70-75 साल पहले कही थी। दीनबंधु सर छोटू राम मेरे प्रवर्तक हैं। दीनबंधु सर छोटू राम जी कभी प्रधान मंत्री नहीं रहे, कभी डिप्टी प्राईम मिनिस्टर नहीं रहे और न ही कभी मुख्यमंत्री रहे लेकिन आज भी लोग उनको श्रद्धा से याद करते हैं। कुछ तो काम उन्होंने किसानों के लिए किए होंगे यही कारण है कि किसान वर्ग आज भी उनको मानता है यह बात पंजाब से बी०जे०पी० के एम०पी० श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस दिन वेवर ऑफ लोन वाली स्कीम आई थी उस दिन कही थी कि 1938 का कानून फिर से लागू होना चाहिए। श्री चिदम्बरम ने भी यह बात कही। Chidambaram may not be knowing Sir Chottu Ram but he knew C. Raja Gopalacharaya. C. Raja Gopalacharaya introduced the same legislation in 1938 which was implemented and introduced and passed by Sir Chootu Ram. So Sir, what I say, in 1935, in the Punjab Legislative Council, Sir Chottu Ram said, "the whole economic fabric of the province depends upon the prosperity of the deter classes which form a portion of 19% of the population of the whole provinces. If this class perishes economically, I think any other section of the population will have ultimately to perish", और यही बात देश के प्रधान मंत्री जी ने अब 70-75 साल बाद कही है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि यह स्टेज क्यों आई इसकी वजह है।मेरे पास 1983 से 1994-95 के एक दशक के आंकड़े हैं। जब देश में कृषि की विकास दर 4.86 प्रतिशत थी और 1995 से 2005 तक का जो दशक है जिसमें हमारे इनेलो के साथी भी सत्ता में रहे और दूसरे लोग भी सत्ता में रहे। मैं सिर्फ हरियाणा की बात कर रहा हूं उस दौरान कृषि की विकास दर जो 1995 में 4.86 प्रतिशत थी वह 2005 में आकर 1.76 प्रतिशत रह गई। स्पीकर सर, इस तरह की जब स्थिति होगी तो किसान क्या करेगा। तो किसान ने बैंकों से भी अपने आपको एग्जास्ट कर लिया। जिस भी बैंक से जो भी मिला ट्रैक्टर के नाम पर, घोड़ी के नाम पर, खाले पक्के करने के नाम पर, मुर्गी के नाम पर या सुअर के नाम पर उसने लोन लेने की पूरी कोशिश की कि कहीं से तो मैं अपना गुजारा चलाऊं। उसके बाद जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर उसने क्रेडिट कार्ड लेना भी शुरू कर दिया। इस बारे में किसी ने उसको बता दिया होगा कि क्रेडिट कार्ड से भी 70-75 हजार रुपये मिल सकते हैं। तो उसने उसका इस्तेमाल किया और इस प्रकार से आखिर में उसे अपने आढ़ती की शरण लेनी पड़ी। आज मेरे दोस्त श्री विनोद शर्मा जी यहां पर नहीं बैठे हैं। विनोद शर्मा जी आज से 7 दिन पहले इस बारे में मुझे बता रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि पंजाब में तो यह सिस्टम है कि किसान की बेटी की अगर शादी

हो तो वह सीधे आढ़ती के पास जाता है और आढ़ती से कहता है कि लाला जी मेरे को लड़की की शादी करनी है पैसा दे दो। इस पर आढ़ती उसे कहता है कि पैसे दी कोई लोड नहीं तूं मैंनू ए गल दस कि तैनू केहड़ी-केहड़ी चीजां लैणी हैं। इस पर वह लिखवाता है कि फ्रिज भी चाहिए, मोटर साईकिल भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, सोफा भी चाहिए, टेबल भी चाहिए इस प्रकार से सारी लिस्ट बताकर वह आढ़ती को दे देता है और फिर खुद आढ़ती टैलिफोन करता है कि यह सारा सामान मेरे ज़मीदार का है इसे आप तैयार करें भिजवा दें और उसके जितने भी पैसे बने वे तुम मेरे से ले जाना। तो जो आढ़ती इतना दयालु होगा वह कितना ब्याज लगाता होगा और जो मैनुफैक्चरर है जिसके पास से वह यह सारा सामान उस किसान को भिजवाता है उससे वह कितना कमीशन खाता होगा यह तो भगवान ही जानता है। स्पीकर सर, इस प्रकार से इस तरह की एक व्यापक स्थिति अपने देश में है और इस बारे में तब चिंता उठी जब केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री पी०चिदम्बरम ने 60 हज़ार करोड़ रुपये के लोन माफ करने की बात कही। उसी दिन से यह एक नई चिन्ता लोगों के सामने आई कि आढ़तियों से और मनीलैंडर्स से जिन्होंने पैसे ले रखे हैं उनका क्या होगा। स्पीकर सर, यह एक बहुत विकट स्थिति है। इस बारे में मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बताकर किसान की व्यथा रखना चाहता हूं। यह दो साल पहले की बात है। मेरी अपनी कांस्टीच्युएंशी में एक गांव है उस गांव में मेरा एक वर्कर है उसने मुझे कहा कि इस बार मैं अपनी फसल आढ़ती को नहीं देकर आया। वह नरवाना में अपने आढ़ती के पास फसल बेचने नहीं गया बल्कि वह बरवाला गया अपनी फसल बेचने के लिए। तो इस पर मैंने उससे कहा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि मुझे अपने आढ़ती का 6 लाख रुपया देना है और इस बार मेरे पास 60 हजार रुपये की गेहूं थी और अगर 60 हजार की गेहूं मैं उसको बेच आता तो वह 60 के 60 हजार अपने पास रख लेता लेकिन फिर भी 5 लाख 40 हजार मेरे ऊपर उसका कर्ज़ रह जाता। तो इसलिए मैंने तो रास्ता ही बदल लिया। Speaker Sir, this is a grave situation. यह ऐसी स्थिति क्यों है? यह सब उसी दिन से हो रहा है जैसी मेरे साथी विनोद शर्मा जी ने बताई है। आज बैंकिंग सिस्टम क्या है। बैंकिंग सिस्टम में इन चीजों के लिए लोन नहीं है। जिस तरीके के लोन बैंकिंग सिस्टम ने किसानों को दिये हैं उससे फायदा भी हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि उससे फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज उसको किसान के लिए ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि जैसे चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने कहा कि वह जाये और जिस भी किस्म की उसको जरूरत हो उसके लिए वह पैसा ले और उसको वह पैसा मिले और जब उसके पास जमा कराने के लिए पैसा हो तो वह जमा करवाये। लेकिन आज ऐसा नहीं है। बैंकिंग सिस्टम में 18 प्रतिशत जो एडवांसमैंट है, लोनिंग है वे कहते हैं कि it should go to the priority sector. Speaker Sir, I know what priority sector is. Priority sector doesn't include only agriculture. It includes small scale industries and other allied activities and out of that 18 per cent maturity of the shares goes to that section that may be small industries or may other activities. They don't prepare Kisan to be their borrower. क्योंकि वे उस पर यकीन नहीं करते। जैसा कि श्री करण सिंह दलाल जी ने कहा कि जब वे लोन लेने के लिए मॉर्टगेज कराते हैं तो स्टॅम्प

13.00 बजे

ड्यूटी लगती है। Sir, this provision does not exist, if big industrialists take loan. Shri Vinod Sharma narrated one of the interesting facts and these facts are corroborating of my thinking also. Sir four years back, Shri Jaswant Singh was the Finance Minister of India and he moved a resolution in the Parliament that 1,10,000/- crores of rupees, which he said that this is non-performing assets, they should be

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

waived off. अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार की मैं बात कर रहा था जो किसान हितैषी बनते थे और ये लोग भी उस समय उनको स्पोर्ट करते थे। उन्होंने उद्योगपतियों के लिए तो 1 लाख दस हजार करोड़ रुपये की बात की लेकिन उस गरीब किसान की बात नहीं की जो कर्जे में दबा हुआ है। उसके बाद कांग्रेस ने उनकी बात की जो कांग्रेस ने यह कर दिखाया। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं कह रहा था कि 4 करोड़ लोग उससे लाभान्वित होंगे। उसमें 10 हजार करोड़ के लोन तो उन लोगों के भी माफ होंगे जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है। अध्यक्ष महोदय, इस सारी समस्या का समाधान जब तक हम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके तीन समाधान हैं। एक तो यह कि किसान को मिनिमम स्पोर्ट प्राईस की बजाय उसको लाभकारी मूल्य मिले। लाभकारी मूल्य का मतलब है कि अगर किसान का गेहूं पर एक हजार रुपये प्रति क्विंटल का खर्चा आता है तो उसको 1300-1400 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिलना चाहिए तब ही हम उसको लाभकारी मूल्य कह सकते हैं। दूसरी बात है कि किसान को डायरैक्ट सब्सिडी मिलनी चाहिए अगर उसको इनडायरैक्ट सब्सिडी मिलेगी तो उसका मिसयूज होगा और तीसरी बात यह है कि गरीब आदमी को अगर चिदम्बरम जी एक दशक में पूरी छलांग लगाने की बात करते हैं और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार 6-7 साल में वह छलांग लगाने की बात करती है तो गरीब आदमी को एक ऐसा जम्प देना होगा कि वह आगे वाली कतार में खड़ा हो जाये। फिर उसकी अपनी विशेषता पर, उसके अपने दिमाग पर और उसकी काबलियत पर है कि वह उस रेस में पाँव से पाँव मिला कर चल सकता है या नहीं। We will have to provide them the level-playing field that is the necessity of today. उसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्री ने जब वे बजट पर बोल रहे थे उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा कि–

"Now, I come to what has become the most important part of this Budget namely; the loan waiver. Loan wavier is debt forgiveness."

Debt forgiveness is not unknown in the History, He said—

"As early as 1938 under the Government of India Act and now this item No. 30 of the List-II, money lending and money-lenders and relief of agriculture indebtedness is a State subject and it is a subject of today. The answer to many questions about what you are going to do about money-lenders, is it is matter of slowly falling within the jurisdiction of the State Government. We can only help the State Government. Parliament of the Central Government has no executive or legislative power in respect of money lending and money lenders. But that is be it as it may be a very wise man like C. Rajagopalachari fondly called Rajaji passed the Madras Agriculture Debt Relief 1938 that what I mentioned. The same Act, the same legislation passed in the Punjab Legislative Assembly before partition."

I want the Hon'ble Members to please go to the library and look at this Act. It is far-reaching Act which said very simple the particular operative section. Speaker Sir, this has to be noted.

"If a borrower has paid twice the amount that he has borrowed, either the principal or interest or the both, the debt is completely wiped out."

This is the need of the hour. जिसने 100 रुपये ले लिया और 200 रुपये दे दिये तो उसकी तरफ चाहे 500 रुपये बकाया हों वे उसके माफ समझे जायें। इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी 2-3 बार सदन में और सदन से बाहर भी अपना ध्यान दिया है। मैं स्पष्टतया यह कहना चाहता हूं कि जब तक इसको रैगुलेट नहीं किया जाएगा तब तक आढ़ती भी सशोपंज में रहेंगे और जो देनदार है वे भी सशोपंज में रहेंगे। हमारी सरकार इस पर पूरी गम्भीरता से विचार कर रही है और भविष्य में इस समस्या का समाधान करके हम सदन के सामने आएंगे मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं। **(इस समय मेजें थपथपाई गई)**

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हम कोई ऐसा मैक्निजम तलाश कर रहे हैं जिससे किसान को भी लाभ हो और आढ़ती को भी नुकसान न हो।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इसके साथ ही साथ मैं जो एग्रीकल्चर डिवैल्पमैंट की बात है उसके बारे में एक-दो बातें और कहूंगा कि हमने काफी प्रावधान किये हैं लेकिन सच्चाई हमें माननी पड़ेगी और हमने मशीनी तरक्की की है। इस दुनियां में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आमदनी मल्टीप्लाई नहीं होती गुणा नहीं होती। किसानी ही एक ऐसा काम है जिससे आमदनी गुणा नहीं होती मल्टीप्लाई नहीं होती बल्कि यह शनैःशनैः बढ़ती है। इस साल अगर 105 है तो अगले साल 120 हो जाएगी, यह हो सकता है उससे अगले साल 135 हो सकती है लेकिन बाकी सारे धन्धे ईवन डैमोक्रेटिक सैटपअ भी मल्टीप्लाई हो जाता है और नेता लोग भी रातों-रात अमीर हो जाते हैं उनकी कोठियां बन जाती है, कारखाने लग जाते हैं और जो नेता जमीन पर नहीं चलना चाहते वे अपने जहाज खरीद लेते हैं। स्पीकर सर, हमारे यहां इस किस्म की व्यवस्था हर धन्धे में है लेकिन किसान के पास ही ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था को किसान के लिए लाभकारी बनाने के लिए आमूल-चूल परिवर्तन करने की बात है। स्पीकर सर, अगर मैं वित्त मंत्री नहीं होता तो मेरा अपना जो थीसिस है वह मैं समझा देता लेकिन it may be anti-thesis to the economists of the country. मैं तो यह भी कहता हूं कि अमरीका का एक रुपया आपको 40 रुपये में खरीदना पड़ता है। अगर किसान की अलग से कोई करन्सी हो और उसका एक रुपया हमारे तीन रुपये में चले, अगर ऐसा सिस्टम हो सकता है तो किसान को कोई सबसिडी की जरूरत नहीं है उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। स्पीकर सर, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। इस बात की जरूरत है कि बायोटैक्नोलोजी के माध्यम से उसकी हालत को सुधारा जाए। स्पीकर सर, हमारे यहां हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आपने डॉक्ट्रेट भी वहीं से की है। आप मुझे मुआफ करेंगे मैं आपके कुलीग के बारे में कह रहा हूं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बने हुए पूरे 12 साल हो गये हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ही नहीं, I blame all the Agriculture Universities of this country. They have not come out with a new variety of seeds. किसान को एक क्वांटम जम्प मिल सके आज इस बात की जरूरत है और हमने इसका प्रावधान किया है। हमने महकमें को लिखा है। आर०एल०डी० के लिए कोई यूनिवर्सिटी हो और चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे एग्रीकल्चरल डिपार्टमैंट हो अगर हमारे से पैसा मांगे तो फाईनैंस डिपार्टमैंट उसके पीछे नहीं हटेगा हम उनको पूरा पैसा देंगे। स्पीकर सर, आज इस बात की जरूरत है कि उसकी उपज बढ़े। आज उसका गेहूं 18 क्विंटल से 20 क्विंटल हो सकता है, 22 से 25 क्विंटल भी हो सकता है लेकिन उसकी जरूरत है आज एक एकड़ में 70 क्विंटल

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

पैदा करे और वह तभी सम्भव हो सकता है जब हम नये बीजों को ईजाद करें, उन पर शोध करें, उन पर विचार करें कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें हम बायोटैक्नोलाजी का इस्तेमाल करें। किसान को उसकी फसल का मूल्य दिलवाने के फील्ड में हमने काम किया है। हमारी सरकार गेहूं और चावल को छोड़ कर जो दूसरी फसलें हैं उनको खरीदने के लिए मार्कीट में आई है। तीन साल पहले हम सरसों खरीदने के लिए मार्कीट में आए उस समय एक लाख क्विंटल से ज्यादा सरसों नहीं बिकती थी लेकिन उसी साल छः लाख क्विंटल सरसों की खरीद हुई। हरियाणा सरकार जब से इस मैदान में आई है तो किसान को यह अहसास हुआ है कि हमें हमारे अनाज का पूरा भाव मिलेगा। तो इस किस्म की मार्कीट फोर्सिस को किसान के हक की बात करने के लिए स्टेट गवर्नमैंट को एक्टिविली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जिस तरह की एक्टिविटी महाराष्ट्र स्टेट करती है उसी तरह दूसरी कुछ ऐसी स्टेटस हैं जहां ऐसी पद्धति का इस्तेमाल होता है। इस किस्म की पद्धति के लिए भी हम विचार कर रहे हैं। स्पीकर सर, आखिर में मैं एग्रीकल्चर का जो महत्व है उस विषय में भी बताना चाहता हूं जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पर आधारित है– In the 21st century agriculture continues to be a fundamental instrument for sustainable development and poverty reduction using agriculture as the basis for economic growth in the agricultural-based countries required the productivity revolution and small holder farming agriculture contributes to development in many ways. Agriculture contributes to development as an economic activity as a livelihood and as a provider of environmental services making the sector a unique instrument for development. This is how they have treated agriculture as the most important. स्पीकर सर, अब मैं उन्हीं बातों पर आता हूं जिन पर हमारे साथियों ने कुछ हद तक चर्चा करने की कोशिश की है और बजट के ऊपर उनके सुझाव आए हैं। इससे पहले कि मैं इन सुझावों पर जवाब दूं मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे उस बात का जवाब देना पड़ रहा है जिसे चौधरी सम्पत सिंह जी ने बाहर बोला था, मुझे जवाब देना पड़ रहा है पंजाब के माननीय वित्त मंत्री के उस ब्यान का जो उन्होंने बाहर बोला था और यहां से जो कोई ठोस सुझाव हमारे कुछ मैम्बर साहेबान ने आज दिये। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे ठोस सुझाव हमे मिलने चाहिए जिससे कि हमें कुछ अहसास हो लेकिन अगर कोई सुझाव हमें न दें या हमें कोई बात समझाए नहीं तो उसका हम क्या जवाब दे सकते हैं। स्पीकर सर, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हमें ठोस सुझाव मिलें। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, on a point of order. मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर यह है कि अभी चौधरी बिरेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि किसानों की ऐसी कोई करन्सी हो जिसके तीन गुणा दाम हो। मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर यह है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने लोगों का धन लूट कर लाखों एकड़ धरती बना रखी है क्या यह भी उसकी कैटेगरी के अन्दर हैं या नहीं?(विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह किस तरह की बात कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, वे प्वायंट ऑफ आर्डर लेकर बोले हैं। आपको अगर कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप बोल सकते हैं।(विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के लोगों को आप बोलने के लिए कैसे अलाउ कर देते हैं, क्या इस तरह से कोई प्वांयट ऑफ आर्डर होता है?

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। कोई भी ऑनरेबल मैम्बर प्वायंट ऑफ आर्डर लेकर कोई बात क्लीयर कर सकता है या कुछ पूछ सकता है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, आप अपनी बात कान्टीन्यू करें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, हमारे बजट में जो मेन दो-तीन कमियां निकालने का प्रयास किया हैं मैं उन पर अपनी बात रखना चाहूंगा। पंजाब के माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि गुड़गांव को अगर निकाल दिया जाए तो हरियाणा में बिहार की स्थिति है। सर, यह बात बिल्कुल आधारहीन बात है। मैं आंकड़े दे कर यह बताना चाहता हूं कि यह ठीक कि Gurgaon is the part and parcel of the Haryana State. (Interruption) स्पीकर सर, हमारे रोहतक की कभी इतनी हैसियत होती थी। हमारे एक बहुत ही माननीय और रिस्पैक्टिड एम०एल०ए० थे डा० मंगल सैन वे वोट मांगते हुए कहते थे। उस समय पंजाब और हरियाणा इकट्ठे हुआ करते थे। वे यह कहा करते थे कि अब की बार मुझे वोट दो मैं रोहतक को लुधियाना बना दूंगा। स्पीकर सर, दूसरी बार जब वे वोट मांगने गए तो लोग उनको कहते थे आपने रोहतक को लुधियाना तो नहीं बनाया लेकिन गोहाना जरूर बना दिया है। (हंसी) स्पीकर सर, एक तो मैं यह बताना चाहता हूं कि जैसे मैं कह रहा था कि हमारे जो आंकड़े हैं उसमें अगर 70 हजार रुपये की पर कैपिटा इन्कम है अगर उन आंकड़ों को हम डिस्ट्रिक्टवाईज निकालें और 34600 रुपये उसके निकालें तो मेरा कहना यह है कि अगर उस पर भी हम स्टिक करें if we take out Gurgaon from the rest of the districts, still we are ahead of Punjab. Sir, that is one factor which is in our favour और गुड़गांव को हम ने कायम किया है, गुड़गांव में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाईड किया है। स्पीकर सर, अगर कोई आज रात को गुड़गांव में जाता है तो कहता कि मैनहटन के कहीं नजदीक घूम रहा हूं। स्पीकर सर, गुड़गांव हमारी देन है। स्पीकर सर, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तो यह बात कही गई थी कि हरियाणा के लोग तो उनके जो कर्मचारी है उनकी एक महीने की तनख्वाह भी नहीं दे सकते। आज वही लोग यह मानते हैं कि आज हम इस कैपेसिटी में हैं कि नये पे स्केल अपने कर्मचारियों को दे सकते हैं। तनख्वाह देने की बात पर हमने अपने घोषणा-पत्र में यह कहा और हम अपनी इस बात पर स्टिक करते हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में यह कहा कि we would ensure that the employees of Haryana should be the best paid in the country. सर, 6th Pay Commission कि रिपोर्ट अभी कल ही आई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है और मैं भी इस बात को यहां पर दोहरा देता हूं कि हम अपने कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखेंगे। फूल चन्द मुलाना जी ने कर्मचारियों के हाउस रैंट के बारे में बात कही चाहे उनके टी०ए०/डी०ए० की बात कही हो और चाहे दूसरी सुविधाओं की बात कही हो। स्पीकर सर, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको वे सारी सुविधाएं मिलें और देश के अन्य प्रान्तों से बेहतर सुविधाएं मिलें, इस बात के लिए हम वचनबद्ध हैं। **(इस समय मेजें थपथपाई गई)** स्पीकर सर, हमारे हरियाणा के बारे में भी इन्होंने एक ब्यान दिया कि जो सेलरी पैंशन रेशो है that is going up. एक तो मैं यह बता दूं कि जो एफ०बी०आर०एम० हैं जिसके हमने बेहतर नॉर्म्ज लेड डाउन किये थे अब दो साल पहले हमने पूरे कर लिये हैं और उसकी वजह से हमारा हर साल 180 करोड़ रुपये का यह जो लोन पर इन्ट्रस्ट में मुआफी आती है, यह कैश

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

मिलना है। पांच सालों में 1100 करोड़ रुपये के करीब हमें ऐसा पैसा मिलेगा क्योंकि हरियाणा ऐसा राज्य है जिसने 12th Finance Pay Commission की वह रिक्मैंडेशन है जो एक अच्छी ऐफिशियैंट फिस्कल मैनेजमैंट के लिए दी है। वह हमने वर्ष 2005-06, 2006-07 पूरा कर लिया है लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि इनकी सैलरी और पैंशन की रेशों में गैप बढ़ा है। स्पीकर सर, मैं आंकड़े दे कर यह बताना चाहूंगा कि यह जो वर्ष 2004-05 में इनैलो की सरकार थी 40.90% पैसा सैलरी और पैंशन में जाता था और वर्ष 2005-06 में वह 34.35% हुआ, वर्ष 2005-06 में 28.37% और वर्ष 2006-07 में यह 30.7% हुआ। सर, उसके बाद जो छठे पे कमीशन की रिक्मैंडेशन्ज़ आई हैं इनमें कैबिनेट सैक्रेटरी से लेकर नीचे क्लास-IV तक कर्मचारियों की तन्ख्वाहों में 25 से 40% की वृद्धि हुई है। We may be the first State. I was reading somewhere that only Tamil Nadu and Haryana they are the only two States those who have made provision for such unforeseen hike and we have made provision for 1550 crore for this thing only. If there is 6th Pay Commission report and we are to implement it then we would have to have 35 to 40% increases in our salary and all that. That is the only State except Tamil Nadu that we have made this provision. यह हमारी स्टेट की इक्नॉमिक बॉयेंसी को दर्शाता है। स्पीकर सर, अगर इसमें हम 1550 करोड़ रुपये का प्रोविजन नहीं करते तो दो हजार करोड़ रुपये के लगभग की सरप्लस स्टेट हरियाणा है। यही नहीं इसको प्रोवाईड करके भी हमने अगले साल 1470 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। जो हम उम्मीद करते हैं उसमें 1470 करोड़ रुपया सरप्लस किया। यह जो अगर आप 36 परसैंट को देखें और अगर कोई यह कहे कि हमारी पेंशन और सैलरी का बढ़ गया। हमने इनकी तरह से काम नहीं किया। इन्होंने चार साल तक कोई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की, प्रतिबंध था और आखिरी साल में ग्राम रक्षक लगा दिये कि शायद ये लोग वोट ही दे दें इन्होंने यह सोचा था। वोट देने का तो उन लोगों ने सोच लिया था कि किसको देने हैं? इनको थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ तो होनी चाहिए थी। जब पार्लियामैंट का इलैक्शन आया जिसमें इन्होंने अपने दोनों बेटों को मैदान में झोंक दिया और उनको लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो फिर 9 महीने बाद ऐसा क्या बदलाव आ गया था कि लोग इनके एम०एल०ए० जितवा देते। इन्होंने गल्ती की और फिर पुलिस फोर्स एच०एस०आई०एफ० के नाम से बना दी, साथ ही ग्राम रक्षक व वन रक्षक लगा दिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। अभी वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि इन्होंने इलैक्शन में अपने दोनों बेटों को झोंक दिया था। मैं बताना चाहता हूं कि ये तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। महम कांड में अपने बेटों को बचाने के लिए न जाने कितने बच्चों को इन्होंने मरवाया था। ये अपनी औलाद के लिए हरियाणा प्रदेश को भी कहीं पर भी दांव पर लगा सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है। वित्त मंत्री जी, आप बजट पर चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में कोई भी गैर जरूरी किस्म का आदमी ऐसे ही खड़ा हो जाए और सदन का बहुमूल्य समय नष्ट करे, क्या यह ठीक है?

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठीक बात कह रहे हैं। अपने बेटों को बचाने के लिए इन्होंने एक पुलिस कर्मचारी की ड्रैस बदलकर धक्का देकर उसको मरवा दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या आप चाहते हैं कि हम आपकी बात सुनें? आपकी इस बारे में मंशा क्या है? यह कोई तरीका थोड़ी है। यह कोई बात थोड़ी है। बीरेन्द्र सिंह जी, आप भी थोड़ी सी XX लगा देते हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी यह जो शब्द कह रहे हैं यह रिकार्ड न किया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : बीरेन्द्र सिंह जी, हम आपकी बजट स्पीच सुन रहे हैं। अगर आप कोई रिलीफ लोगों को दे रहे हैं तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। गैर जरूरी किस्म की बातें सदन में उठाने का यह कोई तरीका नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है। अभी चौटाला जी ने मेरे बारे में कहा कि गैर जरूरी किस्म के लोग। आप इनकी किस्म देखिये और मेरी किस्म देखिये। आप इनका हुलिया देखिये और मेरा हुलिया देखिये। ये मुझ गैर किस्म का कैसे कह सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी अच्छे आदमी हैं इसमें कोई दोराय नहीं है। शब्दों के जाल में ये अपनी बातों को अच्छे ढंग से पेश कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्योंकि ये जवाब भी दे रहे हैं और इसलिए क्लीयर भी करेंगे। कि वैट के बारे में आपने कहा कि वैट से 10 हजार करोड़ रुपये की आमदनी हुई है।

श्री अध्यक्ष : यह बात बजट पर चर्चा के दौरान डॉ० सीता राम ने भी और आपने भी कह दी थी। इस बारे में रिपीटीशन न करें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा बड़ा ही जरूरी पॉइंट है। जब 10 हजार करोड़ रुपये की आमदनी वैट से हो गई है तो ऐन्ट्री टैक्स लगाने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी? जब दूसरे टैक्सिज देश में यूनीफार्मली लागू हैं तो अलग से टैक्स लगाने की क्या आवश्यकता है? फर्टिलाइजर पर सबसिडी के मामले में आपके मन में झिझक है। कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में झिझक दिखाई है। मैं मानता हूं कि सर छोटू राम का खून आज भी आपकी रगों में दौड़ रहा है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वह उबाल भी मारता है लेकिन जिस पार्टी में आप हैं उसकी यह पॉलिसी कभी नहीं हो सकती। आप भी कोई नयी शुरुआत कीजिए जैसे हमने वैट प्रणाली की की थी।

श्री बीरेन्द्र सिंह : आपने वैट की शुरुआत कहां की थी?

डॉ० सुशील इन्दौरा : आप भी किसी नयी सबसिडी की शुरुआत कीजिए। आप किसान को डायरैक्ट सबसिडी देने की बात करिए। केन्द्र के फाइनैंस मिनिस्टर महंगाई की बात करते हैं लेकिन एम०एस०पी० की नहीं करते। विदेशों में 1500-1600 रुपये एम०एस०पी० में खरीदने की बात करते हैं और यहां किसान को आप एक हजार रुपये एम०एस०पी० दे रहे हैं अभी आपने पेंशन और शिक्षा के बारे में बात कही। हमने एक वाजिब चिन्ता जाहिर की है कि जिससे हम बढ़ती हुई पैंशन और सेलरी की जो रेशो थी उसको नीचे ला रहे थे। 40 से लेकर कुछ कम हुई। लेकिन आपकी वर्ष 2006-2007 में कम हुई लेकिन अब आप बढ़ाने लगे हुए हैं। हमें यह चिन्ता है। यह

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[डॉ० सुशील इन्दौरा]
अच्छे वित्त प्रबन्धन का परिणाम नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि यह बढ़कर वैसी ही हो जाए जैसे पंजाब कह रहा है।

Mr. Speaker : Hope sustains life.

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैं एक बात वैट के बारे में कहना चाहता हूं। जो ये विपक्ष के भाई वैट के बारे में डींग मारते हैं। देश में दूसरी जगह वैट लागू नहीं हुआ था और चौटाला साहब की सरकार ने हरियाणा में वैट सारे देश में दो साल पहले लागू कर दिया था। इसकी शुरूआत चौटाला साहब की सरकार ने की। यह हुकमरां और राजा की मानसिकता होती है कि उसका क्या ऐक्शन होगा। उन्होंने यह सोचकर वैट को हरियाणा में लागू किया था कि जो ट्रेडिंग कम्यूनिटी हैं उसको वे पसन्द नहीं करते थे क्योंकि चौटाला साहब का एक श्लोक भी है कि नींबू और बनियों को जितना निचोड़ोगे उतना ही ठीक रहता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हमारी सरकार द्वारा वैट को लागू करना सिर्फ स्टेट के रिसोर्सिज को बढ़ाना था। आप इस बात को मानते हैं। उन्हीं बढ़े हुए रिसोर्सिज की वजह से आज आपकी सरकार पैसे के मामले में पूरी तरह से निश्चिंत है लेकिन आपने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद वैट को समाप्त कर देंगे।

Shri Birender Singh : No, No.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपने तो पब्लिकली यह बात पार्लियामेंट के चुनाव के समय की थी। जब केन्द्र में आपकी पार्टी की सरकार बन गई और जब केन्द्र सरकार के फाइनैंस मिनिस्टर ने ऑन दि फलौर ऑफ दि हाउस पार्लियामेंट में इस बात को तसलीम किया और हरियाणा के फाईनैंस मिनिस्टर की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उसके बाद भी आपने विधान सभा में यह कहा कि हमारी सरकार सत्ता में आयेगी तो हम वैट को हटा देंगे। आज आप वैट के गुणगान गा रहे हो। ठीक है, हमने स्टेट के रिसोर्सिज बढ़ाने के लिए वैट लागू किया और यह भी हम मानकर चलते हैं कि इसकी वजह से हमें राजनीतिक नुकसान हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि आज हरियाणा स्टेट पूरे देश में नम्बर एक पर है और यह हमारी वजह से है।

श्री अध्यक्ष : यह तो बजट की बात आ गई, लेकिन जो नींबू वाली बात है वह क्या बात है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा में यह वैट लागू किया गया था उस समय आप भी सदन के सदस्य थे और मैं भी सदन का सदस्य था और हम विपक्ष में होते थे। उस समय हमने कभी वैट लागू करने के लिए सरकार का विरोध नहीं किया। हमने एक बात कही थी कि इस वैट को इन-आईसोलेशन लागू मत करो। जैसा कि वित्त मंत्री श्री बिरेन्द्र सिंह जी ने नींबू निचोड़ने वाली बात कही है। उस समय बनियों का भी नींबू निचोड़ा गया और किसानों का भी नींबू निचोड़ा गया। जो किसान धान पैदा करते थे उन किसानों का डेढ़ हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जितने शैलर वाले थे वे हरियाणा को छोड़कर पंजाब में चले गये। इस बात के लिए वे अब तक नुकसान भुगत रहे हैं। अगर चौटाला साहब वैट को इन-आईसोलेशन लागू नहीं करते तो यहां के किसान का, यहां के आढ़तियों का इतना नुकसान नहीं होता। मैं यही अनुरोध करना चाहता था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मुख्यमंत्री जी, आप फाईनैंस मिनिस्टर से इस बारे में पूछो, आपको ज्ञान नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आपको ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य सभ्य भाषा बोलें तो ठीक है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपको ज्ञान नहीं है यह सभ्य भाषा है। वैट लगने से इण्डस्ट्रिलिस्ट्स को लाभ मिला, कन्ज्यूमर्स को लाभ मिला लेकिन चोरी करने वालों को लाभ नहीं मिला, चोरी का माल खाने वाले लोगों को उस का जरूर नुकसान हुआ। शायद आप उस समय चोरों का समर्थन कर रहे थे कि हम वैट समाप्त कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, यह डिबेट नहीं हो रही है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जब मैं गर्वनर एड्रैस पर अपनी स्पीच दे रहा था उस समय चौटाला साहब सदन में मौजूद नहीं थे। इस बारे में मैंने एक ही बात कही थी कि-

मेरी जमीर बहुत है,
मेरी सदा के लिए,
तूं तो नसीहत न कर,
खुदा के लिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपने एक और बात कही थी। आपने यह भी कहा था कि मेरी चक्की आहिस्ता चलती है लेकिन बारीक पीसती है। यह भी आपने कहा था। आपकी चक्की का फैसला तो जनता करेगी।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 20 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है हाउस का समय 20 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : मैं आपकी तरह चक्की नहीं रखता हूं। मैंने कानून की चक्की कहा था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपने यह कहा था कि मेरी चक्की। यह हाउस की प्रोसीडिंग्ज में हैं। आपने यह कहा था कि मेरी चक्की आहिस्ता पीसती है और बड़ा बारीक पीसती है हम उसी को देखना चाहेंगे कि कैसे बारीक पीसती है?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने एक बात कही कि ओम प्रकाश चौटाला जी कहते थे कि नींबू और बानियों को जितना निचोड़ा जा सके उतना ठीक

[श्री मांगे राम गुप्ता]

है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने नींबू को तो निचोड़ दिया लेकिन बानियों ने इनको निचोड़ दिया और बानियों का इनका एक भी एम०एल०ए० चुनकर नहीं आया।

श्री के०एल०शर्मा० : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं ओम प्रकाश चौटाला जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 1.3.2004 में वैट लगाया था और इन्होंने वैट लगाते हुए कहा था कि इससे आमदनी बढ़ेगी। इन्होंने 2005 तक सारा साल वैट लगा कर रखा और फिर जब बजट पेश किया तो बजट 2000 करोड़ रुपये का पेश किया तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि वह आमदनी कहां गई? वैट से जो सारी आमदनी आने वाली थी वह आमदनी कहां गई। (शोर एवं व्यवधान) आप सुनने की हिम्मत करें। मैं इन दो सालों की बात कर रहा हूं। अगर अब आमदनी बढ़ी है तो वह एफ०आर०बी०एम० की वजह से बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, इनको पूरी बात समझ नहीं आती और ये पढ़कर नहीं आते।

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, आपने इस हाउस की रैनोवेशन की, बहुत अच्छी बात है। इस रैनोवेशन में साढ़े 6 करोड़ रुपया लगाया गया है लेकिन एक थोड़ी सी कमी छोड़ दी गई है और वह यह है कि इन सीटों का मैगनैट सिस्टम करना चाहिए था और उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए था क्योंकि एक आदमी बोलता है और सारे आदमी खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कितने वजन का मैगनैट लगाएं क्योंकि ये तो मैगनैट तक पाड़ कर ले जाएंगे।

वित्त मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रश्न उठाया कि हमारा जो प्लान एक्सपैंडीचर है उसके मुकाबले में नॉन प्लान एक्सपैंडीचर ज्यादा हो रहा है जो कि अच्छे बजट की निशानी नहीं है, मैं आंकड़ों पर आधारित यह बात कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई थी तो नॉन प्लान एक्सपैंडीचर के जो कम्पोनैंट थे वर्ष 2004-05 में 78.38 प्रतिशत थे और प्लान एक्सपैंडीचर 21.62 प्रतिशत था। 2005-06 में हमने अपने प्लान एक्सपैंडीचर को 25.69 परसैंट किया है और नॉन प्लान एक्सपैंडीचर जो 78.38 प्रतिशत था उसको 74.31 प्रतिशत किया है। अब वर्ष 2007-08 में 31 मार्च तक हमारा अनुमान है कि जो प्लान एक्सपैंडीचर 21.62 प्रतिशत था उसको हमने 30.53 यानि 10 परसैंट जो पैसा है वह प्लान में ज्यादा गया है। जो नॉन प्लान में 78 परसैंट खर्चा होता था वह 10 परसैंट घटकर 69.47 प्रतिशत पर आया है। इसी तरीके से कैपीटल एक्सपैंडीचर का है जैसे ज्यूडिशियल कॉम्प्लैक्सिज और दूसरी इमारतें हैं उसके लिए 2004-05 में 1692 करोड़ रुपये का प्रावधान था। वर्ष 2007-08 में इसको हमने बढ़ाकर 3386 करोड़ कर दिया है जोकि 29.63 परसैंट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके जो आंकड़े थे वह आधारहीन बात थी। जहां हमने प्लान साइज बढ़ाया है वहीं नॉन प्लान एक्सपैंडीचर हमारा 10 परसैंट कम आया है। 10 परसैंट प्लान साइज हमारा बढ़ा है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि हमारा कौलेक्शन कम हुआ है अध्यक्ष महोदय, LADT की वजह से हमें पिछले साल तक 350 करोड़ रुपये मिलता था। कुछ लोग हाई कोर्ट में फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला कर दिया। LADT अब की बार 350 करोड़ रुपये की बजाय सिर्फ 38 करोड़ रुपये मिला है। इसी प्रकार से सी०एस०टी० जो चार प्रतिशत से 3 प्रतिशत हुआ

उससे हमारे को 500 करोड़ रुपये एक दम घाटा हुआ है और 300 करोड़ रुपये के करीब का घाटा एल०ए०डी०टी० में हो गया। इसके अलावा पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में इम्पॉवर्ड कमेटी ने हमें बार-बार कहा कि हम डीजल पर 12 प्रतिशत की बजाय 20 प्रतिशत वैट लागू करें क्योंकि डीजल पर हमारा वैट 20 प्रतिशत फिक्स हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वे हमारे सी०एस०टी० का जो लौस है या दूसरे लोस हैं उनकी भरपाई नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम डीजल को किसान के लिए रा मैटीरियल मानते हैं। डीजल चाहे किसान के खेत में यूज़ हो या उसके ट्रैक्टर में यूज़ हो। हमने इम्पावर्ड कमेटी को साफ इनकार कर दिया कि हम डीजल पर 12 प्रतिशत से 20 प्रतिशत वैट नहीं करेंगे। जिससे 700 करोड़ रुपये का ऐडीशनल लोस हुआ है। पंजाब सरकार ने भी इसमें हमारा साथ दिया है। अध्यक्ष महोदय, फिर भी सी०एस०टी० और यह मिलकर हमारी रैवेन्यू रिसीट्स में 20 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है और इसको हमने तीन साल से मेनटेन करके रखा है। यह हमारी ऐफिसीयंसी है जिसको हम हमारे महकमें के अधिकारियों और कर्मचारियों के अच्छे परिणाम की वजह से मेनटेन कर पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, नवल बजट और फाईव ईयर प्लान की बात नहीं है मैं यह कहता हूं कि सारी पार्टियां बैठकर तय कर लें कि अगले 10-15 साल का हरियाणा का क्या रोड मैप होना चाहिए। हरियाणा में कौन-कौन सी चीजें हैं जो यहां के लोगों को गरीब बनाने के लिए मजबूर कर रही हैं और उनका कैसे समाधान किया जा सकता है। किस प्रकार से हरियाणा दस साल बाद ऐसी स्टेट बने जो दुनियां में किसी भी देश और स्टेट के मुकाबले में सर्वोत्तम हो। यह तभी हो सकता है जब हम दलगत और वोट की राजनीति से ऊपर उठकर बात करें। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार सदन में यह बात कही है कि हमारी कांग्रेस पार्टी की हुकुमत बनी है हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे, अपने लिए काम नहीं करेंगे। जो लोग यह लक्ष्य लेकर राजनीति करते हैं कि हमारा परिवार बड़ा बने, हमारा ऐम्पायर बड़ा बने और हमारी दौलत बढ़े इस तरह के लोग जनता का क्या भला कर सकते हैं? आज जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी यदि वे मुख्यमंत्री बन जाते तो ठीक था लेकिन नहीं बने तो नई पार्टी बना ली। आज वे कहते हैं कि वोट हमारी वजह से मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि जिनको यह गलतफहमी है कि वोट किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण मिलते हैं यह उनकी गलत सोच है, मैं इस बात को नहीं मानता। वोट मिलते हैं पार्टी को, पार्टी की नीतियों और मैनीफस्टों को, वोट मिलते हैं पार्टी के नेता के नाम से और आज तक हमारी पार्टी में एक ही नेता रहा है कोई बीस नेता नहीं हैं। आज के दिन हमारी पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी हैं और पहले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी थे। जिन लोगों को यह गलतफहमी है कि उनकी वजह से वोट मिले उन्हें यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। जनता तो नेताओं के लिए मिरर होती है जो जैसा काम करते हैं जनता उन्हें दिखा देती है कि आपने ऐसा किया है। मैं तो यह बात इसलिए कहता हूं कि आज हम मिलकर हरियाणा के नव निर्माण की बात सोचें और हरियाणा को एक ऐसा वायब्रैंट बजट दस साल के लिए दें जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो सके तथा हरियाणा एक नये युग में प्रवेश कर सके। अध्यक्ष महोदय, एक बात और कही गई कि पावर सैक्टर के अंदर हमने बजट एलोकेशन में रिडक्शन की है यह बिलकुल निराधार बात है। मैं पावर सैक्टर के बारे में बताना चाहूंगा कि वर्ष 2007-08 के दौरान 838 करोड़ रुपये का प्रावधान पावर सैक्टर के लिए किया गया था लेकिन बाद में इसको 933 करोड़ रुपये करना पड़ा क्योंकि कुछ इक्विटी वगैरह का पैसा देना था जो उसी साल देना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, अगर टोटल प्लान की बात करें तो इस साल हमारी प्लान एलोकेशन 3671 करोड़ रुपये प्लान और नोन प्लान की है। स्पीकर सर,

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

अगर टोटल प्लॉन की बात करें तो इस साल हमारा जो प्लॉन एलोकेशन है वह 3671 करोड़ रुपये है जो नॉन प्लॉन और प्लॉन दोनों की है। इस प्रकार से इसमें 142 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसे हमारे इनेलो के साथी आंकड़ों के माध्यम से देख सकते हैं। इनका कहना था कि एक-एक रुपया किस-किस चीज में और कितना-कितना खर्च हुआ? इसमें ऐसा होता है कि अगर हम किसी एक सैक्टर में ज्यादा राशि देते हैं तो दूसरे में तो कम होगा ही। हमारी जो प्लॉन एलोकेशन है मान लीजिए कि पावर सैक्टर में अगर वह पिछले साल 13 पैसे थी और अब वह 12 पैसे हो गई है या 11.50 पैसे हो गई है तो इसमें एक बात वॉल्यूम की भी देखी जाती है कि हमारा वॉल्यूम बढ़ा है या नहीं बढ़ा है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, प्रायरटी के बारे में ये पहले साल से कहते रहे हैं कि हम तीन साल में बिजली देंगे। इस प्रकार से अगर प्रॉयरटी रहते हुए भी उसी सैक्टर में आपकी परसैंटेज़ ऑफ मनी घटती है तो उसमें आप कामयाब कैसे होंगे? यह हमारा सवाल है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, इसमें दूसरी बात यह है कि पहली बार एक कांसरटिड तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से हमने हरियाणा में पावर जैनरेट करने का प्रयास किया है और उसमें 600 मेगावाट का पावर प्लांट यमुनानगर में लगेगा, 1500 मेगावाट का पावर प्लांट झाड़ली, जिला झज्जर में लगेगा जिसमें से हमको 750 मेगावाट बिजली मिलेगी और इसी प्रकार से 1300 मेगावाट का पावर प्लांट खेदड़, जिला हिसार में लगेगा और स्पीकर सर, इसके अलावा 1320 मेगावाट प्रक्योरमैंट बेसिज़ पर बीडिंग के लिए हमने बिजली का प्रावधन किया। इस प्रकार से हम तीन साल में 5 हजार मेगावाट और बिजली पैदा करने की स्थिति में हो जायेंगे। इनमें से 2 प्रोजैक्ट्स तो हमारे शुरू हैं। तीसरे पर भी काम शुरू हो गया है और ये प्रोजैक्ट्स अगले 2 से ढ़ाई साल तक पूरे हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा इनमें तीन साल लग सकते हैं जब ये पूरे हो जायेंगे तो उसके बाद हरियाणा की जो आज पावर की अवेलेबिलटी है जो कि पांच हजार मेगावाट से कम है वह डबल हो जायेगी और यह प्रयास पीछे किसी भी सरकार ने कभी भी करने का काम नहीं किया। इसलिए हम तो यह भी कह रहे हैं। हमने इस बार 24 हजार करोड़ रुपये के लगभग पावर सैक्टर के लिए बजट में रखे हैं और उसमें से हमने वर्ल्ड बैंक से, दूसरे बैंकों से और तीसरे बैंको से भी ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और पावर जैनरेशन के लिए इतनी बड़ी रकम ली है। इतनी बड़ी रकम आज तक कभी भी नहीं ली गई और न ही हरियाणा में इससे पहले इस तरह का कोई प्रावधान हुआ। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं अपने इनेलो के साथियों को एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि पावर सैक्टर पहले भी हमारी प्राथमिकताओं में था और आज भी हमारी प्राथमिकताओं में है। लेकिन हम यह नहीं कहते कि प्रदेश में बिजली की कमी नहीं है। हम यह मानते हैं कि जो लोगों को बिजली की कमी महसूस हो रही है उसके कई कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कभी भी पिछले 40 सालों के दौरान इस प्रकार से पावर सैक्टर में योजनाबद्ध तरीके से और बड़े स्तर पर काम नहीं हुआ और यही कारण है कि आज आधी बिजली की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। स्पीकर सर, इसमें एक बात यह भी है कि इन्होंने कहा है कि हमने गैस बैस्ड पावर प्लांट्स को कोल बैस्ड में क्यों ट्रांसफर कर दिया? Sir, this is a world phenomena कि गैस की अवेलेबिलटी नहीं थी और हम इंतजार नहीं कर सकते थे और इसलिए इस बारे में भारत सरकार की पॉलिसी में भी तबदीली आने के कारण हमने भी जो गैस बैस्ड पॉवर

प्लांट्स थे उनको कोल बैस्ड करने का निर्णय लिया। स्पीकर सर, इसके अलावा इन्होंने इरीगेशन के बारे में भी कहा कि रिडक्शन हुआ है। स्पीकर सर, इसमें रिडक्शन नहीं हुआ है जैसे मैंने बताया कि 2007-08 में हमने इरीगेशन के लिए 1314 करोड़ रुपये प्रोवाईड किये थे और फिर उसको रिवाईज़ करके 1518 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया यानि कि एक साल के अन्दर अगर रिवीज़न होता है तो मैं विपक्ष के साथियों से कहूंगा कि आप इस बात का समझने की कोशिश कीजिए कि प्लॉन का मतबल यह नहीं होता कि हम उस प्लॉन साईज़ में ही बंधकर रह जायें। If they are in a position to implement or to complete a project withing one year then why spread it over two or three years. We made a point wherever the additional funds were requred, we gave them the funds. स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त इन्होंने पब्लिक हैल्थ, वाटर सप्लाई एण्ड सैनीटेशन के बारे में भी यही बात कही कि 1126 करोड़ रुपये हमने प्रोवाईड किये थे और जब रिवाईज़ किए तो 1211 करोड़ हो गये। इस मद में वर्ष 2008-09 के एस्टीमेट्स में 1237 करोड़ रुपये हैं जो कि पिछले साल से लगभग 100 करोड़ रुपये ज्यादा हैं। जब इनकी सरकार थी तब तक इसमें सिर्फ 567 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो कि अब हमने डबल कर दिया है। सीधे तौर पर 100 प्रतिशत से भी ज्यादा की वृद्धि इसमें हुई है। स्पीकर सर, इसके साथ-साथ मैं एक बात और भी कहूंगा कि बहुत से साथियों ने इसमें अपने सुझाव दिए है। जिन साथियों ने बहस में हिस्सा लिया, उन्होंने नम्बर ऑफ डिमांड्स रखी हैं। उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम महकमों को भी लिख देंगे और कल जब डिमांड्स पर बहस होगी तो डिफरैन्ट मिनिस्टर्स उन डिमांड्स के बारे में अपने जवाब दे देंगे और जो नई बात आप एड करेंगे उनके बारे में भी जवाब दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ सबसिडी की बात कही गई थी कि सबसिडी कम हुई है। सर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि 2006-07 में टोटल सबसिडी का अमाऊंट 3858 करोड़ रुपये था और उसके 2007-08 में 2715 करोड़ रुपये रिड्यूस हो गये। अब 2008-09 में 2838 करोड़ रुपये की सबसिडी का प्रावधान किया गया है। उसका कारण यह था कि जब हमने 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किये थे उसके लिए हमें 160 करोड़ रुपये हर साल देने पड़ते थे। आज हमें इस बात की खुशी है कि वह लायबिलिटी अब सबसिडी के तौर पर नहीं रही। वह एक सफल स्कीम थी, उस पर जो मैक्सीमम इम्पलीमैंटेशन होनी थी वह हुई है। जो थोड़ा बहुत पैसा देना भी पड़ेगा तो उसका हम प्रावधान कर सकते हैं। इसी प्रकार से इलैक्ट्रिफिकेशन के नाम पर ट्यूबवैल वगैरह के लिए रूरल सबसिडी दी जाती थी। हमने 2006-07 में 2222 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और 2003-04 में जब हमारी सरकार नहीं थी आप लोगों की सरकार थी उस वक्त के 2 हजार करोड़ की एक बुक एडजैस्टमैंट हमें करनी पड़ी और उसके कारण हमारी सबसिडी 2 हजार करोड़ से एकदम 3800 करोड़ पर पहुंच गई। इस साल उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए उतनी ही सबसिडी कम हो गई है। इसके अलावा एक हमारे साथी हैं जो राजनीति में बहुत उतवाले हैं The man in haste श्री कुलदीप बिश्नोई। वे कहते हैं कि कांग्रेस की तो झूठ बोलने और झूठा बजट पेश करने की आदत है। यह बात हमारे ऊपर तो लागू होती नहीं और न ही चौटाला जी, आप पर लागू होती है। इसलिए यह तो उसी पर लागू होती है जो इस तरह की बात कहता है। यह उसका तकियाकलाम है कि भई झूठ तो मैं बोलता नहीं। इसके अलावा मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, मैं एक लेटर का हवाला देना चाहता हूं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज हरियाणा की पहचान लोगों की नजरों में, भारत सरकार की नजरों में या प्लानिंग कमीशन की नजरों में, आज हम प्रथम श्रेणी के राज्यों में हैं

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

जिसके लिए हमें इस बात का गर्व है। अभी कुछ दिन पहले हम दिल्ली में मीटिंग अटैंड करके आये हैं। उसमें मुख्य मंत्री जी प्रैस के सामने मोनटेक सिंह जी को ले गये और उन्होंने कहा कि हरियाणा जिस कदर तरक्की पर है, हरियाणा की इकोनॉमी ग्रोथ की जो कहानी है, This is a role model for all the States to follow. उन्होंने प्रैस के सामने यह बात कही और इससे बड़ा कम्पलीमैंट हमारे को नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पंजाब के वित्त मंत्री हरियाणा पर टिप्पणी करने से पहले खुद सोचें कि वे आज कहाँ पर खड़े हैं? आज पंजाब की ऐसी हालत क्यों है? मैंने पिछले साल भी कहा था कि उस हालत का जिम्मेदार हमारी और उनकी ब्यूरोक्रेसी में फर्क है। एक या दो आदमियों से न तो ब्यूरोक्रेसी अच्छी बनती है और न ही खराब होती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी रिस्पाँसिबल है और आज तक अच्छे परिणाम दिए हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, बंसी लाल जी के टाईम में भी बंसी लाल जी की दूरदर्शिता की बात करते थे तो उनके साथ मिश्रा जी का नाम जुड़ता था। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के खजाने भरने में ब्योरोक्रेसी का कंट्रीब्यूशन हम आज भी मानते हैं। इन आफिसर्ज ने मेहनत की है जिसकी वजह से हरियाणा के खजाने ने स्ट्रांग पोजीशन प्राप्त की है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब प्लानिंग कमिशन के एडवाईजर डाक्टर कोरियर हैं, वे लिखते हैं कि Punjab is a prosperous State with a highly monetized economy. Surprisingly, this is not reflected in the tax revenue of the State. The neighbouring State of Haryana with a much small economy as compared to Punjab collected this much of amount. These are the compliments and they are advising to learn it from Haryana. हरियाणा से सीख लो कि हरियाणा क्या कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये कुछ बातें हमने रखी हैं। शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने कुछ मुद्दे उठाए थे और उनके बारे में मैंने जवाब दे दिया है, मुलाना जी ने इम्पलाईज के बारे में कहा था, उसके बारे में भी मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने वाटर लैवल को रि-चार्ज करने के बारे में सदन में सुझाव दिया था। अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके के 150-200 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी बिलकुल ही खत्म हो गया है। क्या इसके लिए बजट में सरकार द्वारा कोई प्रावधान किया गया है। इस बारे में वित्तमंत्री जी बता दें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, नरेश यादव जी ने जो बात की है उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी प्रायरिटी है और हम समझते हैं कि दक्षिणी हरियाणा में हमें बहुत बड़ा सिस्टम

डवैल्प करना पड़ेगा, वहां पर जो रैजरवायर हैं, वाटर बाडिज़ हैं और जो पहले मौसमी नाले थे, अगर हम उनमे पानी छोड़ेंगे तो ही वहां का रि-चार्ज पूरा होगा। हमारे इन प्रयासों का सबसे बड़ा उदाहरण चौटाला नहर है। इसका जो पानी है, जब यह उन इलाकों में लगने लगेगा तो ज्यादा एरिया कमाण्ड में आएगा। अध्यक्ष महोदय, इस वजह से रि-चार्जिंग का एक नया अध्याय शुरू होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मंत्री जी ने भी कई प्रयास किए हैं, चाहे वे मसानी बैराज के हों, दोहान और कौशल्या नहर के हों या कृष्णा नहर के हों। (विघ्न)

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नहर जब बनेगी तब बनेगी। मैंने तो वाटर रि-चार्जिंग के बारे में पूछा है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हमने यमुना की कपैस्टी 20 हजार क्यूसिक की है ताकि बारिश के दिनों में रि-चार्जिंग का पानी दक्षिणी हरियाणा के काम आ सके।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर डॉक्टरों के बारे में जिक्र किया गया था, जिसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी। यह बात ठीक है कि जो हमारे डाक्टर्ज हैं उनकी तनख्वाह दूसरे राज्यों के मुकाबलें में बहुत कम है। इस बारे में बोलते हुए सदन में एक सदस्य ने कहा था कि हमारे डाक्टर्ज यहां से प्लायन कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए सदन को एश्योर करता हूं कि इस छठे पे-कमीशन की रिपोर्ट के बाद अपने डाक्टरों को अच्छी सैलरी देंगे ताकि वे हरियाणा की ओर आकृषित होकर यहां पर काम करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मै वित्तमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने बात कही है यह बहुत ही अच्छी बात कही है। कई दफा हमने सुनने में आया है और हमने भी इस बारे में देखा है कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हमारे डाक्टरों से ज्यादा तनख्वाह है। आज मैं सदन को एश्योर करता हूं कि हम हमारे डाक्टरों को पंजाब से कुछ न कुछ ज्यादा तनख्वाह देंगे। (इस समय मेजें थपथपाई गई)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात और सुरजेवाला जी ने कही थी कि बजट में हैल्थ के लिए सिर्फ 130 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं सुरजेवाला जी को बताना चाहूंगा कि यह 130 करोड़ रुपये नहीं है बल्कि बजट में हैल्थ के लिए 281 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, हैल्थ डिपार्टमैंट में बाहर से, भारत सरकार से बहुत पैसे आते हैं। इस बारे में सुरजेवाला जी आपने नहीं देखा होगा। इसके साथ ही कर्ण सिंह दलाल जी ने भी कई सुझाव दिए थे और मैंने उनके बारे में जवाब दे दिया है। उस समय भाई कर्ण सिंह दलाल जी सदन में नहीं थे।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्तमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि विधायकों के भत्ते वगैरह भी बढ़ाए जाएं। (विघ्न)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, नरेश यादव जी ने एक बात रखी है। विपक्ष के हमारे साथी और सत्ता पक्ष के हमारे साथी भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। हम अगले दो दिन में इस बारे में एक विधेयक लेकर आएंगे ताकि सदस्य जो आते हैं हाजिरी लगाते हैं एक बार बैठते हैं उसके बाद भाग जाते हैं जब कमेटी की मीटिंग होती है या कहीं और

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

से उनके सम्मन आते हैं तो वे यहीं पर रहें इसलिए इस तरह का भत्ता जरूर करेंगे ताकि वे यहां से भागे नहीं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : इंदौरा साहब, मंत्री जी ने बता दिया है कि इस बारे में एक विधेयक आ रहा है।

डॉ सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मेरा एक सुझाव है कि आज प्रदेश के हालत ऐसे हैं कि गरीब आदमी महंगाई की मार झेल रहा है इसलिए उनके बारे में भी सोचा जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सर, मेरा पवायंट ऑफ आर्डर यह है कि मैंने चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को एक सुझाव दिया था। मैं कमेटी की मीटिंग में था इसलिए मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने मेरे प्वायंटस नोट किये हैं इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सर, मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो सैल्फ ऐक्वायर्ड प्रोपर्टी है जिसको लोग अपने जीवनकाल में अपने हाथों से बनाते हैं और यदि उस जायदाद को वे अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो वह 15 रुपये के स्टैम्प पेपर पर रिलीज डीड में करने से गांवों में झगड़े खत्म होंगे। स्पीकर सर, इस बारे में भी मंत्री जी आश्वासन दें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : सर, नरेश यादव जी ने विधायकों को भी सुविधाएं देने की बात कही है। जो 6th पे कमीशन की रिपोर्ट है इसको इनके ऊपर भी लागू करेंगे ताकि इनको भी सुविधा मिले। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी ही इस बारे में हम एक विधेयक लेकर आएंगे। सर, किसी सदस्य ने स्पोर्ट्स के बारे में भी बात कही। मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2004-05 में प्लान और नोन प्लान को मिलाकर टोटल स्पोर्ट्स की ऐलोकेशन 27 करोड़ रुपये थी जबकि अब यह 57.99 करोड़ रुपये है हालांकि अब भी मैं इसको कम ही मानता हूं, मुख्यमंत्री जी भी कम मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि निकट भविष्य में हम स्पोर्ट्स को एक महत्वपूर्ण डिपार्टमैंट में कन्वर्ट करेंगे और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या पैसे की जरूरत होगी तो वह भी हम पूरी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रसन्नी देवी जी ने भी कहा कि जो गैर किसान हैं उनके कर्जों को माफ करने की तरफ भी सरकार ध्यान दें। सुरजेवाला जी ने भी तथा दूसरे अन्य सदस्यों ने भी यह बात कही है। अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारे सामने भी है इसके लिए भी हम भारत सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं इसमें कार्यवाही होने की उम्मीद है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, कोओपरेटिव बैंक्स के लिए जो स्कीम दी थी उससे एक लाख लोगों ने फायदा उठाया है। जो नोन ऐग्रीकल्चरिस्ट्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, शिल्पकार हैं उन जैसे एक लाख लोगों ने इस स्कीम का फायदा उठाया है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैंने हरियाणा में बी०पी०एल० का क्राईटेरिया बदलने के लिए भी बोला था कि क्या भारत सरकार को हरियाणा गवर्नमैंट लिखेगी?

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, इस तरह से तो सारे ही लोगों ने अपने सुझाव दिये थे। 36-37 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने अपने सुझाव दिए हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, हम आलरेडी इस बारे में लिख चुके हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने लम्बे समय तक जो बातें मैंने कहीं उनको बड़े धैर्य से सुना। स्पीकर साहब, यह जो बजट है यह हरियाणा के लोगों के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके रुपये पैसों की ताकत को बढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा लोगों को देने के लिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और दुनियां के जो भी निवेशक हैं उनको आकर्षित करने के लिए होगा। ये हमारी प्राथमिकताएं भी हैं। इन्हीं प्राथमिकताओं पर हम यह चाहते हैं कि इनको कंसौलिडेट करके हमारी जो स्पीड बनी है, जो हमने रफ्तार कायम की है उससे हम 20 परसैंट से ऊपर और 11 परसैंट इकोनोमिक ग्रोथ आज है अगर यह बनी रहेगी तो हरियाणा नये युग में प्रवेश करेगा। स्पीकर सर, हम इस डिटरमिनेशन के साथ आए हैं। एक शेर के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि –

चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिश से
अगर आसां जो जिन्दगी तो जीना दुश्वार हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, हम तो अच्छे बुरे सबको झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

एक शेर और अर्ज करना चाहता हूं कि

तू तो छलकी थी किसी कम्जर्फ के पैमाने से
मेरे पैमाने में तो मयखाने समा जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस बजट को सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं एक ही बात कह सकता हूं और जैसा कि वित्त मंत्री जी ने भी माना कि -

माना कि इस जमीं को गुलजार न कर सके लेकिन
कुछ कांटे तो कम किए हैं, जो इन्होंने बोये थे।

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 27th March, 2008.

*14.02 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 27th March, 2008.)

44398—H.V.S.—H.G.P., Chd.